केंद्रीय क्षेत्र योजना
Central Sector Scheme

सिल्क समग्र SILK SAMAGRA-2

मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा निर्देश
Standard Operating Procedure and Guidelines for Implementation

केंद्रीय रेशम बोर्ड
Central Silk Board
(वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार)
(Ministry of Textiles – Govt. of India)
बीटीएम लेआऊट, मडिवाला, बेंगलूरू - 560 068
BTM Layout, Madivala, Bengaluru - 560 068

अप्रैल 2022, 1000 प्रतियां

April 2022, 1000 Copies

द्वारा प्रकाशित

सदस्य सचिव
केंद्रीय रेशम बोर्ड
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)
कें रे बो काम्प्लेक्स, बीटीएम लेआऊट,
मडिवाला
बेंगलूरू - 560 068

Published by

Member Secretary
Central Silk Board
(Ministry of Textiles, Govt. of India)
CSB Complex, BTM Layout, Madivala
Bengaluru - 560 068

द्वारा मुद्रित

सर्वश्री वेंकटाद्री प्रिंटर्स
प्रिंटिंग साल्यूशन्स
सं 187, अक्कीपेट मेन रोड,
बेंगलूरू - 560 053
ई-मेल: murthy64@me.com
दूरभाष: 080-26704667

Printed at

M/s. Venkatadri Printers
Printing Solutions
No.187, Akkipet Main Road,
Bengaluru - 560 053
Email: murthy64@me.com
Phone: 080-26704667

विषय-सूची

#	विषय	पृष्ठ
I	**पृष्ठभूमि**	
i	केंद्रीय रेशम बोर्ड की मुख्य गतिविधियां - उप-घटक	1
ii	लाभार्थी-उन्मुख महत्वपूर्ण क्षेत्र स्तरीय मध्यस्थता - उप-घटक	1
II	**केन्द्रीय रेशम बोर्ड की प्रमुख गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश**	
क	**मूल गतिविधियां**	2
ख	**प्रमुख गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सामान्य दिशा-निर्देश - कार्यक्रम तैयार करना और मंजूरी**	
i	अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आई.टी. पहल	4
ii	बीज संगठन	5
iii	समन्वय और बाजार विकास	6
iv	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (क्यूसीएस)/निर्यात, ब्रांड प्रचार और प्रौद्योगिकी उन्नयन	6
ग	**मुख्य गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश**	7
घ	**निधि का विमोचन और उपयोग**	8
III	**लाभार्थी उन्मुख घटकों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश**	
क	**सहायता के लिए उपलब्ध घटक**	9
ख	**कार्यान्वयन अभिकरण**	10
ग	**निधि सहायता का दायरा और बजटीय आवंटन**	10
I	राज्यों के रेशम उत्पादन विभागों/समान विभागों को सहायता	10
ii	उत्तर पूर्वी राज्यों को परियोजना आधारित सहायता	11
iii	पूर्ववर्ती एनईआरटीपीएस के तहत चल रही रेशम उत्पादन परियोजना के लिए वित्त पोषण	12
iv	निधि का आवंटन	12
घ	**राज्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना**	12
ङ	**परियोजना मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए तंत्र**	16
च	**निधि का विमोचन**	16
छ	**उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना**	17
ज	**राज्य द्वारा लाभार्थी-उन्मुख महत्वपूर्ण मध्यस्थता के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश**	17
झ	**लाभार्थी-उन्मुख सिल्क समग्र-2 पैकेजों/घटकों के लिए निधिकरण पैटर्न**	18
ञ	**अनुश्रवण एवं मूल्यांकन**	**19**
ट	**सिल्क समग्र-2 हेल्पलाइन**	21

केंद्रीय क्षेत्र योजना "सिल्क समग्र-2" - 2021-22 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग चक्र) तक 5 वर्षों के दौरान रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना (आईएसडीएसआई) के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश

I. पृष्ठभूमि

केंद्रीय रेशम बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम (1948 के अधिनियम संख्या LXI) द्वारा की गई थी। केंद्रीय रेशम बोर्ड की मुख्य गतिविधियां हैं, अनुसंधान और विकास; चार स्तरीय रेशमकीट बीज उत्पादन नेटवर्क का रखरखाव; वाणिज्यिक रेशमकीट बीज उत्पादन में नेतृत्व की भूमिका; विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में गुणवत्ता मानकों को मानकीकृत और स्थापित करना और रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना। इन गतिविधियों को केंद्रीय क्षेत्र की योजना नामत: **"सिल्क समग्र -2"**, के माध्यम से देश भर में फैली इकाइयों के नेटवर्क द्वारा किया जाता है, जो रेशम उद्योग के विकास के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा दिनांक 19.01.2022 को अनुमोदित किया गया है। रेशम समग्र-2 योजना में शहतूत, वन्य और कोसोत्तर क्षेत्रों के अधीन विभिन्न घटक और उप-घटक शामिल हैं। यह कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा, कच्चे रेशम की गुणवत्ता, उत्पादकता और उत्पादन में सुधार के लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रयासों में तालमेल बैठाता है।

रेशम समग्र-2 योजना में दो प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं:

i) केंद्रीय रेशम बोर्ड की मुख्य गतिविधियां - उप-घटक

क. अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सूचना प्रौद्योगिकी पहल

ख. बीज संगठन

ग. समन्वय और बाजार विकास

घ. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली, निर्यात, ब्रांड प्रचार और प्रौद्योगिकी उन्नयन

ii) लाभार्थी-उन्मुख महत्वपूर्णक्षेत्र स्तरीय मध्यस्थता - उप-घटक

क. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अलावा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र स्तरीय मध्यस्थता

ख. पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशम उत्पादन परियोजनाओं का कार्यान्वयन

ग. एनईआरटीपीएस की चल रही रेशम उत्पादन परियोजनाओं के व्यय को पूरा करने के प्रावधान

जबकि चार उप-घटकों के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड की मुख्य गतिविधियों यथा, अनुसंधान एवं विकास, बीज उत्पादन, परियोजना कार्यान्वयन और अनुश्रवण और भारतीय और बाहरी बाजारों में रेशम के ब्रांड प्रचार को केन्द्रीय रेशम बोर्ड की इकाइयों के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, लाभार्थी-उन्मुख घटक रेशम समग्र-2 योजना के अधीन केंद्रीय रेशम बोर्ड से निधि सहायता के साथ राज्य रेशम उत्पादन विभागों/अन्य राज्य विभागों द्वारा कार्यान्वित किये जाएंगे।

II. केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्रमुख गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश

क. प्रमुख गतिविधियां

I. अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सूचना प्रौद्योगिकी पहल

अनुसंधान गतिविधियों एवं शहतूत रेशम उत्पादन के लिए तीन मुख्य अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (सीएसआरटीआई) मैसूर (कर्नाटक), बरहमपुर (पश्चिम बंगाल) और पंपोर (जम्मू-कश्मीर) में स्थापित किए गए हैं; रांची (झारखंड) में तसर के लिए एक संस्थान (सीटीआरटीआई), और मूगा एवं एरी के लिए लाहदोईगढ़ (असम) में सीएमईआरटीआई, और कोसोत्तर मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक विशेष प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान (सीएसटीआरआई) बेंगलूरु (कर्नाटक) में स्थापित किया गया है।

बीज, शहतूत एवं रेशमकीट आनुवंशिक सामग्री के संरक्षण/रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्रमशः बेंगलुरू में एक रेशमकीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एसएसटीएल) और होसूर (तमिलनाडु) में एक केंद्रीय रेशम उत्पादन जननद्रव्य संसाधन केंद्र (सीएसजीआरसी) स्थापित किया गया है। इसके अलावा, बेंगलूरू में एक रेशम जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (एसबीआरएल) काम कर रही है। क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र (आरएसआरएस) और अनुसंधान विस्तार केंद्र (आरईसी) कोसापूर्व और कोसोत्तर क्षेत्रों में उपरोक्त अनुसंधान संस्थानों से जुड़े हुए हैं।

अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा सिल्क समग्र-2 योजना के दौरान अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए शहतूत और वन्य रेशम क्षेत्रों में उच्च उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता और जैविक और अजैविक प्रतिबल के प्रति लचीलापन के लिए परपोषी पौधा और रेशमकीट नस्ल का सुधार शामिल हैं; नस्ल/संकर सुधार और रोग निदान के लिए आणविक उपकरणों को अपनाना; उन्नत बीज प्रौद्योगिकी और जननद्रव्य संरक्षण; कड़ी मेहनत में कमी और दक्षता में सुधार के लिए रेशम उत्पादन गतिविधियों का मशीनीकरण; कोसोत्तर क्षेत्र और बेहतर रेशम प्रसंस्करण मशीनरी/प्रौद्योगिकी के लिए मशीन निर्माण व्यवस्था की स्थापना; गैर-वस्त्र प्रयोजनों के लिए रेशम का वाणिज्यिक उपयोग; और रेशम जैव सामग्री अनुसंधान शामिल हैं।

अनुसंधान संस्थान, उद्योग के लिए आवश्यक कुशल जनशक्ति उत्पन्न करने के लिए रेशम उत्पादन के विभिन्न पहलुओं में विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। शहतूत और गैर-शहतूत रेशम उत्पादन में उन्नत प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण का मूल्यांकन और कार्यान्वयन रेशम विभागों के समन्वय से किया जाएगा।

आईटी सेवाओं का उपयोग सिल्क्स (सेरीकल्चर इंफॉर्मेशन लिंक्ड नॉलेज सिस्टम) पोर्टल्स के माध्यम से दैनिक आधार पर रेशम माल मूल्य संचार प्रणाली, नेटवर्किंग और ज्ञान प्रबंधन और डेटा वेयरहाउसिंग प्रसार के लिए किया जाता है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड की इकाइयों का कम्प्यूटरीकरण, सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग, केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली आदि भी आईटी एप्लिकेशन के उपयोग से किए जाते हैं।

ii. बीज संगठन

क. लक्षित रेशम उत्पादन को प्राप्त करने के लिए रेशम विभागों और निजी भागीदारों के समर्थन से पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले रेशमकीट बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उत्पादकता मानकों में सुधार के लिए कार्य करना।

ख. नाभिक और मूल रेशमकीट बीज के उत्पादन और आपूर्ति के लिए चार स्तरीय बीज प्रगुणन नेटवर्क बनाए रखना।

ग. द्विप्रज वाणिज्यिक बीज उत्पादन में नेतृत्व की भूमिका

घ. राज्य इकाइयों और निजी रेशमकीट बीज उत्पादकों को गुणवत्तापूर्ण रेशमकीट बीज उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए सुविधा प्रदान करना

ङ. रेशमकीट बीज अधिनियम को लागू करके अपनी इकाइयों के लिए गुणवत्ता प्रमाणन का संचालन और राज्य एवं निजी इकाइयों के लिए इसकी सुविधा प्रदान करना।

च. बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए अंगीकृत बीज पालकों (एएसआर) को सहायता।

छ. बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान, रोग नियंत्रण, शीत भंडारण प्रौद्योगिकी, बीज संरक्षण आदि।

iii. समन्वय और बाजार विकास

क. रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए राज्य विभागों के साथ संपर्क और समन्वय।

ख. रेशम उत्पादन के विकास के लिए प्रभावी तालमेल और संसाधनों का एकत्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं / घटकों से सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / लाइन विभाग के साथ समन्वय।

ग. फैब्रिक इंजीनियरिंग, सिल्क ब्लेंड्स, नए फैब्रिक स्ट्रक्चर को डिजाइन करने, सिल्क और सिल्क ब्लेंड्स में नए उत्पादों के डिजाइन और विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ उत्पाद डिजाइन, विकास और विविधीकरण (पी 3 डी)।

घ. देश में कोसे और कच्चे रेशम का निष्पक्ष और पारदर्शी विपणन प्रदान करने के लिए बाजार कड़ी/बाजार की अवसंरचना को मजबूत करने के लिए समर्थन।

ङ. जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा के लिए गैर-शहतूत कोसों के लिए मूल्य स्थिरीकरण समर्थन।

iv. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (क्यूसीएस), निर्यात, ब्रांड संवर्धन और प्रौद्योगिकी उन्नयन

क. गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता मूल्यांकन और गुणवत्ता प्रमाणन को सुदृढ़ करने की दिशा में उपाय।

ख. घरेलू बाजार में भारतीय रेशम का ब्रांड और जेनेरिक संवर्धन, निर्यात बाजार में ब्रांड भारतीय रेशम का संवर्धन।

ग. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेशम की गुणवत्ता, प्रसंस्करण और परिष्करण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन।

घ. रेशम की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कोसे और कच्चे रेशम का परीक्षण।

ङ. सिल्क मार्क ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (एसएमओआई) के माध्यम से रेशम उत्पादों की शुद्धता के लिए "सिल्क मार्क" को लोकप्रिय बनाकर शुद्ध रेशम उत्पादों को बढ़ावा देना।

ख. मुख्य गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सामान्य दिशा-निर्देश : कार्यक्रम तैयार करना और मंजूरी

(I) अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सूचना प्रौद्योगिकी पहल

1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास संस्थान शहतूत, एरी, मूगा और तसर रेशम उत्पादन में आवश्यकता आधारित अनुसंधान करेंगे और आयात स्थानापन्न अंतरराष्ट्रीय श्रेणी द्विप्रज रेशम के उत्पादन और स्वदेशी मशीन निर्माण आदि में आत्मनिर्भर बनने के लिए कोसापूर्व और कोसोत्तर दोनों क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों का विकास करेंगे।
2. केंद्रीय रेशम बोर्ड फैब्रिक इंजीनियरिंग, रेशम मिश्रणों आदि पर विशेष ध्यान देने के साथ उत्पाद डिजाइन, विकास और विविधीकरण (पी3डी) के लिए विभिन्न संस्थानों/अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ सहयोगात्मक परियोजनाएं शुरू करेगा। इसके लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाएगी।
3. अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने और ऐसी तकनीक को क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए समय सीमा होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
4. पाँच वर्ष की कार्य योजना केन्द्रीय रेशम बोर्ड को जमा करनी होगी और वार्षिक कार्य योजना के आधार पर बजट आबंटित किया जाएगा।
5. वर्षवार कार्य योजना में आईसीएआर के मौजूदा नेटवर्क, कृषि विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के अन्य अनुसंधान संगठनों के साथ अनुसंधान एवं विकास सहयोग शामिल होगा।
6. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की समीक्षा और अनुश्रवण के लिए प्रत्येक मुख्य अनुसंधान संस्थान की अपनी अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी)/अनुसंधान परिषद (आरसी) होगी।
7. राष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान समन्वयन समिति सिल्क समग्र-2 के परिणाम/परिणाम अनुश्रवण के लिए उद्देश्यों/तार्किक ढांचे के अनुरूप अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा, मूल्यांकन व अनुमोदन करेगी ।
8. सभी अनुसंधान परियोजनाओं/प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए एक अनुसंधान प्रबंधन और प्रौद्योगिकी प्रसार मैनुअल तैयार की जाएगी, जिसमें परियोजना की अवधारणा जांच व अनुश्रवण के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं उल्लिखित की जाएंगी।
9. संकर प्राधिकरण समिति और शहतूत प्राधिकरण समिति रेशम समग्र-2 के लक्ष्य के अनुसार नई शहतूत किस्मों और रेशमकीट नस्लों को व्यवहार में लाने की सिफारिश करेगी।
10. रेशम समग्र-2 के लिए ईएफसी प्रस्ताव पर विचार करते समय नीति आयोग द्वारा सुझाए गए तार्किक ढांचे के दस्तावेजों के संदर्भ में अनुसंधान परियोजनाओं के निष्पादन का तिमाही आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

11. आईसीएआर और सीएसआईआर संस्थानों की निष्पादन जांच प्रणाली को केन्द्रीय रेशम बोर्ड की अनुसंधान व विकास प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा।
12. किसानों के लिए रेशम उत्पादन सलाह सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप/पोर्टल, अनुसंधान एवं विकास, व आईटी पहल के एक भाग के रूप में किसानों और धागाकारों के लिए कोसा और रेशम दरों के लिए एसएमएस सेवा को विकसित किया जाएगा।
13. सिल्क्स पोर्टल के माध्यम से रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल के माध्यम से डेटा भंडारण और प्रसार, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के अनुप्रयोग के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड इकाइयों का डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण ।
14. विभिन्न परियोजनाओं के अधीन सृजित रेशम उत्पादन संपत्तियों की जियो टैगिंग जीपीएस आधारित मोबाइल एप 'सिल्क' का उपयोग करके सुनिश्चित की जाएगी।
15. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, राज्यों को सिल्क समग्र-2 के अनुसार वृक्षारोपण विकास, रेशमकीट बीज, कोसा व कच्चे रेशम का उत्पादन और अन्य मानकों के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार लक्ष्यों को संप्रेषित करेगा और उनकी सहमति लेगा।
16. एमआईएस को एक मंच के तहत एकीकृत किया जाएगा और योजना के लाभ/परिणाम के अनुश्रवण और इसके वितरण प्रणाली और किसानों और धागाकारों के डेटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए मजबूत प्रणाली विकसित की जाएगी।
17. सभी रेशम उत्पादन हितधारकों/रेशम उत्पादन पर राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल सेरी डाटा बेस बनाया जाएगा।
18. मंत्रालय और नीति आयोग सहित हर स्तर पर निगरानी की सुविधा के लिए सभी डेटा बेस और मानदंड सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाएंगे।
19. नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का कार्यान्वयन, सॉफ्टवेयर विकास (ई-ऑफिस, एचआरएमएस, ईआरपी और अन्य एमआईएस) और उनके रखरखाव, सॉफ्टवेयर की खरीद/उन्नयन आदि को सुनिश्चित किया जाएगा।
20. रेशम उत्पादन गतिविधियों और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

(ii) बीज संगठन

1. शहतूत, तसर, एरी और मूगा के बीज संगठनों के पास केन्द्रीय रेशम बोर्ड, राज्य और पंजीकृत बीज उत्पादकों (आरएसपी) इकाइयों के माध्यम से देश की संपूर्ण बीज आवश्यकताओं का आकलन, उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए अलग-अलग बीज कार्य योजना समितियां होंगी।
2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बीज संगठन उन्नत द्विप्रज नस्लों और वन्य रेशमकीट बीज के कुलीन और नाभिक बीज उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेंगे तथा चार स्तरीय रेशमकीट बीज उत्पादन नेटवर्क की देखरेख और रखरखाव सुनिश्चित करेंगे।

3. द्विप्रज शहतूत क्षेत्र के अधीन बीज उत्पादन के लिए उद्यमियों को बढ़ावा देना और व्यावसायिक उपयोग के लिए और शीत भंडारण इकाइयों की स्थापना ।
4. रेशमकीट बीज उत्पादकों और किसानों/रेशम विभागों को एक साझा मंच प्रदान करने के लिए रेशमकीट बीज की वास्तविक समय पर उपलब्धता, बीज की लागत और उत्पादकों के विवरण के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा।
5. बीज संगठन शहतूत और वन्य रेशम क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले द्विप्रज बुनियादी और वाणिज्यिक रेशमकीट बीज के उत्पादन के लिए राज्य सरकारों और आरएसपी का समर्थन करेंगे।
6. राज्य की वाणिज्यिक बीज आवश्यकता के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य निजी भागीदारों के सहयोग से द्विप्रज वाणिज्यिक रेशमकीट बीज उत्पादन गतिविधियों को प्राथमिकता देगा।
7. द्विप्रज और वन्य वाणिज्यिक रेशमकीट बीज उत्पादन को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने के लिए कार्य योजना तैयार कर कार्यान्वित की जाएगी।
8. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बीज संगठन अन्य रेशम उत्पादक देशों को रेशमकीट के बीज के निर्यात की संभावना का पता लगाएंगे और रेशमकीट बीज निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए कार्य योजना भी तैयार करेंगे।
9. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, राज्य और निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी।

(iii) समन्वय और बाजार विकास

1. केंद्रीय रेशम बोर्ड देश में कोसे और कच्चे रेशम के निष्पक्ष और पारदर्शी विपणन को बढ़ावा देने के लिए बाजार संपर्कों/बाजार अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करेगा।
2. रेशम उत्पादन के विकास के लिए प्रभावी तालमेल और संसाधनों के एकत्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं/घटकों से सहायता प्राप्त करने के लिए समान केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकार के समान विभाग के साथ अभिसरण के माध्यम से रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए समकक्ष वित्त पोषण का पता लगायेगा ।
3. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शुद्ध रेशम उत्पादों के सतत् विकास, लक्ष्य और आजीविका सृजन और ब्रांड संवर्धन के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों के साथ सहयोग का पता लगायेगा।
4. आदिवासी समुदायों के लाभ के लिए वन्य क्षेत्र में मूल्य स्थिरीकरण समर्थन सुनिश्चित करेगा। तसर, एरी और मूगा के लिए अलग से मूल्य निर्धारण समिति गठित की जाएगी।

(iv) गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (क्यूसीएस), निर्यात, ब्रांड संवर्धन और प्रौद्योगिकी उन्नयन

1. एसएमओआई की गतिविधियों की पूर्ण आउटसोर्सिंग मोबाइल ऐप का उपयोग करके और एसएमओआई गतिविधियों के ऑनलाइन/डिजिटलीकरण द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
2. क्यूसीएस के तहत गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के लिए, एसएमओआई द्वारा वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें वार्षिक कार्यनीति और मील के पत्थर हों।

3. सिल्क मार्क लेबल को बढ़ावा देने, उपभोक्ता जागरूकता और दुनिया भर में भारतीय रेशम के लिए ब्रांड छवि बनाने के लिए विपणन कार्यनीतियों के लिए एसएमओआई कार्य योजना तैयार करेगा।
4. एसएमओआई रेशम उत्पादों की मांग और आपूर्ति, उपभोक्ता वरीयताओं और भारतीय रेशम उत्पादों के लिए वैश्विक अवसर पर बाजार अध्ययन करेगा।
5. एसएमओआई सिल्क समग्र-2 योजना के तहत निधि सहायता प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा और निम्नलिखित गतिविधियों के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड को अपनी प्रशासन समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा:
   क. शुद्ध रेशम उत्पादों की बिक्री को लोकप्रिय बनाने के लिए सिल्क मार्क लेबल की खपत बढ़ाने के लिए सिल्क मार्क के पंजीकृत अधिकृत उपयोगकर्ताओं को निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान करना।
   ख. रेशम के ब्रांड और जेनेरिक प्रचार के लिए शुद्ध रेशम की वस्तुओं के प्राथमिक उत्पादकों को सहायता प्रदान करना । रेशम के गुणवत्ता आश्वासन के लिए कोसे और कच्चे रेशम परीक्षण उपकरण की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों में राज्य/सरकारी एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाएगी।

ग. मुख्य गतिविधियों के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश

1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड मुख्यालय और संस्थानों में लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी, भारत सरकार के कार्यालयों द्वारा की जाएगी।
2. वार्षिक कार्य योजना बैठक अप्रैल के दौरान आयोजित की जाएगी और विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभी संबंधितों को प्रशासनिक अनुमोदन के साथ कार्य योजना बैठक के निर्णयों से अवगत कराया जाएगा।
3. कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ योजना के सभी घटकों और गतिविधियों के तिमाही वित्तीय और भौतिक लक्ष्य शामिल होंगे।
4. वार्षिक कार्य योजना और प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के संस्थान/इकाइयां सभी औपचारिकताओं के साथ दूसरी तिमाही के अंत से पहले प्रस्ताव भेजेंगे।
5. बीज क्षेत्र के लिए वार्षिक कार्य योजना में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की अपनी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के अलावा राज्य क्षेत्र और आरएसपी के लिए घटक भी शामिल होंगे।
6. एकल खिड़की प्रणाली द्वारा खरीद/भंडार और निर्माण/रखरखाव दोनों के संबंध में प्रस्तावों, स्पष्टीकरण की मांग, अनुमोदन प्रदान करना, कार्यान्वयन प्रगति आदि की निगरानी की जाएगी।
7. योजनाओं के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर मासिक वित्तीय और भौतिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित इकाइयों द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
8. केंद्रीय क्षेत्र की सभी योजनाओं के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर आंतरिक मूल्यांकन केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

9. अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए कार्य योजना तैयार और कार्यान्वित की जाएगी।
10. सिल्क समग्र-2 अवधि के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा विकसित नई प्रौद्योगिकी/नवाचार को लाभार्थी उन्मुख घटकों के माध्यम से क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा।
11. केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा गठित एक समिति प्रौद्योगिकी/नवाचार के व्यावसायीकरण के लिए इकाई लागत का आकलन करेगी। समिति में उद्योग जगत के सदस्य भी शामिल होंगे।
12. प्रशासनिक व्यय या पदों के सृजन से संबंधित घटकों/मदों में वृद्धि नहीं की जाएगी। सामान्य वित्तीय/बजटीय पुनर्विनियोग नियमों का पालन किया जाएगा।
13. योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों में सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न होने वाली 1442 की अतिरिक्त रिक्तियों में से 30 वैज्ञानिकों और समूह-ए स्तर पर 10 प्रशासनिक अधिकारियों सहित 395 पद नहीं भरे जाएंगे।
14. प्रदर्शन उन्मुख जनशक्ति की नियुक्ति के माध्यम से अनुसंधान व विकास परियोजनाओं/सिल्क समग्र-2 योजना कार्यान्वयन/केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन में जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए योग्य व्यक्तियों, विशेषज्ञ सेवाओं, जेआरएफ/एसआरएफ आदि को लेने के लिए वार्षिक योजना तैयार की जाएगी।

घ. निधि का विमोचन और उपयोग

1. मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड को अनुमोदित वार्षिक बजट और सिल्क समग्र-2 के प्रावधानों के अनुसार निधि जारी की जाएगी और इकाई के अनुमोदित बजट/कार्य योजना के अनुसार पीएफएमएस के माध्यम से प्रत्यायोजित इकाइयों को आगे जारी किया जाएगा।
2. वित्तीय स्वीकृतियां, लेखा और व्यय केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मौजूदा नियमों के अनुसार होंगे और जीएफआर प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगे।
3. वार्षिक कार्य योजना के समग्र लक्ष्यों और उद्देश्यों से समझौता किए बिना, निधि की उपलब्धता के अधीन अंतर-घटक परिवर्तन की अनुमति है।
4. योजना के विभिन्न घटकों/उप-घटकों के लिए ईएफसी में प्रावधान केवल सांकेतिक है और वस्त्र मंत्रालय/केंद्रीय रेशम बोर्ड आवश्यकता आधारित अंतर-घटक परिवर्तनों का निर्णय ले सकता है।
5. ईएफसी में इंगित वर्ष-वार प्रावधान केवल सांकेतिक है और बजट प्रावधान के अधीन, किसी भी वर्ष के लिए ईएफसी प्रावधान से अधिक व्यय किया जा सकता है।
6. संलग्नक-I में दिए गए अनुसार जीएफआर 12-ए के अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।

III लाभार्थी-उन्मुख घटकों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश

क. सहायता के लिए उपलब्ध घटक

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा सीधे क्रियान्वित की गई प्रमुख गतिविधियों के अलावा, रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिल्क समग्र-2 योजना अवधि के दौरान क्षेत्र में आवश्यक कुछ लाभार्थी उन्मुख महत्वपूर्ण मध्यस्थताओं को लागू किया जाएगा। ये मध्यस्थता केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी पैकेजों के हस्तांतरण और अपनाने का महत्वपूर्ण साधन हैं। लाभार्थी उन्मुख मध्यस्थता के अंतर्गत कोसापूर्व एवं कोसोत्तर क्षेत्र जैसे परपोषी पौधों का विकास और विस्तार, रेशमकीट पालन के लिए समर्थन, रेशमकीट बीज उत्पादन बुनियादी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और सृजन, फार्म एवं कोसोत्तर क्षमताओं का विकास, रेशम धागाकरण व संसाधन प्रौद्योगिकियों का उन्नयन एवं कौशल विकास तथा कौशल उन्नयन के माध्यम से क्षमता विकास को शामिल किया जाएगा । इन घटकों को लाभार्थियों को व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए पैकेज के रूप में अथवा परियोजना के रूप में प्रदान किया जाएगा।

रेशम/रेशम उत्पादन क्षेत्र में रेशम उत्पादन हितधारकों को सशक्त करने एवं अपने कौशल व क्षमता को बढ़ाने/कौशल विकसित करने व कौशल उन्नयन के लिए (i) क्षमता विकास/प्रशिक्षण (ii) किसान नर्सरी के विकास के लिए सहायता और (iii) वन्य रेशम धागाकरण मशीनरी जैसे कुछ व्यक्तिगत घटकों के अलावा व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ-साथ रेशम व्यापार उद्यमियों/कॉर्पोरेट रेशम उत्पादन (खेत से वस्त्र - बड़े पैमाने पर खेती) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन हितधारकों के लिए पैकेजों के नौ बंडल उपलब्ध है ।

पैकेजों के बंडल निम्नानुसार है :

1. **शहतूत एवं वन्य रेशम कीटपालन के लिए सहायता पैकेज:** इस पैकेज में उन्नत किस्म के पौधारोपण, सिंचाई, कीटपालन गृह का निर्माण, कीटपालन उपकरण और कीटाणुनाशक की आपूर्ति (बेहतर उत्पादन के लिए रोगनिरोधी उपाय) के लिए समर्थन और शहतूत और वन्य रेशम के लिए चॉकी कीटपालन केंद्रों को लोकप्रिय बनाना शामिल है।
2. **रेशमकीट बीज कीटपालकों को सहायता:** इस मद के अंतर्गत, गुणवत्तायुक्त रेशमकीट बीज के उत्पादन के लिए तसर, एरी एवं मूगा क्षेत्रों में चॉकी उद्यान के विकास/रख-रखाव के अलावा अधिगृहीत बीज कीटपालकों को सशक्त बनाने, राज्य और पंजीकृत बीज उत्पादकों के लिए कीटाणुनाशक और बीज परीक्षण उपकरणों की खरीद के प्रति सहायता दी जाती है ।
3. **लघु एवं मध्यम धागाकरण इकाइयों के लिए सहायता:** यह उन्नत लघु एवं मध्यम शहतूत रेशम धागाकरण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करता है। इस पैकेज में सभी पहचाने गए और सूचीबद्ध उपकरण शामिल हैं।
4. **उद्यम हेतु स्वचालित रेशम धागाकरण मशीनरी पैकेज के लिए सहायता:** इकाई लागत में दर्शाए गए अनुसार सभी मशीनरी पुर्जे पैकेज में होंगे एवं इनकी आपूर्ति स्वचालित धागाकरण मशीन के साथ की जाएगी।

5. **प्यूपा संसाधन इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता:** इसमें पीलेड निष्कर्षण और प्यूपा पृथक्करण मशीन शामिल है। उपयुक्त संशोधनों के साथ, एरी क्षेत्र के लिए प्यूपा संसाधन और कैनिंग इकाई के लिए स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप भी इस मद का उपयोग किया जा सकता है।
6. **रेशम बुनाई क्षेत्र के लिए सहायता:** रेशम बुनाई क्षेत्र की सहायता के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और गैजेट्स के साथ रेशम बुनाई क्षेत्र की समस्याओं को हल करने जैसे बेहतर उत्पादकता, वस्त्रों की गुणवत्ता और बुनकरों के कठिन परिश्रम को कम करने के उपाय इस पैकेज में उपलब्ध हैं।
7. **रेशम रंगाई और संसाधन के लिए सहायता:** इस मद के अंतर्गत प्रस्तावित प्रौद्योगिकियां रेशम धागे की रंगाई और संसाधन क्षेत्र में पानी, ऊर्जा की खपत और जनशक्ति की आवश्यकता को कम करता है। रंगाई की गुणवत्ता में सुधार के अलावा, यह श्रमिकों को अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने में भी मदद करता है।
8. **रेशम व्यापार उद्यम के लिए सहायता पैकेज:** इस मद में द्विप्रज रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए आयात विकल्प, रेशम-व्यापार उद्यमी/कॉर्पोरेट रेशम उत्पादन (खेत से वस्त्र - बड़े पैमाने पर खेती)/उन्नत धागाकरण गतिविधि के माध्यम से उद्योग की भागीदारी युक्तिसंगत पैमाने के सब्सिडी समर्थन के साथ शामिल की गई है ।
9. **एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट - जीरो डिस्चार्ज और ग्राउंड डिस्चार्ज टाइप की स्थापना के लिए सहायता:** पैकेज ईटीपी के साथ रेशम सूत रंगाई और रेशम कपड़ासंसाधन सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करता है और प्रदूषण मुक्त संसाधन इकाइयों को प्रोत्साहित करता है।

ख. कार्यान्वयन अभिकरण

i. राज्य रेशम उत्पादन विभाग और वर्तमान प्रकिया के अनुसार राज्य सरकारों के अन्य समान विभाग ।

ii. राज्य रेशम उत्पादन विभागों को विभाग के माध्यम से इसे लागू करने अथवा पहचाने गए विशिष्ट क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकार के अनुमोदन के अनुसार उपयुक्त अभिकरण/स्थानीय निकायों की पहचान करने का विवेकाधिकार होगा।

iii. राज्य सरकार के कोई अन्य विभाग जैसे वन/बागवानी/कृषि/ग्रामीण विकास आदि, अपनी स्वयं की योजना के साथ बेहतर अभिसरण की सुविधा के लिए परियोजना मोड में इन घटकों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ग. निधि सहायता का दायरा और बजटीय आवंटन

(I) राज्यों के रेशम उत्पादन विभागों/समान विभागों को सहायता

1. सिल्क समग्र-2 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी लाभार्थी उन्मुख घटकों को परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य रेशम उत्पादन विभाग/इसी प्रकार के विभागों द्वारा लाभार्थी/हितधारकों के समर्थन के लिए कार्यान्वित किया जाएगा।
2. इसके अलावा, रेशम उत्पादन क्षेत्र में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने एवं रेशम उत्पादों के लिए बाजार संपर्क प्रदान करने हेतु राज्य की विशिष्ट आवश्यकता पर विचार करते हुए, राज्य के रेशम उत्पादन

अवसंरचना जैसे रेशमकीट बीजागार, राज्य के हितधारकों/रेशम उत्पादकों के लाभ हेतु विपणन अवसंरचना एवं गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली को सुदृढ करने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र और उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए भी राज्य रेशम उत्पादन विभाग प्रस्ताव कर सकते हैं।

3. इस तरह के की मध्यस्थता हेतु लागत राज्य लोनिवि/केलोनिवि के विद्यमान एसओआर के अनुसार होगी और जहां तक वित्त पोषण के हिस्सेदारी पैटर्न का संबंध है, राज्य को एक लाभार्थी के रूप में माना जाएगा।

(ii) उत्तर पूर्वी राज्यों को परियोजना आधारित सहायता

1. सिल्क समग्र-2 के अंतर्गत रेशम के स्थानीय उत्पादन और खपत के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला प्रदान करते हुए उत्तर-पूर्व में परियोजना आधारित रेशम उत्पादन गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने प्रस्ताव किया है ।
2. इसमें स्थानीय लोगों और कार्यान्वयन अभिकरणों के कार्यकर्ताओं के कौशल निर्माण व विकास, बुनियादी अवसंरचना के सृजन हेतु सहायता प्रदान करना, संवृद्धि सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना तथा घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में रेशम उत्पादों के लिए बाजार संपर्क प्रदान करना, हितधारकों की आय बढ़ाने के लिए देश के अंदर और बाहर बाज़ार उन्नयन गतिविधियों में भागीदारी जैसे घटक शामिल होंगे।
3. इसे संभव बनाने के लिए राज्य की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार, एनईआरटीपीएस परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित किए गए अनुसार, नई परियोजनाओं में सामान्य सुविधा केंद्रों, फार्म मशीनीकरण, कोसोत्तर एवं पोस्ट यार्न क्षेत्र, विपणन अवसंरचना एवं उत्कृष्ट केन्द्र आदि की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव किया जा सकता है।
4. इस तरह के मध्यस्थता की लागत सिल्क समग्र-2 के अंतर्गत अनुमोदित एनईआरटीपीएस/घटकों के अंतर्गत कार्यान्वित परियोजनाओं के आधार पर निर्माण गतिविधियां और उपकरणों तथा मशीनरी के लिए राज्य लोनिवि/ केलोनिवि अथवा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के वर्तमान एसओआर के अनुसार होगी।
5. परियोजना के अंतर्गत सृजित अवसंरचनाओं का परियोजना के पश्चात अनुरक्षण शीर्ष अनुमोदन व अनुश्रवण समिति के अनुमोदन से संबंधित राज्य विभागों अथवा राज्य विभाग द्वारा निर्धारित परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
6. परियोजना में आवश्यकता-आधारित अपेक्षाओं के आधार पर, परियोजना स्थानों के लिए उपकरणों और मशीनरी की परिवहन लागत, कर आदि को पूरा करने के लिए नव मध्यस्थता के माध्यम से परियोजना का वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए 10% की सीमा तक फ्लेक्सी फंड के अंतर्गत आवश्यक लिंकेज भी प्रदान किए जाएंगे।
7. सभी पूर्वोत्तर राज्यों में परिधान और परिधान इकाइयों को पूरा करने के लिए प्रावधान भी निर्धारित किया गया है। निधि पैटर्न और कार्यान्वयन दिशा-निर्देश एनईआरटीपीएस के अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे।

(iii) पूर्ववर्ती एनईआरटीपीएस के अंतर्गत चल रही रेशम उत्पादन परियोजना के लिए वित्त पोषण: रेशम उत्पादन के अंतर्गत चल रही एनईआरटीपीएस परियोजनाओं की बची हुई गतिविधियों को सिल्क समग्र-2 योजना के अनुमोदित कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त पोषित किया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई दिशानिर्देश नहीं होंगे। तथापि, इन परियोजनाओं को 31.03.2023 तक अनुमोदित डीपीआर के अनुसार पूरा किया जाना है।

(iv) निधि का आवंटन: सिल्क समग्र-2 योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों (2021-22 से 2025-26) के लिए कुल 1050.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निधि प्रावधान का इकाई-वार विवरण और इकाई लागत, शामिल की जाने वाली संभावित भौतिक इकाइयों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्य भी इस शीर्ष के अंतर्गत निधि सहायता के पात्र होंगे। तथापि, पूर्वोत्तर विशिष्ट रेशम उत्पादन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु रु.230.00 करोड़ अलग से आवंटित किया जाएगा और पूर्ववर्ती एनईआरटीपीएस के अंतर्गत चल रही परियोजना को पूरा करने के लिए चालू रेशम उत्पादन परियोजना/ए एंड जीएमयू के लिए 154.85 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की जाएगी। राज्यों को निधि का आवंटन पिछले 2-3 वर्षों में कच्चे रेशम के उत्पादन, रेशम उत्पादकों की संख्या, निधि का उपयोग, आकार, विकास दर और रेशम उद्योग के विस्तार के लिए भविष्य की संभावनाओं पर निर्भर करेगा।

घ. राज्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना

1. राज्य रेशम उत्पादन विभाग/इसी प्रकार के विभाग, विभाग के निदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं राज्य रेशम उत्पादन विभाग के सदस्यों निहित राज्य की परियोजना अनुश्रवण समिति (पीएमसी) के अनुमोदन के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। पीएमसी के गठन का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।
2. राज्य विभाग सिल्क समग्र-2 के अंतर्गत व्यक्तिगत किसानों के आधार पर और परियोजना मोड दोनों में सहायता प्राप्त कर सकता है। तथापि, कार्यान्वयन सख्ती से केवल क्लस्टर मोड में होगा जिसके प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 50 लाभार्थी होने चाहिए ।
3. राज्य रेशम उत्पादन विभाग/इसी प्रकार के विभाग द्वारा यथा लागू परियोजना अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति का गठन किया जायेगा।
4. इसी प्रकार के विभागों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को भी समान विभागों द्वारा गठित पीएमसी द्वारा निरीक्षित किया जाएगा।
5. इस प्रकार के विभाग के मामले में, केन्द्रीय रेशम बोर्ड/राज्य रेशम उत्पादन विभाग और कार्यान्वयन अभिकरण के बीच या केन्द्रीय रेशम बोर्ड और इस प्रकार के विभाग के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा।
6. केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा हिस्सेदारी पैटर्न के अनुसार और एएएमसी, केन्द्रीय रेशम बोर्ड मुख्यालय में सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति के अनुमोदन के पश्चात् निधि सीधे कार्यान्वयन अभिकरणों को विमोचित की जाएगी। एएएमसी के गठन का विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

7. केन्द्रीय रेशम बोर्ड उपलब्ध बजट के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों को निधि मंजूर कर विमोचित करेगा तथा प्रस्ताव के मूल्यांकन संबंधी प्रक्रिया निर्धारित करेगा।
8. सभी मामलों में, संबंधित राज्य विभाग/इसी प्रकार के विभाग ऐसे घटकों के लिए निधि के बराबर हिस्से की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
9. राज्यों के लिए निधि के अनंतिम अनुमोदित आवंटन को समय पर नए प्रस्तावों की योजना हेतु भारत सरकार द्वारा वार्षिक बजट आवंटन के अनुसार दिसंबर महीने के दौरान संसूचित किया जाएगा।
10. परियोजना की अवधि क्षेत्र स्तर की आवश्यकता के अनुसार घटकों/परियोजना क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर 2 से 3 वर्ष तक हो सकती है।
11. राज्यों को वर्ष-वार उत्पादन/परिणाम सहित वर्ष-वार एवं घटकवार निधि आवश्यकता का विवरण (भारत सरकार:राज्य:लाभार्थी) दर्शाते हुए अगले 5 वर्षों (2021-22 से 2025-26) के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना होगा।
12. प्रस्ताव में भारत सरकार/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से वित्त पोषण भी शामिल होगा (सिल्क समग्र-2, आरकेवीवाई, मनरेगा, राज्य का हिस्सा और अन्य, यदि कोई हो) ।
13. कार्यान्वयन करने वाला राज्य विभाग निधि मांगने के लिए परियोजना प्रस्ताव को अन्य विभागों को संदर्भित करेगा ताकि परियोजना की तैयारी और तद्संबंधी निधि उपलब्ध करने में अतिव्याप्ति और दोहराव न हो ।
14. परियोजना प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से लाभार्थियों की श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य की सहलग्नता और प्रत्येक समूह के लिए निधि की आवश्यकता का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।
15. परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले या निधि विमोचित करने से पहले राज्य द्वारा लाभार्थी का चयन किया जाएगा।
16. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के चयन को आसपास के समूह/ब्लॉक में क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और अधिक लचीला बनाया जाएगा ताकि योजना और निधि आवंटन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहलग्नता को अधिकतम किया जा सके।
17. परियोजना प्रस्तावों में स्पष्ट लक्ष्य, मापने योग्य लक्ष्य, संसाधन और समय अनुसूची होनी चाहिए। न्यूनतम परियोजना अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए।
18. उच्च सब्सिडी दर वाले लघु और सीमांत किसानों पर ध्यान केंद्रित करने और गतिविधियों को प्रारंभ करने के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्यमियों/किसान उत्पादक संगठन और कॉर्पोरेट क्षेत्र की सहायता करने के लिए योजना के हिस्सेदारी पैटर्न को युक्तिसंगत बनाया गया है।
19. राज्य एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि प्रस्तावित परियोजना में अन्य मंत्रालयों/विभागों से सहायता या लाभार्थियों का कोई अतिव्यापी या दोहराव नहीं है।

20. तदनुसार, योजना की तीन व्यापक श्रेणियां होंगी और प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किए जाएं :
    - लघु और सीमांत किसान
    - नए उद्यमी
    - विद्यमान उद्यमियों/लाभार्थियों को अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए।
21. प्रस्ताव तैयार करते समय फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जैसे पौधारोपण सामग्री की आपूर्ति, रेशमकीट बीज, अन्य निवेश और विपणन सहायता आदि सुनिश्चित की जानी चाहिए।
22. सिल्क समग्र-2 के अंतर्गत अपेक्षित घटक-वार मध्यस्थता और अन्य विभागों से भी अनुमोदित इकाई लागत, हिस्सेदारी पैटर्न, वर्ष-वार परिणाम और प्रत्याशित परिणाम आदि के अनुसार प्रत्येक घटक की लागत के साथ अभिसरण के माध्यम से परियोजना में उल्लेख किया जाएगा।
23. नर्सरी विकास घटक के लिए निधि आरकेवीवाई–आरएएफटीएएआर के अंतर्गत आरकेवीवाई के साथ अभिसरण के माध्यम से प्राप्त की जाए ।
24. कार्यान्वयन अभिकरण सामान्य अवसंरचना के सृजन के लिए आरकेवीवाई से निधि प्राप्त कर सकती हैं। इसी प्रकार कृषक स्तर पर पौधारोपण का विकास मनरेगा के माध्यम से उपलब्ध किया जाए।
25. कोसोत्तर क्षेत्र में स्थापित करने हेतु प्रस्तावित इकाई / अवसंरचना में कच्चे माल का उत्पादन, क्षेत्र और बाज़ार के बीच अच्छा और स्पष्ट संबंध होना चाहिए, ताकि कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित की जा सके ।
26. कोसापूर्व क्षेत्र के लिए परियोजना तैयार करने हेतु आरएस एंड जीआईएस/सिल्क्स पोर्टल के अनुसार केवल संभावित क्षेत्र की पहचान की जाएगी और गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों/ किसानों के साथ परामर्श किया जाएगा एवं प्रस्ताव में इसका उल्लेख किया जाएगा।
27. निष्पादन का बेंचमार्क सर्वेक्षण विद्यमान रेशम उत्पादन ब्लॉक/क्लस्टर पर किया जाएगा और प्रस्ताव में संदर्भित किया जाएगा।
28. राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्नलिखित को विस्तार से बताया जाएगा:
    i. परियोजना क्षेत्र की पहचान करने का औचित्य।
    ii. लाभार्थी की उपलब्धता और न्यूनतम 30% महिला लाभार्थी हैं।
    iii. प्रस्ताव के साथ या बाद में, लेकिन निधि विमोचित करने से पहले, आधार संख्या, भूमि का स्वामित्व, वर्तमान व्यवसाय और आय स्तर आदि सहित लाभार्थी का डेटा बेस।
    iv. विस्तृत कार्य योजना और समय पर कार्यान्वयन के लिए मौसम और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर गतिविधियों का समकालिक फ्लो चार्ट।
    v. प्रस्ताव में क्षमता विकास और प्रशिक्षण की आवश्यकता और बुनियादी अवसंरचना की जियो-टैगिंग की व्यवस्था संबंधी विवरण भी होगा।

29. प्रस्ताव में वर्तमान बुनियादी अवसंरचना का मानचित्रण शामिल होगा जो वर्तमान सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग और अंतराल को पूरा करने, यदि कोई हो तो, को सक्षम करने के लिए संस्थापित क्षमताओं और कार्य क्षमताओं को दर्शाता है।
30. जहां तक संभव हो, राज्य को सिल्क समग्र-2 के अंतर्गत द्विप्रज रेशम उत्पादन पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि आयात विकल्प रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके।
31. घटकों के पैकेज के रूप में उपलब्ध सहायता और साथ ही प्रत्येक घटक पर संक्षिप्त लेख एवं इकाई लागत संबंधी विवरण, सिल्क समग्र-2 योजना के अंतर्गत परियोजना की तैयारी/सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राज्य विभागों को परिचालित किया जाएगा **(अनुबंध-IX)**।
32. पैकेज में कुल लागत की समग्र सीमा होगी। तथापि पैकेज के अंदर वैयक्तिक घटकों की इकाई लागत लचीली होगी और एक घटक से बचत, यदि कोई हो, का उपयोग अन्य घटक के लिए किया जा सकता है, जहां यह अनुमोदित हिस्सेदारी पैटर्न के अनुसार इकाई लागत से अधिक होती है।
33. पैकेज में लचीलापन केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा गठित एक तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड और राज्य के सदस्य होंगे। पीएमसी तकनीकी समिति की सिफारिशों की जांच करेगी और योग्यता के आधार पर मंजूरी देगी।
34. सिल्क समग्र-2 के अंतर्गत घटकों का कार्यान्वयन करते समय, ब्याज के रूप में अर्जित राशि, यदि कोई हो, का उपयोग केवल पीएमसी के अनुमोदन से रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रमों/अतिरिक्त गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
35. कोई भी सरकारी पंजीकृत संगठन/निकाय/संघ/स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों/एसपीवी और एफपीओ अपना प्रस्ताव केवल संबंधित राज्य रेशम उत्पादन विभागों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव की जांच कर सिफारिश के लिए राज्य परियोजना अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
36. राज्य विशेष रूप से लाभार्थियों के लिए कोई घटक(कों) को कार्यान्वित करने का इच्छुक है, तो राज्य फार्मों/राज्यों की इकाइयों में राज्य हिस्से के अलावा लाभार्थियों के हिस्से का भी वहन कर, ऐसे कर सकते हैं ।
37. परियोजना लागत का 10% तक फ्लेक्सी फंड और 5% सूचना, शिक्षा और संचार, प्रशासन और अनुश्रवण के प्रति प्रस्तावित किया जा सकता है। इसमें से भारत सरकार का हिस्सा परियोजना के घटकों के लिए कुल केन्द्रीय रेशम बोर्ड के हिस्से के अनुपात में होगा।
38. फ्लेक्सी फंड का उपयोग परियोजना कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग, अभिनव घटकों [जो योजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान विकसित किए गए हैं], रेशम मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली की स्थापना, नए रूप में प्रस्तावित कृषक समूहों से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन तथा उपकरण/मशीनरी के लागत वृद्धि के प्रति किया जाएगा।
39. केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कुल परियोजना लागत के 2.5% एक स्वतंत्र सरकार/बाहरी अभिकरण द्वारा सिल्क समग्र-2 योजना के समर्थन से सृजित अवसंरचना की जांच और क्षेत्र की गतिविधियों के निष्पादन के

मूल्यांकन के प्रति आने वाले व्यय को पूरा करने के लिए रखा जाएगा। यह राशि परियोजना तैयार करते समय राज्य द्वारा निर्धारित की जाने वाली आईईसी का हिस्सा होगी।

ङ. परियोजना मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए तंत्र

i. परियोजना प्रस्ताव को सभी आवश्यक प्रमुख निवेश/पैरा को ध्यान में रखते हुए सुझाए गए टेम्प्लेट के अनुसार तैयार किया जाएगा, जैसा कि **अनुबंध-V** के चेक लिस्ट में दर्शाया गया है।

ii. सभी परियोजना प्रस्तावों को चर्चा और अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय परियोजना अनुश्रवण समिति (पीएमसी) के समक्ष रखा जाएगा और केन्द्रीय रेशम बोर्ड को अग्रेषित किया जाएगा।

iii. केन्द्रीय रेशम बोर्ड की आंतरिक मूल्यांकन समिति (तकनीकी, अनुसंधान, बीज, पीसीटी, वित्त और सांख्यिकीय प्रभागों के सदस्यों सहित) (आईएसी) द्वारा परियोजना की संवीक्षा की जाएगी जो बोर्ड सचिवालय स्तर के शीर्ष अनुमोदन और अनुश्रवण समिति (एएएमसी) द्वारा अनुमोदन और निधि विमोचन के लिए सिफारिश करेगी।

iv. लाभार्थी उन्मुख घटकों के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर निधि विमोचित करने के लिए विचार किया जाएगा।

v. योजना की प्रगति की समीक्षा और कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए दो समितियां (i) केन्द्रीय रेशम बोर्ड मुख्यालय में शीर्ष अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति और (ii) राज्य स्तर पर परियोजना अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। इन समितियों की संरचना और विचाराधीन विषय **अनुबंध-III और IV** में हैं ।

vi. राज्यों में इसी प्रकार के विभागों के लिए उनके संसाधनों से समकक्ष निधि के साथ परियोजना प्रारंभ करने के लिए एक अलग परियोजना अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। तथापि, उस समिति में राज्य रेशम उत्पादन विभाग और केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक-एक सदस्य को शामिल किया जाएगा।

vii. उत्पादन और परिणाम के संदर्भ में लाभार्थी-उन्मुख घटकों के निष्पादन की समीक्षा **अनुबंध-VI** में सुझाई गई है।

च. निधि विमोचन

i. निधि किश्तों में सिंगल विंडो विमोचन प्रणाली के माध्यम से संबंधित राज्यों तथा इसी प्रकार के विभागों को विमोचित की जाएगी।

ii. केन्द्रीय रेशम बोर्ड अनुमोदित इकाई लागत और हिस्सेदारी पैटर्न के अनुसार भारत सरकार का शेयर विमोचित करेगा। केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निधि विमोचित करने के बाद, जहां तक संभव हो, एक घटक से दूसरे घटक में निधियों के पुनर्विनियोजन से बचें ।

iii. प्रथम वर्ष के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पहली किस्त विमोचित की जाएगी। अनुवर्ती किस्त परियोजना के कार्यान्वयन, उपयोग प्रमाण-पत्र और प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुतीकरण के आधार पर विमोचित की जाएगी।

iv. भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान विमोचन के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन अभिकरणों को उचित समय की आवश्यकता और वार्षिक आधार पर गतिविधि के फ्लो चार्ट के अनुसार निधि विमोचित करने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे ।

v. कार्यान्वयन अभिकरणों को पीएफएमएस के माध्यम से और राज्य से लाभार्थियों को आधार एनेबुल्ड डीबीटी मोड के माध्यम से धनराशि जारी की जाएगी।

vi. गैर सरकारी संगठन/स्वयं सहाय समूह कार्यान्वयन अभिकरण होने की स्थिति में, वे परियोजना के लिए एक एस्क्रो (ESCROW) खाता खोलेंगे। केन्द्रीय रेशम बोर्ड और राज्य परियोजना के कार्यान्वयन और परियोजना पश्चात अवसंरचना के रख-रखाव और रेशम उत्पादन को जारी रखने के लिए कार्यान्वयन करने वाले गैर सरकारी संगठन/स्वयं सहाय समूह के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापितकरेंगे।

छ. उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना

i. राज्य सरकारों को विमोचित धनराशि के लिए निर्धारित प्रपत्र अर्थात जीएफआर-12 सी में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और राज्य के संबंधित रेशम उत्पादन विभाग या इसी प्रकार के विभाग के लेखा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। विवरण **अनुबंध-VII** में दिया गया है।

ii. उपयोगिता प्रमाण-पत्र लाभार्थियों की सूची और हितधारकों को नकद (डीबीटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड) और काइन्ड बेनिफिट मोड में खर्च की गई या विमोचित राशि के प्रति भौतिक प्रगति के साथ समर्थित किया जाएगा।

iii. घटक-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण और लाभार्थी विवरण मासिक आधार पर डीबीटी के "सर्विसप्लस" पोर्टल में अपडेट किया जाएगा।

iv. वित्तीय वर्ष जिसके दौरान राज्यों को राशि विमोचित की जाती है, पूरा होने के 12 महीनों के अंदर प्रगति रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

v. जीएफआर 2017 के प्रावधान के अनुसार नए विमोचन पर विचार करते समय, परियोजना के लिए पिछले वर्ष के निधि विमोचन के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति पर ध्यान रखा जाएगा।

ज. राज्य द्वारा लाभार्थी उन्मुख महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश

i. परियोजनाओं को तैयार करने एवं कार्यनीति व वार्षिक कार्य योजना तैयार करने से पहले केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से परामर्श किया जाएगा।

ii. राज्य गैर सरकारी संगठनों, एसपीवी, स्वैच्छिक सेवा संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को लाभार्थियों/हितधारकों की पहचान करने और यहां तक कि परियोजना को लागू करने में शामिल कर सकते हैं।

iii. राज्य सरकार, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से जहां कहीं लागू हो, ऋण सुविधाओं की सुविधा प्रदान करेगा।

iv. एक लाभार्थी योजना पैकेज में शामिल सहायक घटकों के साथ पौधारोपण विकास के लिए पांच एकड़ तक की सहायता प्राप्त कर सकता है।

v. मोबाइल एप के विकास के माध्यम से किसानों को कोसा और कच्चे रेशम के बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए पुल सेवा का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

vi. अधिकांश पौधारोपण गतिविधियाँ, विशेष रूप से वन्य के मामले में, राज्य वन विभागों, ग्रामीण विकास विभाग आदि के साथ करीबी-समन्वय में की जाएंगी।

vii. राज्य विशेष रूप से रेशमकीट बीज उत्पादन और कोसोत्तर क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।

viii. सिल्क समग्र-2 योजना के सहयोग से विकसित अवसंरचना के रख-रखाव/आवर्ती लागत का उत्तरदायित्व उद्यमियों/हितधारकों/राज्यों का होगा, जैसी भी स्थिति हो ।

ix. फ्लेक्सी फंड के अंतर्गत 'विशेष पहल' के लिए किए गए प्रावधान, उन अप्रत्याशित महत्वपूर्ण क्षेत्रों/अंतरालों के लिए उपयोग किया जाना है जो पीएमसी/एएएमसी की सिफारिशों के आधार पर कार्यान्वयन के दौरान हल किये जाएंगे।

x. लाभार्थी स्तर पर सृजित की जाने वाली सभी संपत्तियों की जियो-टैगिंग की जानी है।

xi. योजना/घटकों के अंतर्गत पैकेजों/घटकों के लिए निर्धारित इकाई लागत अधिकतम सीमा है और यदि यह किसी राज्य में कम है, तो केंद्र का हिस्सा तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

xii. यह सुनिश्चित किया जाना है कि सिल्क समग्र-2 योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के बाद अगले पांच वर्षों तक हितधारक रेशम उत्पादन जारी रखता है । राज्य विभाग इसके लिए कानूनी रूप से वैध करार/समाझौता ज्ञापन के माध्यम से उपयुक्त सहारा तंत्र विकसित करेगा।

झ. लाभार्थी उन्मुख सिल्क समग्र-2 पैकेजों/घटकों के लिए निधिकरण पैटर्न

1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के अलावा व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख सिल्क समग्र-2 घटकों के लिए निधि हिस्सेदारी पैटर्न (%):

श्रेणी (लघु एवं सीमांत कृषक)	भारत सरकार (केन्द्रीय रेशम बोर्ड)	राज्य	लाभार्थी
सामान्य राज्य	50%	25%	25%
सामान्य राज्य– एससीएसपी एवं टीएसपी के लिए	65%	25%	10%
विशेष स्तर प्राप्त राज्य (सामान्य, एससीएसपी एवं टीएसपी श्रेणी के लिए)	80%	10%	10%

2. रेशम उत्पादन बिजनेस एंटरप्राइज/नए उद्यमियों के लिए फंडिंग पैटर्न (%) :

श्रेणी (नए उद्यमी/स्टार्टअप)	भारत सरकार (केन्द्रीय रेशम बोर्ड)	राज्य	लाभार्थी
सामान्य	30%	20%	50%
एससीएसपी, टीएसपी, विशेष स्तर प्राप्त राज्य/पूर्वोत्तर राज्य	40%	30%	30%
मौजूदा उद्यमी			
सामान्य	20%	20%	60%
एससीएसपी, टीएसपी, विशेष स्तर प्राप्त राज्य/पूर्वोत्तर राज्य	30%	30%	40%

हालांकि, कुछ अपवादात्मक मामलों में, यदि पात्र व्यक्तिगत लाभार्थी राज्य के हिस्से के साथ-साथ लाभार्थी के हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार है, तो एएएमसी राज्य के बराबर हिस्से के लिए शेयरिंग पैटर्न के अनुसार शर्त में छूट दे सकती है, और केंद्रीय हिस्से के समर्थन पर विचार करेगी। ऐसे सभी मामलों में, निधियों के केंद्रीय हिस्से की हिस्सेदारी अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि, राज्य विभाग घटक के कार्यान्वयन के लिए कार्यप्रणाली तैयार करेगा और यह भौतिक रूप से सत्यापन योग्य होगा।

3. एनईआरटीपीएस के अनुरूप पूर्वोत्तर विशिष्ट रेशम उत्पादन परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण पैटर्न (%) निम्नानुसार जारी रखा जाएगा:

श्रेणी	भारत सरकार (केन्द्रीय रेशम बोर्ड)	राज्य	लाभार्थी
समूह गतिविधि/समुदाय आधारित कार्यक्रम **(छोटे और सीमांत किसान)**	100%	-	-
सामान्य सुविधा/राज्य अवसंरचना	90%	10%	-
व्यक्तिगत लाभ **(छोटे और सीमांत किसान)**	90%	-	10%

ञ. अनुश्रवण और मूल्यांकन

1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड स्तर पर, शीर्ष अनुमोदन और अनुश्रवण समिति (एएएमसी) परियोजनाओं को लागू करने के निष्पादन का अनुश्रवण और समीक्षा करेगी और अनुमोदन और निधि जारी करने के लिए राज्यों के नए प्रस्तावों की भी जांच करेगी।
2. केंद्रीय क्षेत्र की चालू योजना के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा राज्य पीएमसी द्वारा की जाएगी।
3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अनुश्रवण के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड मुख्यालय, बेंगलुरु में अनुश्रवण कक्ष भी बनाएगा, परियोजना से संबंधित डेटा बनाए रखेगा और डेटा वेयरहाउसिंग और सूचना के सुचारू प्रवाह के लिए संबंधित कार्यान्वयन राज्य/एजेंसी के साथ समन्वय करेगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय केन्द्रीय रेशम बोर्ड और राज्य के बीच संपर्क स्थापित करेंगे।

4. अनुश्रवण प्रकोष्ठ कुछ सरकारी एजेंसियों के माध्यम से या बाहरी एजेंसी को आउटसोर्स के माध्यम से सिल्क समग्र -2 योजना के तहत बनाए गए लाभार्थी समर्थन / बुनियादी ढांचे की जांच और अनुश्रवण के संचालन में सहायता करेगा।
5. सिल्क समग्र-2 योजना के तहत प्रदान की गई लाभार्थी सहायता/सृजित बुनियादी ढांचे की जांच के व्यय को केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा रखी गई परियोजना लागत के 2.5% में से पूरा किया जाएगा।
6. जांच से पहले, रेशम उत्पादन विभाग अप्रैल के पहले सप्ताह में केन्द्रीय रेशम बोर्ड को प्रगति और समापन रिपोर्ट का विवरण प्रदान करेगा। अधिमानतः परियोजना के लिए धन की अगली किस्त जारी करने से पहले वर्ष में एक बार सत्यापन किया जाएगा।
7. केंद्रीय रेशम बोर्ड एक अनुश्रवण फारमेट तैयार करेगा और इसे केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सूचना प्रस्तुत करने के लिए रेशम उत्पादन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
8. केंद्रीय रेशम बोर्ड लाभार्थी द्वारा सभी भौतिक अवसंरचना (अचल संपत्ति) की जियो-टैगिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराएगा। रेशम उत्पादन विभाग इस उद्देश्य के लिए लाभार्थी के साथ समन्वय और सहायता करेगा।
9. ऐसे सभी डेटाबेस को केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सिल्क्स पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा और राज्य नियमित रूप से डेटा अपलोड करेंगे।
10. संबंधित राज्यों के केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय/नामित नोडल अधिकारी परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने में राज्यों/ विभागों की मदद करेंगे।
11. तकनीकी समिति सिल्क समग्र-2 योजना के अंतर्गत क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रम का नियमित रूप से अनुश्रवण अर्धवार्षिक आधार पर करेगी, जिसमें समूह-क/वर्ग-I अधिकारी अर्थात केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक और राज्य क्षेत्र अधिकारी शामिल होंगे।
12. तकनीकी समिति प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए सुझाई गई जांच सूची **(अनुबंध-VIII)** के अनुरूप नए परियोजना प्रस्तावों की भी जांच करेगी और राज्य पीएमसी द्वारा विचार के लिए सिफारिश करेगी।
13. एएएमसी की बैठक से पहले, केन्द्रीय रेशम बोर्ड मुख्यालय में आंतरिक मूल्यांकन समिति परियोजना प्रस्ताव की समीक्षा करेगी और बाद में एएएमसी द्वारा विचार के लिए सिफारिश करेगी।
14. कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर वार्षिक संयुक्त जांच, मूल्यांकन और सामाजिक अंकेक्षण राज्य के क्षेत्रीय अधिकारियों को शामिल करते हुए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा।
15. योजना कार्यान्वयन में मध्यावधि सुधार/संशोधन का सुझाव देने के लिए वर्ष 2023-24 के अंत में किसी बाहरी एजेंसी द्वारा योजना/घटकों का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा।
16. सिल्क समग्र-2 योजना के समग्र निष्पादन पर अंतिम मूल्यांकन अध्ययन और योजना को आगे जारी रखने की सिफारिश बाहरी एजेंसी द्वारा 2025-26 के अंत में की जाएगी।

17. राज्य स्तरीय शीर्ष समिति अर्थात राज्य स्तरीय रेशम उत्पादन समन्वय समिति (एसएलएससीसी) संबंधित राज्य के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राज्यों में रेशम उत्पादन विकास गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। समिति राज्य में रेशम उत्पादन और रेशम क्षेत्र के मामले में नीतिगत निर्णय भी लेगी। समिति की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी। समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

(i)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव	- अध्यक्ष
(ii)	लाइन विभाग के सचिव	- सदस्य
(iii)	सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड या उनके प्रतिनिधि	- सदस्य
(iv)	रेशम उत्पादन के निदेशक/आयुक्त	- सदस्य
(v)	केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान संस्थान / बीज संगठन के निदेशक या उनके प्रतिनिधि	- सदस्य
(vi)	रेशम उत्पादन विभाग मुख्यालय से वरिष्ठ रेशम उत्पादन अधिकारी	- सदस्य
(vii)	राज्य के रेशम उत्पादन संघ के चेयरमेन/प्रेसिडेन्ट	- सदस्य
(viii)	कोसा पूर्व व कोसोत्तर क्षेत्र से दो हितधारक	- सदस्य
(ix)	प्रभारी, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड	- सदस्य संयोजक

ट. सिल्क समग्र-2 हेल्पलाइन

हितधारकों की शिकायतों को दूर करने एवं जागरूकता पैदा करने तथा सूचनाओं को साझा करने के लिए एक हेल्पलाइन और विशेष ई-मेल आईडी, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं। ये इस प्रकार हैं:

हेल्प लाइन नंबर	: 080-26282612
फेसबुक	: https://www.facebook.com/central.Silkboard
ट्विटर	: http://twitter.com/csbmot/
वेबसाइट	: http: //www.csb.gov.in/
ईमेल आईडी	: csbsilksamagra2@gmail.com

अनुबंध।

एफआर 12 – ए

[(नियम 238 (1) देखें)]

उपयोगिता प्रमाण पत्र

अनुदान पाने वाले संगठन के स्वायत्त निकायों के लिए

आवर्ती/गैर-आवर्ती

सहायता अनुदान/वेतन/पूंजीगत संपत्ति के सृजन के संबंध में

.....वर्ष के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र

1. योजना का नाम.....
2. क्या आवर्ती या अनावर्ती अनुदान ....
3. वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
   (i) नगद/बैंक .....
   (ii) असमायोजित अग्रिम .....
   (iii) कुल .....
4. प्राप्त अनुदान, किए गए व्यय और अंतिम शेष का विवरण: (वास्तविक)

प्राप्त अनुदानों की अव्ययित शेष राशि [आंकड़ा क्र.सं. सं. 3 (iii)] के अनुसार	उस पर अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध निधि (1+2-3+4)	किया गया व्यय	अंत शेष (5-6)
1	2	3	4			5	6	7
			संस्वीकृति संख्या	दिनांक	राशि			
			(i)	(ii)	(iii)			

अनुदानों का घटक-वार उपयोग:

सामान्य सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदान	पूंजीगत संपत्ति का सृजन सहायता अनुदान	कुल

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

(I) नकद / बैंक .....

(ii) असमायोजित अग्रिम .....

(iii) कुल .....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किया गया था, उन्हें विधिवत पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित की जांच की है कि धन का उपयोग वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था:

(i) संबद्ध अधिनियम/नियमों/स्थायी अनुदेशों (अधिनियम/नियमों का उल्लेख करें) में निर्धारित अनुसार मुख्य खातों और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों (संपत्ति रजिस्टरों सहित) का रखरखाव किया जाता है और निर्दिष्ट लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत् लेखा परीक्षा की जाती है। ऊपर दर्शाए गए आंकड़े वित्तीय विवरणों/लेखों में उल्लिखित लेखापरीक्षित आंकड़ों से मेल खाते हैं।

(ii) सार्वजनिक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा वित्तीय इनपुटों पर भौतिक लक्ष्यों व उपलब्धियों के परिणामों को देखने तथा परिसंपत्ति निर्माण आदि में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद है और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।

(iii) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, प्रासंगिक अधिनियम/नियमों/स्थायी अनुदेशों और योजना मार्गदर्शनों का उल्लंघन किसी भी लेनदेन में दर्ज नहीं किया गया है ।

(iv) योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख पदाधिकारियों के बीच उत्तरदायित्व स्पष्ट शब्दों में सौंपे गए हैं और प्रकृति में सामान्य नहीं हैं।

(v) लाभ इच्छित लाभार्थियों को दिए गए थे और केवल उन्हीं क्षेत्रों/जिलों को कवर किया गया था जहां योजना को संचालित करने का उद्देश्य था।

(vi) योजना के विभिन्न घटकों पर व्यय योजना के दिशा-निर्देशों और सहायता अनुदान के नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।

(vii) यह सुनिश्चित किया गया है कि ..... (योजना का नाम) के तहत भौतिक और वित्तीय निष्पादन आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित है, वर्ष जिसके लिए निधि के उपयोग है, के दौरान निष्पादन/लक्ष्य प्राप्त विवरण अनुबंध-I में विधिवत् संलग्न हैं।

(viii) निधि के उपयोग के फलस्वरूप अनुबंध-II में दिए गए परिणाम विधिवत् संलग्न हैं (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना है।)

(ix) उसी मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायता अनुदान के माध्यम से एजेंसी द्वारा निष्पादित विभिन्न योजनाओं का विवरण अनुबंध-II (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना) में संलग्न है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर
नाम.....
संगठन के प्रमुख

हस्ताक्षर
नाम.....
मुख्य वित्त अधिकारी (वित्त प्रमुख)

(अनुपयुक्त शर्तों को काट दें)

अनुबंध-II

इकाई लागत सहित लाभार्थी उन्मुख मध्यस्थता और 5 वर्षों में कवर की जाने वाली भौतिक इकाइयां (2021-22 से 2025-26)

#	योजना और घटक	इकाई लागत (रु.)	कुल भौतिक (2021-26)	वित्तीय (करोड़ रुपये में) (2021-26) भारत सरकार का हिस्सा
क	**रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए क्षमता विकास और प्रशिक्षण**			
1	कौशल निर्माण और कौशल उन्नयन के लिए क्षमता विकास और प्रशिक्षण (इकाई संख्या)	7,000	18250	12.78
ख	**पूर्व कोसा सेक्टर**			
1	**शहतूत और वन्य के लिए किसान नर्सरी के विकास हेतु सहायता**			
1क	शहतूत किसान नर्सरी (इकाई प्रति एकड़)	1,50,000	350	3.15
1ख	वन्य किसान नर्सरी (इकाई प्रति एकड़)	1,00,000	50	0.38
2	**रेशमकीट पालन के लिए सहायता पैकेज (शहतूत और वन्य)**			
2क	शहतूत रेशमकीट पालन 250 डीएफएल क्षमता (केवल दक्षिणी क्षेत्र) (इकाई संख्या) 2 एकड़ पौधारोपण के लिए	7,50,000	10260	461.7
2ख	शहतूत रेशमकीट पालन 150 डीएफएल क्षमता (केवल दक्षिणी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र) (इकाई संख्या) 1 एकड़ पौधारोपण के लिए	5,00,000	5280	171.6
2ग	शहतूत रेशमकीट पालन 100 डीएफएल क्षमता (केवल उत्तर-पश्चिम क्षेत्र) (इकाई संख्या) 0.5 से 1 एकड़ पौधारोपण के लिए	3,00,000	1822	40.99
2घ	**वन्य रेशमकीट पालन (इकाई प्रति एकड़)**			
	तसर	1,20,000	2000	18
	एरी	1,50,000	2500	28.12
	मूगा	2,00,000	250	4
3	**चॉकी कीट पालन केंद्रों का लोकप्रियकरण (संख्या)**	13,00,000	100	7.8
	ख. उपकुल (पूर्व-कोसा)		22612	729.61
ग	**बीज क्षेत्र**			
1	**रेशमकीट बीज पालकों को सहायता**			
1क	शहतूत रेशमकीट बीज पालक	5,00,000	600	18
1ख	वन्य रेशमकीट बीज पालक	5,00,000	1000	35

#	योजना और घटक	इकाई लागत (रु.)	कुल भौतिक (2021-26)	वित्तीय (करोड़ रुपये में) (2021-26) भारत सरकार का हिस्सा
2	**रेशमकीट बीज उत्पादन इकाइयों को सहायता**			
2क	बीजागार भवन का निर्माण (10000वर्ग फीट) और बीजागार उपकरण की खरीद (शहतूत-द्विप्रज)	2,16,00,000	17	22.03
2ख	वन्य रेशमकीट बीज	6,00,000	25	1.12
2ग	वन्य निजी बीजागार	5,00,000	500	18.75
	ग. उप कुल (बीज क्षेत्र)		2142	94.9
घ	**कोसोत्तर सेक्टर**			
1	**लघु और मध्यम शहतूत रेशम धागाकरण इकाइयों के लिए समर्थन**			
1क	बाल श्रम को रोकने के लिए मोटर चालित चरखा	30,000	100	0.18
1ख	मौजूदा कुटीर बेसिन/घरेलू बेसिन इकाइयों का उन्नयन	2,40,000	500	7.2
1ग	मल्टी-एंड रीलिंग इकाइयों की स्थापना – 10 बेसिन	20,76,000	125	15.57
2	**व्यक्ति के लिए स्वचालित रेशम धागाकरण मशीनरी पैकेज के लिए समर्थन**			
2क	एआरएम यूनिट की स्थापना-120 छोर	39,15,000	100	21.53
2ख	एआरएम यूनिट की स्थापना - 200 छोर	85,90,000	20	9.45
2ग	एआरएम यूनिट की स्थापना - 400 छोर	1,49,66,500	85	69.97
2घ	ऐंठन इकाइयों के लिए सहायता (480 तकली क्षमता)	11,00,000	100	6.05
2च	धागाकरण इकाइयों के लिए जल पुनर्चक्रण संयंत्र की स्थापना (1.0 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता)	18,00,000	19	1.88
3	**उद्यम के लिए स्वचालित रेशम धागाकरण मशीनरी पैकेज के लिए समर्थन**			
	एआरएम यूनिट की स्थापना - 5 लाइन (2000 छोर)	5,98,00,000	5	8.97
4	**प्यूपा प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए समर्थन**	22,85,700	40	5.03
5	**वन्य धागाकरण और कताई इकाइयों के लिए समर्थन**			
	बुनियाद धागाकरण मशीन	9,750	6000	4.39
	सोनालिका मूगा आर्द्र धागाकरण मशीन	16,330	675	0.88
	उन्नति धागाकरण मशीन	27,300	250	0.51

#	योजना और घटक	इकाई लागत (रु.)	कुल भौतिक (2021-26)	वित्तीय (करोड़ रुपये में) (2021-26) भारत सरकार का हिस्सा
	मोटर चालित धागाकरण व ऐंठन मशीन	25,350	360	0.64
	मोटर चालित-सह-पेडल संचालित कताई मशीन	8,050	250	0.14
	मोटर संचालित सिंगल विंडो पुन: धागारण मशीन	16,000	100	0.11
	तसर धागाकरण मशीनरी पैकेज	13,87,000	6	0.58
	लघु एरी कताई संयंत्र	80,00,000	5	2.8
6	**रेशम उद्योग के लिए ट्विस्टर/बुनकर/रंगरेज/ मैकेनिक के रूप में मास्टर धागाकार/ तकनीशियनों की सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता**	2,52,000	375	9.45
7	**नामित कोसा बाजार में कोसा सुखाने की सुविधा के लिए सहायता**			
	कन्वेयर हॉट एयर ड्रायर	16,77,500	10	0.92
	कन्वेयर हॉट एयर ड्रायर (2000 किलो क्षमता)	24,27,000	5	0.67
8	**रेशम बुनाई क्षेत्र के लिए सहायता**			
	संशोधित क्षेत्र विशिष्ट रेशम हथकरघा (पिटलूम)	41,000	1600	3.94
	कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइनिंग (CATD) यूनिट	5,85,000	130	4.56
	इलेक्ट्रॉनिक जैक्कार्ड (720 हुक) लिफ्टिंग मैकेनिज़म के साथ	2,42,000	585	8.49
	जैक्कार्ड, पर्न वाइंडिंग और अन्य उपकरणों के माध्यम से करघा उन्नयन	17,500	850	0.89
	न्यूमेटिक लिफ्टिंग मेकेनिज़म (पीएलएम) - 2 करघा इकाई	38,000	250	0.57
	अनुभागीय वार्पिंग मशीन / बॉल वार्पिंग मशीन	35,000	450	0.95
	एएसयू मशीन और वाइंडिंग मशीन पैकेज	45,000	450	1.22
9	**रेशम रंगाई और प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सहायता**			
	माइक्रो टब रंगाई यूनिट - 2 किलो यूनिट	1,00,000	80	0.44
	टब रंगाई - 50 किलो यूनिट	10,13,000	15	0.84
	आर्म रंगाई - 50 किलो इकाई	23,80,000	5	0.65
	आवश्यक आर्द्र प्रसंस्करण मशीनरी पैकेज के साथ सिल्क डिजिटल प्रिंटिंग मशीन (केवल उद्यम)	1,65,00,000	5	2.48
	फैब्रिक प्रोसेसिंग यूनिट - 250 किग्रा	34,34,000	5	0.94

#	योजना और घटक	इकाई लागत (रु.)	कुल भौतिक (2021-26)	वित्तीय (करोड़ रुपये में) (2021-26) भारत सरकार का हिस्सा
	फिनिशिंग यूनिट	11,42,000	8	0.5
9क	**सेरिसिन एक्सट्रैक्शन यूनिट - 10किलो क्षमता**	15,24,000	8	0.67
10	**रेशम प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बहिःस्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) की स्थापना के लिए सहायता**			
	ईटीपी - जमीन पर निर्वहन	10,00,000	13	0.72
	ईटीपी – शून्य निर्वहन	15,00,000	8	0.66
	क. उप-कुल (कोसोत्तर क्षेत्र)		13592	195.44
घ	**फ्लेक्सी फंड (परियोजना लागत का 10%)**	**लागू नहीं**		17.27
		कुल वित्तीय		1050

अनुबंध-III

परियोजना अनुश्रवण समिति (राज्य स्तरीय)

गठन	विचारार्थ विषय
1. राज्य के रेशम उत्पादन आयुक्त/ निदेशक/संबद्ध विभाग के प्रमुख **सदस्य** 2. निदेशक, केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु या उनके प्रतिनिधि 3. संबंधित केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान संस्थान के निदेशक/उनके स्थानीय प्रतिनिधि 4. राज्य मुख्यालय में रेशम उत्पादन विभाग के वरिष्ठ लेखा अधिकारी 5. कृषि, आरडी / अन्य विभाग जहां से अभिसरण प्रस्तावित के अधिकारी है 6. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी 7. राज्य रेशम उत्पादन विभागों के बीज, कोसापूर्व व कोसोत्तर क्षेत्रों की देख-भाग करने वाले एक-एक प्रतिनिधि 8. परियोजना क्षेत्र के जिला रेशम उत्पादन अधिकारी 9. राज्य के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड से नोडल अधिकारी 10. संबंधित राज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी - सदस्य संयोजक	1. वित्त पोषक अन्य एजेंसियों और वार्षिक कार्य योजना से अभिसरण के साथ परियोजनाओं का निर्माण। 2. जिला/मंडल/क्षेत्र स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ निकट सहयोग से जमीनी स्तर पर सिल्क समग्र-2 घटकों के कार्यान्वयन पर प्रगति की निगरानी/अनुश्रवण करना। 3. डीबीटी-सर्विसप्लस पोर्टल में निधि जारी करने और लाभार्थी के विवरण को अपडेट करने के लिए जीएफआर के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र और केन्द्रीय रेशम बोर्ड को प्रगति रिपोर्ट जमा करना सुनिश्चित करना। 4. आधार संख्या और अन्य विवरण के साथ लाभार्थी सूची को अंतिम रूप देना। 5. सिल्क समग्र -2 घटकों में शामिल अन्य मामलों के लिए खरीद प्रस्तावों की जांच और सिफारिश करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड और राज्य प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए राज्य रेशम निदेशालयों की अध्यक्षता में उप-समिति का गठन करना। 6. लक्ष्य के प्रति तिमाही आधार पर द्विप्रज और रेशम की अन्य किस्मों के उत्पादन की निगरानी करना और कमी की स्थिति में पहल करने हेतु सुझाव देना। 7. निर्धारित रूप रेखा को ध्यान में रखते हुए अधिकतम लाभ के लिए पहले की अवधि में रेशम उत्पादन के लिए बनाए गए बुनियादी ढांचे के उपयोग पर प्रगति की समीक्षा करना। 8. उत्पादन और उत्पादकता में सुधार की समीक्षा करना। 9. विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत लाभार्थियों के कवरेज पर चर्चा करना। 10. रेशम उत्पादन विकास (वित्तीय और भौतिक) के लिए कार्यान्वित अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा और केन्द्रीय रेशम बोर्ड को प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति सुनिश्चित करना। 11. एएएमसी और अन्य समीक्षा बैठकों के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई। 12. योजना दिशा-निर्देशों के समग्र ढांचे के भीतर एक घटक से दूसरे घटक में निधि के पुनर्विनियोजन पर औचित्य सहित विचार करना। 13. तिमाही आधार पर राज्य प्रोफाइल का अपडेशन और परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग की समीक्षा करना। 14. सिल्क समग्र-2/अन्य योजना के तहत सहयोग/समर्थन पर जिलेवार डेटाबेस का रखरखाव और समीक्षा। 15. रेशम उत्पादन विकास से संबंधित मुद्दों/बाधाओं को सूचीबद्ध करना और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना। 16. समवर्ती मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करना। 17. अन्य मामले जो सिल्क समग्र -2 के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण हों। 18. समिति की बैठक तिमाही में एक बार भौतिक या वर्चुअल रूप में होगी। 19. जरूरत पड़ने पर पीएमसी किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकती है या अन्य उप-समितियां बना सकती है। 20. समिति का कार्यकाल 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि अर्थात 2021-2026 के लिए है।

अनुबंध-IV

शीर्ष अनुमोदन और अनुश्रवण समिति (केन्द्रीय रेशम बोर्ड सचिवालय स्तर)

घटक	संदर्भ के मद
अध्यक्ष 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड **सदस्य** 2. राज्यों के रेशम उत्पादन विभाग जिनकी परियोजनाओं को कार्यसूची में रखा गया है 3. निदेशक (वित्त), केन्द्रीय रेशम बोर्ड 4. निदेशक (तकनीकी), केन्द्रीय रेशम बोर्ड 5. निदेशक, राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड 6. निदेशक, केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड 7. वैज्ञानिक-डी (पीसीटी), केन्द्रीय रेशम बोर्ड 8. प्रभारी, सिल्क समग्र योजना/ तकनीकी अनुभाग, केन्द्रीय रेशम बोर्ड - सदस्य संयोजक **स्थायी आमंत्रित** 9. केन्द्रीय रेशम बोर्ड सचिवालय से राज्यों के लिए नोडल अधिकारी 10. वैज्ञानिक-डी, सांख्यिकी, केन्द्रीय रेशम बोर्ड सचिवालय	1. राज्यों के पीएमसी द्वारा अनुशंसित सिल्क समग्र -2 की परियोजनाओं जिनकी विधिवत जाँच एवं मूल्यांकन केन्द्रीय रेशम बोर्ड मुख्यालय की इन-हाउस समिति द्वारा की जाती है, पर विचार करना। 2. 5 वर्ष की अवधि के लिए सामान्य, एससीएसपी, टीएसपी और उत्तर पूर्व शीर्षों के तहत उपलब्ध निधियों के समग्र आवंटन के आधार पर परियोजनाओं को मंजूरी देना। 3. परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना। 4. लक्ष्य के सापेक्ष बीज उत्पादन, वृक्षारोपण विकास और कच्चे रेशम उत्पादन (द्विप्रज और रेशम की अन्य किस्में की प्रगति की समीक्षा करना। 5. 5 वर्षों (2021-22 से 2025-26) में सिल्क समग्र-2 योजना के कार्यान्वयन की निगरानी/अनुक्षवण करना। 6. जियो-टैगिंग के अलावा सिल्क समग्र-2 कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा के लिए एक एमआईएस स्थापित करना। 7. सिल्क समग्र-2 योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में सभी मामलों पर पीएमसी/राज्यों को समय-समय पर दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करना। 8. राज्यों से प्राप्त वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा करना और 2023-24 के दौरान मध्यावधि मूल्यांकन आयोजित करना और उसके बाद 2025-26 के दौरान अंतिम मूल्यांकन करना। 9. सिल्क समग्र-2 घटकों के कार्यान्वयन की समीक्षा/अनुक्षवण करने और प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी। 10. समिति किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकती है या आवश्यक समझे जाने पर उप-समितियां बना सकती है और आवश्यकता के अनुसार राज्यों के अधिकारियों को एएएमसी में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है। 11. समिति का कार्यकाल 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि अर्थात् 2021-2026 के लिए है।

अनुबंध-V

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की रेशम समग्र-2 योजना के तहत परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र (टेम्पलेट)

1. परियोजना का शीर्षक
2. कार्यान्वयन एजेंसी का विवरण
3. परियोजना का कार्यकारी सारांश
1. परियोजना का अपेक्षित परिणाम (उत्पादन/रोजगार/आय वृद्धि/बाजार में पैठ/पहुँच के संदर्भ में मापने/परखने योग्य। (संकेतकों की सूची अनुलग्नक II में दी गई है)
2. आधारभूत डेटा
3. आधारभूत डेटा का स्रोत
4. परियोजना का उत्पादन भौतिक प्रदेय
5. परियोजनाओं में प्रस्तावित इनपुट
6. इनपुट की घटक-वार लागत
7. कार्यान्वयन रणनीति
8. लाभार्थी के मामले में आधार संख्या/आधारभूत संरचना के मामले में जियो-टैगिंग का व्यवस्था करना
9. अभिसरण ढांचा (राज्य/संघ सरकार की अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण)
10. क्या सभी आवश्यक सांविधिक प्रशासनिक मंजूरी उपलब्ध हैं?
11. अनुश्रवण तंत्र
12. क्या परियोजना के लिए आवश्यक भूमि और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्या ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी?
13. क्या कार्यान्वयन के सेन्ट्रल सेक्टर के पैटर्न का पालन करने का प्रस्ताव है? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार, परियोजना की 10% लागत वहन करने को तैयार है?
14. एक नज़र में परियोजना के साथ अनुबंध, वर्ष-वार चरणबद्धता, इकाई लागत विवरण, आउटपुट और परिणाम।
15. प्रस्तावित परियोजना की विशिष्ट अन्य सहायक जानकारी

हस्ताक्षर _____
(अधिकारी का नाम और पदनाम)
कार्यालय मुहर के साथ
स्थान:
दिनांक:

अनुबंध-VI

अनुशंसित परिणाम संकेतक

1. बेसलाइन से उत्पादन % की वृद्धि
2. प्रति 100 रोमुच कोसा के उत्पादन में % की वृद्धि
3. 1 एकड़ से कोसा के उत्पादन में % की वृद्धि
4. रेशम उत्पादन में 1 एकड़ से % की वृद्धि
5. श्रम दिवस प्रति एकड़/वर्ष के संदर्भ में रोजगार
6. परियोजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी
7. परियोजना के अंतर्गत सृजित रोजगार
8. अप्रत्यक्ष रोजगार
9. आय में वृद्धि (पारिवारिक आय में % की वृद्धि)
10. बाजार में पैठ/पहुँच - मेलों की संख्या में भागीदारी (घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय)
11. अंतरफसल और उप-उत्पाद उपयोग के माध्यम से प्रति एकड़/वर्ष आय सृजन
12. डीपीआर की प्रकृति के आधार पर परियोजना से संबंधित अन्य संकेतक

अनुबंध-VII

जीएफआर 12 - सी

[(नियम 239 देखें)]

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रपत्र (राज्य सरकारों के लिए)

(जहां केवल सरकारी निकायों द्वारा व्यय किया जाता है)

क्रमांक	पत्र संख्या और तारीख	राशि	प्रमाणित किया जाता है कि हाशिए पर उल्लिखित मंत्रालय/विभाग के पत्रांक के अंतर्गत वर्ष .....के दौरान.....रु. में से रु. .....का अनुदान ..... संस्वीकृत किया गया है एवं विगत वर्ष व्यय नहीं हुई राशि का.....मद में उपयोग किया गया है जिसके लिए मंजूरी दी गई थी एवं शेष उपयोग नहीं की गई राशि वर्ष के अंत (सं. ..... दिनांक.....) द्वारा सरकार को वापस कर दी गई है /अगले वर्ष भुगतेय अनुदान के मद में समायोजित की जाएगी ।
	कुल		

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, वे पूरी हो गई हैं/पूरी हो रही हैं और मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जांचों का प्रयोग किया है कि धन वास्तव में उस प्रस्ताव के लिए उपयोग किया गया था जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी।

3. भौतिक उपलब्धि का सार:

क्रम सं	कार्यान्वित लाभार्थी उन्मुखी घटकों का विवरण	स्वीकृत इकाई की स्थिति		कवर किए गए लाभार्थी की स्थिति	
		स्वीकृत इकाई की संख्या	पूर्ण इकाई की संख्या	कवर किए गए लाभार्थी की संख्या	शेष जिसे पूरा किया जाना है ।
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

प्रयुक्त जाँच की विधि/प्रकार

1.
2.
3.
4.
5.

हस्ताक्षर .....

पद .....

दिनांक .....

अनुलेख: उपयोगिता प्रमाण-पत्र में किए गए वास्तविक व्यय, ऋण एवं भंडार तथा परिसंपतियाँ के आपूर्तिकर्ताओं एवं निर्माण एजेंसियों को दिए गए अग्रिमों के विवरण का अलग-अलग उल्लेख होगा जो योजना के दिशा-निर्देश के अनुरूप योजना के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करेगा जो कार्य की अवस्था के व्यय को नहीं बढ़ाते हैं । इन्हें उपयोग किए गए अनुदान के रूप में माना जाएगा परंतु उन्हें इसे आगे ले जाने की अनुमति होगी ।

अनुबंध-VIII

परियोजना निर्माण और मूल्यांकन के लिए जाँच सूची

#	जांच सूची	अनुपालन
क	**परियोजना निर्माण और मूल्यांकन चरण**	
1	राज्य पीआईएमसी की सिफारिश के साथ अवधारणा पत्र प्रस्तुत करना	
2	डीपीआर तैयार करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड से राज्य/एजेंसी की सहमति	
3	केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एएएमसी के अनुमोदन के आधार पर, डीपीआर निम्नलिखित विवरणों के साथ प्रस्तुत किया जाना है: क) क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय कार्यालय से डीपीआर का मूल्यांकन नोट ख) राज्य पीएमसी की टिप्पणियों के साथ सिफारिश ग) राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी से परियोजना पर पीपीटी घ) नैदानिक अध्ययन/आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट डीपीआर के साथ संलग्न है ङ) डीपीआर टेम्पलेट के अनुसार तैयार की गई परियोजना	
4	केन्द्रीय रेशम बोर्ड मुख्यालय में परियोजना विश्लेषण और डीपीआर पर विचार के लिए एएएमसी के समक्ष प्रस्तुत करना	
5	राज्य/एजेंसी द्वारा संक्षिप्त प्रस्तुति	
6	राज्य/एजेंसी को एएएमसी के अनुमोदन/निर्णय का संप्रेषण	
ख	**पहली किस्त जारी करने की शर्तें**	
1	निधि जारी करने के लिए राज्य/एजेंसी से विवरण के साथ पत्र	
2	परियोजना स्तर और राज्य स्तरीय समितियों का गठन	
3	वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों के लिए कार्य योजना	
4	परियोजना अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए माइल स्टोन के साथ-साथ घटक-वार गतिविधियों के लिए समय सीमा	
5	द्वितीय किश्त से पूर्व जमा करने हेतु लाभार्थियों/उपक्रमों की सूची	
6	जमीनी स्तर पर तैयारी पर रिपोर्ट और परियोजना को लागू करने के लिए पहले ही शुरू किए गए कार्य	
7	परियोजना के लिए आवश्यक सड़क और ट्रंक अवसंरचना की सुविधा/उपलब्ध कराने की व्यवस्था	
8	जहां भी आवश्यक हो, राज्य के हिस्से के मिलान का प्रावधान	
9	मिलान लाभार्थी शेयर को जुटाना	
10	परियोजना को स्वीकृत अवधि के दौरान पूरा किया जाएगा	
11	वेब आधारित एमआईएस विकास की स्थिति	
12	निधि जारी करने के लिए पीएफएमएस/ईएटी मॉड्यूल स्थापित करना	
13	डीबीटी की व्यवस्था और मासिक अनुपालन की प्रतिबद्धता	
14	परियोजना प्रबंधक/समन्वयक की नियुक्ति	

#	जांच सूची	अनुपालन
15	लाभार्थियों द्वारा बैंक खाते की व्यवस्था/स्थिति	
16	राज्य सरकार की वचनबद्धता कि उनके पास वृक्षारोपण और निर्माण कार्य के लिए आवश्यक वैधानिक और कानूनी मंजूरी है	
17	परियोजना क्षेत्र में रेशम उत्पादन के लिए लागू राज्य/अन्य मंत्रालयों की योजनाएं, यदि कोई हों	
18	लाभार्थियों के बीच आधार नामांकन की स्थिति और सभी लाभार्थियों को आधार कब तक प्रदान किया जाएगा	
ग	**दूसरी किस्त जारी**	
1	जीएफआर शर्तों को पूरा करते हुए दूसरी किस्त के लिए राज्य का पत्र	
2	परियोजना के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का दस्तावेज व्यक्तिगत लाभार्थियों के नाम पर होगा	
3	कम से कम 5 वर्षों की अवधि के लिए रेशम उत्पादन गतिविधि जारी रखने के लिए लाभार्थियों के साथ समझौता किया गया और बनाई गई संपत्ति का विशेष स्वामित्व भारत सरकार से वित्त पोषण की सीमा तक भारत सरकार के नाम पर होगा।	
4	वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट केन्द्रीय रेशम बोर्ड इकाई/राज्य द्वारा 70% या अधिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र के समर्थन के साथ प्रतिहस्ताक्षरित	
5	क्षेत्र प्रगति की सहायक तस्वीरों के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड/राज्य द्वारा संयुक्त क्षेत्रीय दौरा रिपोर्ट	
6	पीएफएमएस/ईएटी मॉड्यूल और डीबीटी का अनुपालन	
7	वेब आधारित एमआईएस का विकास और जारी की गई निधियों/भौतिक लक्ष्यों की तुलना में डीपीआर से डेटा अपलोड करना - उपलब्धि	
8	वृक्षारोपण/परिसंपत्तियों के लिए की गई जियो-टैगिंग गतिविधियां	
9	द्वितीय किश्त से सहायता प्राप्त लाभर्थियों की सूची	
10	पहली किश्त में जारी की गई राशि के अनुपात में राज्य के हिस्से का मिलान	
11	दूसरी किश्त के लिए राज्य के हिस्से के मिलान की व्यवस्था	
12	परियोजना के तहत मशीनरी/उपकरण आपूर्ति के संबंध में लाभार्थी हिस्से के लिए की गई व्यवस्था	
13	दूसरी किस्त निधि के उपयोग के लिए माइल स्टोन के साथ-साथ घटक-वार गतिविधियों के लिए समय सीमा	
14	डीबीटी के रूप में प्रशिक्षुओं को उनके खाते में जमा की गई वृत्तिका	
15	प्रासंगिक जीएफआर प्रावधानों के अनुसार की गई परियोजनाओं के लिए निर्माण कार्य/ उपकरणों और सेवाओं की खरीद	
16	परियोजना कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा के लिए परियोजना स्तरीय समिति द्वारा आयोजित बैठकें	

#	जांच सूची	अनुपालन
17	जारी की गई राशि का उपयोग योजना दिशा-निर्देशों, अन्य प्रासंगिक नियमों और शर्तों और इस मामले पर सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है	
18	राज्य सरकार/लाभार्थी ने इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी/गैर-सरकारी संगठन से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है	
19	जारी की गई निधि उसी उद्देश्य के लिए खर्च की जाती है जिसके लिए इसे स्वीकृत की गई है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निधि का विचलन नहीं है	
20	अंतिम चरण/उपगत व्यय के लिए निधि जारी समयसीमा और माईल स्टोन अनुसार हो	
घ	**तीसरी किस्त जारी (अंतिम)**	
1	पिछली किश्त जारी करते समय निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए अंतिम किस्त के लिए राज्य का पत्र	
2	पहली किस्त के लिए 100% उपयोगिता प्रमाण-पत्र और दूसरी किस्त के लिए 70% या अधिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र के समर्थन के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड इकाई/राज्य द्वारा भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित	
3	क्षेत्र प्रगति की सहायक तस्वीरों के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड/राज्य द्वारा संयुक्त क्षेत्रीय दौरा रिपोर्ट	
4	परियोजना के समवर्ती/मध्यावधि मूल्यांकन के लिए कार्रवाई शुरू	
5	दूसरी किस्त जारी करने के लिए उल्लिखित अन्य सभी शर्तें तीसरी और अंतिम किस्त जारी करने के लिए भी लागू हैं	

*****

CONTENTS

#	Topics	Page
I	**BACKGROUND**	
i	Core activities of Central Silk Board – Sub-components	1
ii	Beneficiary-oriented Critical Field level intervention – Sub-components	1
II	**GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF CORE ACTIVITIES OF CENTRAL SILK BOARD**	
A	**Core activities**	2
B	**General guidelines for implementation of core activities - Programme formulation and sanction**	
i	Research & Development, Training, Transfer of Technology and I.T. initiatives	4
ii	Seed Organizations	5
iii	Coordination and Market Development	6
iv	Quality Certification Systems (QCS)/Export, Brand Promotion and Technology Up-gradation	6
C	**Specific guidelines for implementation & monitoring of core activities**	7
D	**Fund release and utilization**	8
III	**GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF BENEFICIARY-ORIENTED-COMPONENTS**	
A	**Components available for assistance**	9
B	**Implementing agencies**	10
C	**Scope of fund support and budgetary allocation**	
i	Support to State Sericulture Departments/Line Departments	10
ii	Project based support to North Eastern States	11
iii	Funding to ongoing Sericulture Project under erstwhile NERTPS	11
iv.	Allocation of fund	11
D	**Submission of proposal by States**	12
E	**Mechanism for project appraisal/approval**	15
F	**Fund release**	16
G	**Submission of Utilization Certificate**	16
H	**Specific guidelines for implementation of beneficiary-oriented critical interventions by the State**	17
I	**Funding pattern for beneficiary-oriented Silk Samagra-2 packages/components**	18
J	**Monitoring and evaluation**	19
K	**Silk Samagra-2 Helpline**	21

Standard Operating Procedure (SOP) and Guidelines for implementation of Central Sector Scheme "Silk Samagra-2" – An Integrated Scheme for Development of Silk Industry (ISDSI) during 5 years from 2021-22 to 2025-26 (15th Finance Commission Cycle)

I. BACKGROUND

The Central Silk Board (CSB) is a Statutory Body, established by an Act of Parliament (Act No.LXI of 1948). The core activities of Central Silk Board are Research and Development; maintenance of four-tier silkworm seed production network; leadership role in commercial silkworm seed production; standardizing and instilling quality parameters in various production processes and advising the Government on all matters concerning sericulture and silk industry. These activities are carried out by network of units spread across the country, through the Central Sector Scheme *viz.*, "**Silk Samagra-2**", an integrated scheme for development of silk industry, which has been approved by the Cabinet Committee of Economic Affairs on 19.01.2022. The Silk Samagra-2 scheme consists of various components and sub-components under Mulberry, Vanya and Post-cocoon Sectors. The programme synergises the efforts of State Governments and other implementing agencies to improve the quality, productivity and production of raw silk, besides generating employment opportunities, particularly in the rural areas.

The Silk Samagra-2 scheme comprises of two major activities as under:

i. **Core activities of Central Silk Board – Sub-components**
   - a. R&D, Training, Transfer of Technology and I.T. initiatives
   - b. Seed Organization
   - c. Coordination and Market Development
   - d. Quality Certification Systems, Export, Brand Promotion & Technology upgradation

ii. **Beneficiary-oriented Critical Field level intervention – Sub-components**
   - a. Critical Field Level Interventions other than North Eastern Region
   - b. Implementation of Sericulture Projects in North Eastern Region
   - c. Provisions to meet expenditure of ongoing Sericulture Projects of NERTPS

While the core activities of Central Silk Board with four sub-components are implemented through a network of CSB units in the areas of R&D, seed production, project implementation & monitoring and brand promotion of silk in Indian and outside markets, the beneficiary-oriented components shall be implemented by the State Sericulture Departments/other State Departments with the fund support from Central Silk Board under Silk Samagra-2 scheme.

II GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF CORE ACTIVITIES OF CENTRAL SILK BOARD

A. Core activities

i. Research & Development, Training, Transfer of Technology and I.T. initiatives

To carry out the research activities, three main research and training institutes for mulberry sericulture (CSRTI) are established at Mysuru (Karnataka), Berhampore (West Bengal) and Pampore (J&K); one institute for tasar (CTRTI) at Ranchi (Jharkhand), and CMERTI at Lahdoigarh (Assam) for muga & eri, and an exclusive technological research institute (CSTRI) for addressing post-cocoon issues is established at Bengaluru (Karnataka).

A Silkworm Seed Technology Laboratory (SSTL) at Bengaluru and a Central Sericultural Germplasm Resources Centre (CSGRC) is established at Hosur (Tamilnadu) for focused attention on seed and preserving/maintaining mulberry and silkworm genetic materials, respectively. Besides, a Seri-Biotechnological Research Laboratory (SBRL) is functioning at Bengaluru. The Regional Sericulture Research Stations (RSRSs) and Research Extension Centers (RECs) are attached with the above research institutes in pre and post-cocoon sectors.

The thrust areas in mulberry and vanya silk sectors for undertaking R&D activities during the Silk Samgara-2 scheme by the R&D institutes include host plant and silkworm breed improvement for higher production, productivity and quality & resilience to biotic and abiotic stresses; adoption of molecular tools for breed/hybrid improvement & disease diagnosis; improved seed technology & germplasm conservation; mechanization of sericulture activities for drudgery reduction and efficiency improvement; establishing machine manufacturing set-up for post-cocoon sector & improved silk processing machineries/technology; commercial utilization of silk for non-textile purposes; and silk biomaterial research.

The research institutes also conduct specialized training in various aspects of sericulture to generate skilled manpower required for the industry. Transfer of improved technologies in mulberry and non-mulberry sericulture would be evaluated and implemented in coordination with DoSs.

IT services are used for silk commodity price communication system on daily basis, networking and knowledge management, data warehousing & dissemination through SILKS (Sericulture Information Linked Knowledge System) portals. Computerization of CSB units, Geo tagging of assets created, Centralised monitoring system etc., are also undertaken using IT application.

ii. Seed Organizations

a. Ensure availability of quality silkworm seed in adequate quantities with the support of DOSs and private partners for achieving the targeted silk production and act to improve the productivity parameters.

b. Maintain four-tier seed multiplication network for production & supply of nucleus and basic silkworm seed.

c. Leadership role in bivoltine commercial seed production.

d. Facilitate State units and private silkworm seed producers to enhance their capacity for quality silkworm seed production.

e. Conduct quality certification to own units and facilitate the same for State and Private units by implementing Silkworm Seed Act.

f. Support to Adopted Seed Rearers (ASRs) for up-scaling the seed production.

g. Seed technology research, disease control, cold storage technology, seed preservation etc.

iii. Coordination and Market Development

a. Liaison and coordination with State Departments for implementing and monitoring of sericulture development programmes.

b. Coordination with various associated Ministries/Line Departments of State government for dovetailing assistance from schemes/components to ensure effective synergies and pooling of resources for sericulture development.

c. Product Design, Development & Diversification (P3D) with special focus on fabric engineering, silk blends, designing new fabric structures, design and development of new products in silk and silk blends.

d. Support for market linkages/strengthening of market infrastructure for providing fair and transparent marketing of cocoon and raw silk in the country.

e. Price stabilization support for non-mulberry cocoons to safeguard the interest of tribal communities.

iv. Quality Certification Systems (QCS), Export, Brand Promotion and Technology Up-gradation

a. Measures towards strengthening quality assurance, quality assessment and quality certification.

b. Brand and generic promotion of Indian Silk in the domestic market, promotion of Brand India Silk in the export market.

c. Technology up-gradation for improving the quality, processing and finishing of Indian Silk to boost export.

d. Cocoon and raw silk testing to ensure quality and purity of silk.

e. Promotion of pure silk products by popularising “Silk Mark”, for purity of silk products through the Silk Mark Organisation of India (SMOI).

B. General guidelines for implementation of core activities – Programme formulation and sanction

(i) Research & Development, Training, Transfer of Technology and I.T. initiatives

1. R&D institutes of CSB shall carry out need based focused research in mulberry, eri, muga and tasar sericulture and develop technologies (both pre & post-cocoon sectors) to become *Atmanirbhar* in production of import-substitute international grade bivoltine silk and indigenous machine manufacturing etc.
2. Central Silk Board shall take up collaborative projects with various institutes/research labs for Product Design, Development & Diversification (P3D) with special focus on fabric engineering, silk blends etc. Annual Action Plan shall be prepared for the same.
3. Research projects shall have time line for their completion and transfer of such technologies to the field to ensure that the benefits reach the last mile.
4. Action Plan for 5 years have to be submitted to CSB and budget will be allotted based on Annual Action Plan.
5. Annual Action Plan shall include R&D collaboration with the existing network of ICAR, the Agricultural Universities and other research organizations of national and international repute.
6. Each of the main research institutes would have their own Research Advisory Committee (RAC)/Research Council (RC) for review and monitoring of R&D activities.
7. National level Research Coordination Committee (RCC) would review, evaluate and approve the research projects in line with the objectives/logical framework for output/outcome monitoring as per Silk Samagra-2.
8. A Research Management & Technology Dissemination Manual shall be prepared for all research projects/proposals to be implemented providing detailed procedures for project conceptualization, screening and monitoring.
9. Hybrid Authorization Committee and Mulberry Authorization Committee would recommend release of new mulberry varieties and silkworm breeds to the field as per Silk Samagra-2 target.
10. Research projects performance shall be evaluated on quarterly basis in terms of Logical Framework documents as suggested by the NITI Aayog while considering the EFC proposal for Silk Samagra-2.
11. Performance audit system of ICAR & CSIR institutes shall be integrated into CSB's R&D system.
12. Mobile app/portal for Sericulture Advisory Services to farmers, SMS service for cocoon and silk rates to the farmers and reelers shall be developed as a part of R&D, IT Initiatives.

13. Digitization and computerization of CSB units for data warehousing and dissemination through portals, application of Remote Sensing and GIS for promoting sericulture through SILKS Portal.
14. Geo-tagging of sericulture assets created under various projects shall be ensured by using GPS based mobile App 'SILK'.
15. Central Silk Board shall communicate state-wise & year-wise targets for plantation development, silkworm seed, cocoons, raw silk production and other parameters as per Silk Samagra-2 to States and seek their consent.
16. MIS to be integrated under one platform and develop robust system for monitoring of scheme benefits/outcome and its delivery mechanism and regular updation of Farmers' & Reelers' Database.
17. National level digital Seri Database of all sericulture stakeholders/silk production shall be maintained.
18. All database and norms to be made available in public domain to facilitate monitoring at every level including Ministry & NITI Aayog.
19. Implementation of Digital India Programme to reduce compliance burden on citizen, Software Development (E-Office, HRMS, ERP and other MIS) and their maintenance, purchase/upgradation of software etc., shall be ensured.
20. Social media platforms shall be used for promoting and popularizing sericulture activities and technologies.

(ii) Seed Organizations

1. The Seed Organizations for mulberry, tasar, eri and muga shall have separate Seed Action Plan Committees to assess, produce and supply the entire seed requirements of the country through CSB, State and Registered Seed Producers (RSPs) units.
2. The Seed Organizations of CSB shall focus on elite and nucleus seed production of improved bivoltine breeds, and Vanya silkworm seed, oversee and ensure maintenance of four-tier silkworm seed production network.
3. Promote entrepreneurs for seed production and installation of cold storage units for commercial use under bivoltine mulberry sector.
4. Mobile app for real time availability of silkworm seed, cost of seed and producers details shall be developed to provide a common platform for silkworm seed producers and farmers/DOSs.
5. Seed Organizations shall support State Governments and RSPs for production of quality bivoltine basic and commercial silkworm seed in mulberry and vanya silk sectors.
6. State shall give priority to bivoltine commercial silkworm seed production activities with

support of private partners to reduce dependency on CSB for commercial seed requirement of the State.

7. Action plan shall be prepared and implemented for transfer of bivoltine and Vanya commercial silkworm seed production to private sector.
8. The Seed Organizations of CSB shall explore the possibility for export of silkworm seed to other sericulture/silk producing countries and also prepare a roadmap for foreign exchange earnings through silkworm seed export.
9. Monitor the seed production process at CSB, State and private sector.

(iii) Coordination and Market Development

1. Central Silk Board shall extend support to State Government for market linkages/strengthening of market infrastructure to promote fair and transparent marketing of cocoon and raw silk in the country.
2. Explore counterpart funding for sericulture sector through convergence with line Central Ministries/Line Department of State government for dovetailing assistance from schemes/components to ensure effective synergies and pooling of resources for sericulture development.
3. Explore collaboration with international funding agencies to achieve Sustainable Development Goal and livelihood creation and brand promotion of pure silk products in domestic and international markets.
4. Ensure price stabilization support in vanya sector for the benefit of tribal communities. A Price Fixation Committee shall be constituted separately for tasar, eri and muga.

(iv) Quality Certification Systems (QCS), Export, Brand Promotion and Technology Up-gradation

1. Complete outsourcing of activities of SMOI shall be ensured by using mobile app and online/digitization of SMOI activities.
2. For outsourcing of activities under QCS, annual action plan to be submitted by SMOI with yearly strategy and milestones.
3. Action Plan for marketing strategies for promotion of the Silk Mark Label, consumer awareness, and creating brand image for Indian Silk across the globe shall be prepared by SMOI.
4. SMOI shall conduct market study on silk products, demand and supply, consumer preferences and global opportunity for Indian silk products.
5. SMOI shall prepare Annual Action Plan to seek fund support under Silk Samagra-2 scheme and submit proposal duly approved by its Committee of Administration to CSB for the following activities:

a. Providing performance based incentive to registered Authorized Users of Silk Mark for increasing the consumption of Silk Mark Label to popularize sale of pure silk products.

b. Providing assistance to the primary producers of pure silk items for brand & generic promotion of Silk. States/Government agencies in various States shall be assisted for installation of cocoon & raw silk testing equipment for quality assurance of silk.

C. Specific guidelines for implementation & monitoring of core activities

1. Auditing of the accounts would be undertaken by the Offices of the CAG, Govt. of India, at CSB Headquarters and Institutions.
2. Annual Action Plan meeting will be held during April and decisions of Action Plan meeting will be communicated along with administrative approval to all concerned for submission of detailed proposals.
3. The Action Plan *inter alia* shall contain quarterly financial and physical targets of all the components and activities of the scheme.
4. As per Annual Action Plan and administrative approval, the Institutes/CSB units shall send proposals before end of 2nd quarter, with all formalities.
5. Annual Action Plan for the Seed Sector shall also include the components for State sector and RSPs, besides CSB's own infrastructure strengthening.
6. Proposals, seeking clarifications, according approval, implementation progress etc., shall be monitored by a single window system both in respect of purchase/stores and construction/maintenance.
7. Monthly financial and physical progress reports on implementation of various components under the schemes will be furnished to CSB by the concerned units.
8. In-house evaluation on implementation of various programmes under all the Central Sector schemes shall be carried out by CSB.
9. Road map for modernization and upgrading the CSB's R&D Institutes to match with international standard of R&D Labs shall be prepared and implemented.
10. New technologies/innovations developed by CSB's R&D Institutes during the Silk Samagra-2 period shall be transferred to the field through beneficiary-oriented components.
11. A committee constituted by CSB shall work out the unit cost for the commercialization of a technology/innovation. The committee shall also include members from the industry.
12. The components/items relating to administrative expenses or involving any creation of posts shall not be increased. Normal financial/budgeting re-appropriation rules shall be followed.

13. Out of additional vacancy of 1442 arising due to retirement across various cadres of the employees of CSB during the scheme period, 395 posts will not be filled including 30 scientists and 10 administrative officers at Group-A level.
14. Annual Plan for hiring of qualified persons, expert services, JRF/SRF etc., shall be prepared to meet the manpower requirement in R&D projects/Silk Samagra-2 scheme implementation/CSB's administration through engagement of performance oriented manpower.

D. Fund release and utilization

1. Funds shall be released by the Ministry to CSB as per approved annual budget and provisions under Silk Samagra-2 and further released to the delegated units through PFMS as per approved Budget/Action Plan of the unit.
2. Financial sanctions, accounting and expenditures shall be as per the extant rules of CSB and regulated as per GFR provisions.
3. Inter-component flexibility is permitted without compromising the overall targets and objectives of Annual Action Plan, subject to fund availability.
4. The provision in the EFC for various components/sub-components of the scheme is only indicative and Ministry of Textiles/Central Silk Board may decide need based inter-component changes.
5. Year-wise provision indicated in the EFC is only indicative and expenditure in excess of EFC provision for any year can be incurred, subject to budget provision.
6. UCs shall be submitted as per **GFR 12-A** as provided at **Annexure-I.**

III GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF BENEFICIARY-ORIENTED COMPONENTS

A. Components available for assistance

In addition to core activities directly implemented by CSB, certain beneficiary-oriented critical interventions required in the field for the promotion of sericulture will be implemented during the Silk Samagra-2 scheme period**.** These interventions are important tools for transfer and adoption of improved technology packages developed by the Research Institutes of CSB**.** The beneficiary-oriented interventions cover the major areas in pre and post-cocoon sector *viz.,* development and expansion of host plant, support for silkworm rearing, strengthening and creation of silkworm seed production infrastructure, development of farm and post-cocoon capacities, up-gradation of reeling and processing technologies in silk, and capacity building through skill development and skill upgradation. These components shall be provided to the beneficiaries either in package mode to individual beneficiary or in a project mode.

Apart from some individual components like (i) Capacity Building/Training for skill seeding & skill upgradation for empowering the sericulture stakeholders to enhance their skills & efficiency in silk/sericulture sector; (ii) Support for development of kisan nursery and (iii) Vanya silk reeling machinery, there are nine bundles of packages available for sericulture stakeholders to cater to the need of individual beneficiaries as well as Seri-Business Entrepreneurs/corporate sericulture (farm to fabric-large scale farming).

The bundles of packages are as under:

1. **Package of assistance for silkworm rearing for mulberry & vanya:** The package includes support for improved variety plantation, irrigation, construction of rearing house, supply of rearing appliance & disinfectants (prophylactic measures for better yield) and popularisation of Chawki Rearing Centres for mulberry and vanya.
2. **Support to silkworm seed rearers:** Under this component, support is extended towards strengthening of adopted seed rearers, disinfectants & purchasing Seed Testing Equipments for State and RSPs besides development/maintenance of chawki garden in tasar, eri & muga sectors to produce quality silkworm seed.
3. **Support for small and medium size reeling units:** It provides support for setting up of improved Small & medium mulberry silk reeling units. The package includes all identified and listed equipment.
4. **Support for Automatic Silk Reeling Machinery Package for enterprise:** All machinery parts as indicated in the unit cost shall be in the package and supplied along with the ARM.
5. **Support for establishment of pupae processing units:** It includes a pelade extraction and pupa separation machine. This component can be used for pupa processing and

canning unit for eri sector too, with appropriate modifications suiting to the local requirement.

6. **Support for silk weaving sector:** To support silk weaving sector with advanced technology & gadgets, a package is available to address the issues in silk weaving sector for better productivity, quality of fabrics and reduce the drudgery of the weavers.
7. **Support for silk dyeing and processing:** The technologies proposed under this component are to reduce consumption of water & energy and manpower requirement in silk yarn dyeing & processing sector. Apart from improving the quality of dyeing, it also helps to provide conducive working environment to the workers.
8. **Package of assistance to seri business enterprises:** To scale up the import-substitute bivoltine silk production, support for seri-business entrepreneurs/corporate sericulture (farm to fabric-large scale farming)/Industry participation through up-scaling the reeling activity have been included with rationalised scale of subsidy support.
9. **Support for establishing for effluent treatment plant-zero discharge and ground discharge type:** The package provides support to silk yarn dyeing and silk fabric processing facilities with ETP and encourage pollution-free processing units.

B. Implementing agencies

I. State Sericulture Departments and other Line Departments of State Governments as per extant procedure.

II. State Sericulture Departments may have the discretion to implement the same through Department or identify suitable agency/local bodies as approved by the respective State government in identified specific areas.

III. Any other Line Departments of State Govt. such as Forest/Horticulture/Agriculture/ Rural Development etc., may also propose to implement the components in project mode to facilitate better convergence with their own scheme.

C. Scope of fund support and budgetary allocation

(i) Support to States Sericulture Departments/Line Departments

1. All beneficiary-oriented components proposed under Silk Samagra-2 scheme shall be implemented by the State Sericulture Department/Line Department to support the beneficiary/stakeholders by implementation of projects.
2. Besides, considering the State specific need for promoting growth and employment in sericulture sector and to provide market linkages for silk products, the State Sericulture Departments may also propose for establishment of Common Facility Centres and Centre of Excellence, strengthening of State's sericulture infrastructure *viz.,* silkworm seed grainages, marketing infrastructure and quality certification system for the benefit of stakeholders/sericulturists of the State.
3. Cost of such intervention shall be as per the prevailing SOR of State PWD/CPWD and

State shall be treated as beneficiary so far as the sharing pattern of funding is concerned.

(ii) Project based support to North Eastern States

1. Under Silk Samagra-2, Central Silk Board has proposed to implement the project based sericulture activities in North East providing complete value chain for local production & consumption of silk.
2. It shall include components such as skill seeding and development of the locals and functionaries of implementing agencies, providing support for creating infrastructure, ensure growth, create employment opportunities, and provide market linkages for silk products in domestic and international markets, participation in market promotion activities within and outside the country, for increasing the income of stakeholders.
3. To enable this, establishment of Common Facility Centres, farm mechanization, post-cocoon and post-yarn sectors, marketing infrastructure, and Centre of Excellence etc., as implemented under NERTPS projects may also be proposed as per State specific need, in the new projects.
4. Cost of such intervention shall be as per the prevailing SOR of State PWD/CPWD for NE Region for construction activities and equipments and machineries based on the projects implemented under NERTPS/components approved under Silk Samagra-2.
5. The post-project maintenance of infrastructures created under the project shall be done by the concerned State Departments or the project implementing agency as assigned by the State Department with the approval of the Apex Approval & Monitoring Committee.
6. Depending upon the need-based requirement in the project, necessary linkages shall also be provided under Flexi Fund to the extent of 10% to achieve the desired outcome of the project through innovative interventions, meeting transportation cost of equipment and machineries to project locations, taxes etc.
7. Provision is also earmarked for completion of the Apparel & Garmenting Units in all NE States. Funding pattern and implementation guidelines will be as per approved guidelines of the NERTPS.

(iii) Funding to ongoing sericulture project under erstwhile NERTPS: The leftover activities of the ongoing NERTPS projects under sericulture shall be funded as per approved implementation guidelines of Silk Samagra-2 scheme. There shall not be any separate guidelines for this. However, these projects have to be completed as per approved DPR by 31.03.2023.

(iv) Allocation of fund: Under Silk Samagra-2 scheme, a total provision of Rs.1050.00 crore has been made for next 5 years (2021-22 to 2025-26). Detailed unit-wise break-up of fund provision and unit cost, tentative physical units to be covered are given in **Annexure-II.** North East States shall also be eligible for funds support under this

component. However, there shall be separate allocation of Rs.230.00 crore for North East specific Sericulture Project implementation and Rs.154.85 crore funds to ongoing Sericulture Project/A&GMU under erstwhile NERTPS to complete the project. Fund allocation to States shall depend on the production of raw silk in last 2-3 years, number of sericulturists, performance of fund utilization, size, growth rate and future potential for expansion of sericulture industry.

D. Submission of proposal by States

1. State Sericulture Department/Line Department shall submit the proposal with due approval of the State's Project Monitoring Committee (PMC) chaired by the Director/Commissioner of the Department and members from CSB and State Departments. Details of the constitution of PMC are given at **Annexure-III**.
2. State Department may avail assistance under Silk Samagra-2 both for the individual farmers' basis and in Project mode. However, the implementation shall be strictly in cluster mode only with not less than 50 beneficiaries in each block.
3. A Project Monitoring & Implementation Committee shall be constituted by the State Sericulture Department/Line Department as applicable.
4. Projects submitted by the Line Departments shall also be vetted by the PMC to be constituted by the Line Departments.
5. In case of Line Department, MoU shall be executed between CSB/State Sericulture Department and Implementing Agency or between CSB and Line Department.
6. Funds shall be released directly to the implementing agencies by CSB as per the sharing pattern and after approval by AAMC, an apex committee at CSB HQ under the chairpersonship of the Member Secretary, CSB. Details of the constitution of AAMC are given at **Annexure-IV**.
7. Central Silk Board will sanction and release fund to implementing agencies as per available budget and set procedure for evaluation of proposal.
8. In all cases, the concerned State Department/Line Department may ensure availability of matching share of funds for such components.
9. Tentative approved allocation of funds for the States shall be communicated as per annual budget allocation by the Govt. of India in the month of December to plan for new proposals in time.
10. Project duration can range from 2 to 3 years depending on the nature of the components/project area as per field level requirement.
11. States shall have to prepare detailed proposal(s) for next 5 years (2021-22 to 2025-26) indicating the year-wise & component-wise fund requirement details (GoI:State:Beneficiary), along with year-wise output/outcome.

12. Proposal shall also include funding through convergence with other schemes of the Govt. of India/State Government (Silk Samagra-2, RKVY, MGNREGS, State share and others, if any).
13. The implementing State Department shall refer the project proposal to other Departments for seeking funds to avoid overlapping and duplication in project preparation and availing funds thereof.
14. Project proposal shall clearly indicate the coverage of category of beneficiaries *viz.,* SC, ST & General and fund requirement for each group separately in the project proposal.
15. Beneficiary selection by the State shall be done before submitting the project proposal or before release of fund.
16. Selection of SC/ST beneficiaries shall be made more flexible to extend the area in adjoining cluster/block so as to maximize coverage to meet the requirement of the scheme and fund allocation.
17. Project proposals shall have clear goals, measurable targets, resources and time schedule. Minimum project period should be 2 years.
18. Scheme sharing pattern has been rationalized to focus on small & marginal farmers with higher rate of subsidy and also to support Entrepreneurs/Farmers Producer Organization and Corporate Sector for initiation of activities as well as upscaling the production.
19. State shall furnish a certificate that there is no overlapping or duplication of assistance or beneficiaries from other Ministries/Departments in the proposed project.
20. Accordingly, scheme shall have three broad categories and the proposals may be submitted separately for each category:
    - Small and marginal farmers
    - New entrepreneurs
    - Existing entrepreneurs/beneficiaries to upscale their activities.
21. Forward and backward linkages such as supply of planting materials, silkworm seed, other inputs and marketing support etc., should be ensured while preparing the proposals.
22. Component-wise interventions required under Silk Samagra-2 and also from other Departments through convergence with cost of each component as per approved unit cost, sharing pattern, year-wise output and expected outcome etc., shall be indicated in the project.
23. Funds for nursery development component may be availed through convergence with RKVY- under RKVY-RAFTAAR.
24. Implementing agencies may avail funding from RKVY for creating Common Infrastructure. Likewise, plantation development at farmers' level may be availed through MGNREGS.

25. In post-cocoon sector, the unit/infrastructure proposed to be established should have well defined linkages with production zone of raw material and market to ensure adequate quantity of raw material.
26. Only potential area shall be identified for pre-cocoon sector, as per RS & GIS/SILKS portal for project formulation and consultation with the stakeholders/farmers for implementation of the activity shall be done and the same shall be mentioned in the proposal.
27. Benchmark survey of performance shall be conducted on the existing sericulture block/cluster and referred in the proposal.
28. Following shall be elaborated in the proposal submitted by the States:
    i. Justification for identifying the project area.
    ii. Availability of the beneficiary of which at least 30% are women.
    iii. Database of beneficiary including Aadhaar number, land ownership, existing occupation and income level etc., along with the proposal or subsequently, but before release of funds.
    iv. Detailed Action Plan and synchronised flow chart of activities based upon season and local conditions for timely implementation.
    v. Proposal shall also have details on capacity building and training requirement and arrangement for geo-tagging of the infrastructure.
29. Proposal shall include mapping of existing Infrastructure, indicating the installed capacities and working capacities to enable to plan for fully utilizing the existing facilities and bridging the gaps, if any.
30. As far as possible, State should focus to submit proposal on bivoltine silk production under Silk Samagra-2 so as to achieve the *Atmanirbharta* (self-sustenance) in import-substitute silk production.
31. Assistance available in the form of package of components and also supported by brief write-up on each of the components and unit cost break-up shall be circulated to State Departments for preparation of project/submission of proposal for assistance under Silk Samagra-2 scheme **(Annexure-IX).**
32. Package shall have overall ceiling of the total cost. However, the unit cost of individual components within the package shall be flexible and savings if any, from one component can be utilized for other component where it is exceeding the unit cost as per approved sharing pattern only.
33. Flexibility in the package shall be decided by a Technical Committee constituted by the Central Silk Board, which shall have members from CSB and State. The PMC shall examine the recommendations of the Technical Committee and approve it on merit basis.

34. While implementing the components under Silk Samagra-2, the amount accrued as interest, if any, shall be utilized only for the sericulture development programmes/ additional activities with the approval of PMC.
35. Proposals from any government registered organizations/body/federation/local bodies & including NGOs/SPVs & FPOs shall be submitted through respective State Sericulture Departments only. The proposal shall be examined and approved by State Project Monitoring Committee for recommendation.
36. States desiring to implement any component(s) meant for beneficiaries, in State farms/units of States, may do so by meeting beneficiary share also, in addition to State share.
37. Up to 10% of the project cost may be proposed towards Flexi Fund and 5% towards Information, Education & Communication, Administration & Monitoring. Of this, share from GoI will be in proportion to the total CSB share for project components.
38. Flexi Fund shall be utilized for project implementation to meet the viability gap funding, innovative components (which are developed during the scheme implementation period), establishment of Quality Certification System across silk value chain, formation of Farmer Producer Organisations (FPOs) from the newly proposed farmers' group and cost escalation of equipments/machineries.
39. 2.5% of the total project cost shall be retained by the CSB to meet the expenditure towards verification of infrastructure created & evaluation of the performance of field activities with support from Silk Samagra-2 scheme by an independent government/ external agency. This amount shall be the part of the IEC to be earmarked by the State while formulating the project.

E. Mechanism for project appraisal/approval

i. Project proposal shall be prepared as per template suggested and keeping in view all the required key input/para as indicated in the check list at **Annexure-V.**
ii. All project proposals shall be placed before the State Level Project Monitoring Committee (PMC) for discussion and approval and forwarded to CSB.
iii. The project will be scrutinized by the In-House Appraisal Committee (IAC) in CSB (with members from Technical, Research, Seed, PCT, Finance & Statistical Divisions) that will make recommendations for approval and release by Apex Approval & Monitoring Committee (AAMC) at Board's HQ level.
iv. The proposal approved by the AAMC shall be considered for release of funds for implementation of beneficiary-oriented components.
v. Two committees *viz.,* (i) Apex Approval & Monitoring Committee at CSB Headquarters, and (ii) Project Monitoring Committee at State level shall be constituted to review the progress and monitor implementation of the scheme. Composition and terms of reference for these committees are at **Annexure-III & IV.**

vi. A separate Project Monitoring Committee shall be constituted for the Line Departments in States to take up project with counterpart funding from their resources. However, a member each from State Sericulture Department and CSB shall be included in that committee.

vii. Performance review of the beneficiary-oriented components in terms of output and outcome has been suggested at **Annexure-VI.**

F. Fund release

i. Funds will be released to the concerned States and Line Departments through Single Window Release System in instalments.

ii. CSB shall release GoI share as per the approved unit costs and sharing pattern. After release of funds by CSB, as far as possible, re-appropriation of funds from one component to another may be avoided.

iii. First instalment shall be released to cover the first year targets. Subsequent instalment shall be released based on project implementation, submission of UC and progress reports.

iv. In view of implementation of Treasury Single Account system for GIA release by the Govt. of India, appropriate measures shall be taken to release the fund to the implementing agencies for just in time requirement and as per flow chart of the activity on annual basis.

v. Funds shall be released to the implementing agencies through PFMS and from State to beneficiaries through Aadhaar enabled DBT mode.

vi. In case of NGOs/SHGs being the implementing agency, they shall open an ESCROW Account for the project. CSB and State shall enter into a tripartite MoU with the implementing NGO/SHG for project implementation and post-project maintenance of infrastructure and to continue sericulture.

G. Submission of Utilization Certificate

a. Utilization Certificate shall be submitted in prescribed format *i.e.*, **GFR-12 C** for the funds released to State Governments and countersigned by the Accounts Officer of the concerned Sericulture Department or Line Department of the State. Details are provided at **Annexure-VII.**

b. The Utilization Certificate shall be supported by the list of beneficiaries and physical progress for the amount spent or released to stakeholders in cash (electronic mode through DBT) & kind benefit mode.

c. Statement of component-wise physical and financial progress and beneficiary details shall be updated in “Serviceplus” portal of DBT on monthly basis.

d. The progress report and UCs should be submitted within 12 months from the completion of financial year, in which, funds are released to States.

e. While considering fresh releases, the status of UCs of previous year fund release for the project shall be taken into consideration as per provision under GFR 2017.

H. Specific guidelines for implementation of beneficiary-oriented critical interventions by the State

i. CSB's R&D Institutes shall be consulted before formulating the projects and preparation of strategy and Annual Action Plan.

ii. States may involve NGOs, SPVs, Voluntary Service Organisations, Self Help Groups, Panchayati Raj Institutions (PRIs), in identification of beneficiaries/stakeholders and even to implement the project.

iii. The State Govts. shall facilitate credit facilities from banks/financial institutions wherever applicable.

iv. One beneficiary can avail the assistance upto five acres for plantation development with supporting components included in the scheme package.

v. Farmers to be facilitated to use pull service to obtain market prices of cocoon and raw silk through development of Mobile app.

vi. Majority of the plantation activities, especially in case of Vanya, will be taken up in close coordination with the State Forest Departments, Rural Development Department etc.

vii. States shall encourage Public Private Participation, especially in areas of silkworm seed production & post-cocoon sector.

viii. Maintenance/recurring cost of infrastructure developed with support from Silk Samgra-2 scheme shall be the responsibility of entrepreneurs/stakeholders/States, as the case may be.

ix. Provision made for 'Special Initiatives' under Flexi Fund, to be utilized for those unexpected critical areas/gaps shall be addressed during the implementation, based on the recommendations of PMC/AAMC.

x. Geo-tagging to be done for all the assets to be created at beneficiary level.

xi. Unit cost fixed for the packages/components under the scheme/components are maximum ceiling and if it is less in any State, the central share shall be adjusted accordingly.

xii. To ensure that the stakeholders continue to practice sericulture for the next five years after availing assistance under Silk Samagra-2 scheme. State Department shall develop suitable recourse mechanism through legally valid agreements/MoUs to deal with this.

A. Funding pattern for beneficiary-oriented Silk Samagra-2 packages/components

1. The fund sharing pattern (%) for individual beneficiary-oriented Silk Samagra-2 components other than States in NE region:

Category (Small and Marginal Farmers)	GOI (CSB)	State	Beneficiary
General States	50%	25%	25%
General States – For SCSP & TSP	65%	25%	10%
Special Status States (for General, SCSP & TSP Category)	80%	10%	10%

2. Funding Pattern (%) for Seri Business Enterprise/New Entrepreneurs:

Category (New Entrepreneurs/Startups)	GOI (CSB)	State	Beneficiary
General	30%	20%	50%
SCSP, TSP, Special Status States/NE States	40%	30%	30%
Existing Entrepreneurs			
General	20%	20%	60%
SCSP, TSP, Special Status States/NE States	30%	30%	40%

However, in some exceptional cases, AAMC may relax the condition for State's matching share as per sharing pattern, if the eligible individual beneficiary is ready to meet both the State's share as well as the beneficiary share, and the Central share shall be considered for support. In all such cases, the sharing of Central share of funds shall remain unchanged. However, State Department shall formulate/devise *modus operandi* for implementation of the component and the same shall be physically verifiable.

Category	GOI (CSB)	State	Beneficiary
Group activity/Community based programmes **(Small and Marginal Farmers)**	100%	-	-
Common Facility/State infrastructure	90%	10%	-
Individual Benef. **(Small and Marginal Farmers)**	90%	-	10%

A. Monitoring and Evaluation

1. At CSB level, Apex Approval & Monitoring Committee (AAMC) shall monitor and review the performance of implementing the projects and also examine new proposals from the States for approval and release of funds.
2. Periodical review of ongoing Central Sector scheme implementation shall be done by State PMC.
3. CSB shall also create Monitoring Cell at CSB Headquarter, Bengaluru for monitoring the Central Sector Scheme, maintain data related to project and coordinate with concerned implementing State/agency for data warehousing & smooth flow of information. Respective Regional Offices of Central Silk Board shall liaison between CSB and State.
4. The Monitoring Cell shall assist to conduct the verification & monitoring of beneficiary support/infrastructure created under the Silk Samagra-2 scheme through some government agencies or outsource to external agency.
5. Expenditure for conducting verification of the beneficiary support provided/ infrastructure created under the Silk Samagra-2 scheme shall be met out of 2.5% of the Project Cost retained by CSB.
6. Before verification, DOS shall provide details of the progress and completion report to CSB preferably in the 1st week of April. Verification will be done once in a year, preferably before release of next instalment of funds for the project.
7. Central Silk Board shall design a monitoring format and the same shall be made available to the DOS for submission of information to CSB.
8. Central Silk Board shall also provide online platform *viz.,* mobile app for geo-tagging of all physical infrastructure (immovable assets) by the beneficiary itself. DOS shall coordinate and assist the beneficiary for this purpose.
9. All such database shall be integrated with CSB's SILKS portal and States shall upload the data regularly.

10. Regional Offices/nominated Nodal officers of CSB for respective States shall help the States/Line Departments in formulation of project proposals.
11. The Technical Committee shall undertake regular monitoring of the programme under Silk Samagra-2 scheme at field level on half-yearly basis, involving Group–A/Class-I officer *i.e.,* CSB Scientists and State Field Officers.
12. The Technical Committee shall also examine the new project proposals in line with the suggested check list **(Annexure-VIII)** for submission of proposals and recommend for consideration by the State PMC.
13. Prior to meeting of AAMC, In-House Appraisal Committee at CSB HQ shall review the project proposal and recommend for consideration by AAMC subsequently.
14. Annual joint verification, evaluation and social audit on implementation of the programme shall be conducted at field level by CSB involving field officers of the State.
15. The Mid-Term evaluation of the scheme/components by an external agency will be done at the end of 2023-24 to suggest mid-course correction/modification in the scheme implementation.
16. The final evaluation study on the overall performance of Silk Samagra-2 scheme and recommendation for further continuation of the scheme shall be done at the end of 2025-26 by an external agency.
17. The State level Apex Committee *viz.*, State Level Sericulture Coordination Committee (SLSCC) under the chairpersonship of the Addl. Chief Secretary/Principal Secretary of the concerned State shall review the sericulture development activities in the States. The committee shall also take policy decisions in the matter of sericulture and silk sector in the State. The committee shall meet at least once in a year. Composition of the committee shall be as under:

(I)	Addl. Chief Secretary/Principal Secretary	- Chairperson
(ii)	Secretary of the line Department	- Member
(iii)	Member Secretary, CSB or his representative	- Member
(iv)	Director/Commissioner of Sericulture	- Member
(v)	Director or his representative of CSB's Research Institute/Seed organization	- Member
(vi)	Senior sericulture officer from DOS HQ	- Member
(vii)	Chairman/President of State's Seri Federation	- Member
(viii)	Two stakeholders from pre & post cocoon sector	- Member
(ix)	In charge, Regional Office, CSB	- Member Convener

K. Silk Samagra-2 Helpline

A helpline and exclusive e-mail ID, Face book account & Twitter handles have been created to address the grievances of the stakeholders and to create awareness and sharing of information. These are as follows:

Helpline No.	:	080-26282612
Facebook	:	https://www.facebook.com/central.Silkboard
Twitter	:	http://twitter.com/csbmot/
Website	:	http: //www.csb.gov.in/
E mail Id	:	csbsilksamagra2@gmail.com

****

Annexure-I

GFR 12 – A

[(See Rule 238 (1)]

UTILIZATION CERTIFICATE
FOR AUTONOMOUS BODIES OF THE GRANTEE ORGANIZATION

UTILIZATION CERTIFICATE FOR THE YEAR.....in respect
of recurring/non-recurring
GRANTS-IN-AID/SALARIES/CREATION OF CAPITAL ASSETS

1. Name of the Scheme.....
2. Whether recurring or non-recurring grants.....
3. Grants position at the beginning of the financial year
   (i) Cash in Hand/Bank.....
   (ii) Unadjusted advances.....
   (iii) Total.....
4. Details of grants received, expenditure incurred and closing balances: (Actuals)

Unspent Balances of Grants received years [figure as at Sl. No. 3 (iii)]	Interest earned thereon	Interest deposited back to the Government	Grant received during the year			Total available funds (1+2-3+4)	Expenditure incurred	Closing balances (5-6)
1	2	3	4			5	6	7
			Sanction No.	Date	Amount			
			(i)	(ii)	(iii)			

Component-wise utilization of grants:

Grant-in-aid–General	Grant-in-aid–Salary	Grant-in-aid–creation of capital assets	Total

Details of grants position at the end of the year

(i) Cash in Hand/Bank……

(ii) Unadjusted Advances……..

(iii) Total……

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which grants were sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned:

(i) The main accounts and other subsidiary accounts and registers (including assets registers) are maintained as prescribed in the relevant Act/Rules/Standing instructions (mention the Act/Rules) and have been duly audited by designated auditors. The figures depicted above tally with the audited figures mentioned in financial statements/ accounts.

(ii) There exist internal controls for safeguarding public funds/assets, watching outcomes and achievements of physical targets against the financial inputs, ensuring quality in asset creation etc., & the periodic evaluation of internal controls is exercised to ensure their effectiveness.

(iii) To the best of our knowledge and belief, no transactions have been entered that are in violation of relevant Act/Rules/standing instructions and scheme guidelines.

(iv) The responsibilities among the key functionaries for execution of the scheme have been assigned in clear terms and are not general in nature.

(v) The benefits were extended to the intended beneficiaries and only such areas/districts were covered where the scheme was intended to operate.

(vi) The expenditure on various components of the scheme was in the proportions authorized as per the scheme guidelines and terms and conditions of the grants-in-aid.

(vii) It has been ensured that the physical and financial performance under…….(name of the scheme has been according to the requirements, as prescribed in the guidelines issued by Govt. of India and the performance/targets achieved statement for the year to which the utilization of the fund resulted in outcomes given at Annexure – I duly enclosed.

(viii) The utilization of the fund resulted in outcomes given at Annexure – II duly enclosed (to be formulated by the Ministry/Department concerned as per their requirements/ specifications.)

(ix) Details of various schemes executed by the agency through grants-in-aid received from the same Ministry or from other Ministries is enclosed at Annexure-II (to be formulated by the Ministry/Department concerned as per their requirements/specifications).

Date:

Place:

Signature

Name.....

Chief Finance Officer (Head of the Finance)

Signature

Name.....

Head of the Organization

(Strike out inapplicable terms)

Annexure-II

Beneficiary-oriented interventions with Unit cost & Physical units to be covered in 5 years (2021-22 to 2025-26)

#	Scheme & Components	Unit cost (Rs.)	Total physical (2021-26)	Financial (Rs. in cr.) (2021-26) GOI Share
A	**Capacity Building & Training for Sericulture Sector**			
1	Capacity Building & Training for skill seeding & skill upgradation (Unit No.)	7,000	18250	12.78
B	**Pre-cocoon Sector**			
1	**Support for development of Kisan Nurseries for Mulberry & Vanya**			
1a	Mulberry Kisan Nursery (Unit Per Acre)	1,50,000	350	3.15
1b	Vanya Kisan Nursery (Unit Per Acre)	1,00,000	50	0.38
2	**Package of assistance for silkworm rearing (mulberry & Vanya)**			
2a	Mulberry silkworm rearing 250 dfls capacity (Southern region only) (Unit No.) For 2 Acre Plantation	7,50,000	10260	461.7
2b	Mulberry silkworm rearing 150 dfls capacity (Southern, Central & Eastern region only) (Unit No.) For 1 Acre Plantation	5,00,000	5280	171.6
2c	Mulberry silkworm rearing 100 dfls capacity (North-West region only) (Unit No.) For 0.5 to 1 Acre Plantation	3,00,000	1822	40.99
2d	**Vanya silkworm rearing (Unit per Acre)**			
	Tasar	1,20,000	2000	18
	Eri	1,50,000	2500	28.12
	Muga	2,00,000	250	4
3	**Popularization of Chawki Rearing Centres (No.)**	13,00,000	100	7.8
	B. Sub Total (Pre-cocoon)		22612	729.61
C	**Seed Sector**			
1	**Support to Silkworm Seed rearers**			
1a	Mulberry silkworm seed rearers	5,00,000	600	18
1b	Vanya silkworm seed rearers	5,00,000	1000	35
2	**Support to Silkworm Seed Production Units**			
2a	Construction of grainage building (100 squares) and procurement of grainage equipment (Mulberry-Bivoltine)	2,16,00,000	17	22.03
2b	Strengthening of Vanya silkworm seed production units (Tasar)	6,00,000	25	1.12
2c	Vanya Private Graineurs	5,00,000	500	18.75
	C. Sub Total (Seed sector)		2142	94.9

#	Scheme & Components	Unit cost (Rs.)	Total physical (2021-26)	Financial (Rs. in cr.) (2021-26) GOI Share
D	**Post cocoon sector**			
1	**Support for Small & Medium Mulberry Silk Reeling units**			
1a	Motorized charka to dissuade child labour	30,000	100	0.18
1b	Up-gradation of existing cottage basin/domestic basin units	2,40,000	500	7.2
1c	Establishment of Multi-end Reeling Units–10 Basins	20,76,000	125	15.57
2	**Support for Automatic Silk Reeling Machinery Package for individual**			
2a	Establishment of ARM Unit–120 ends	39,15,000	100	21.53
2b	Establishment of ARM Unit–200 ends	85,90,000	20	9.45
2c	Establishment of ARM Unit–400 ends	149,66,500	85	69.97
2d	Assistance for twisting units (480 spindle capacity)	11,00,000	100	6.05
2e	Establishment of water recycling plant for reeling units (1.0 Lakh litres per day capacity)	18,00,000	19	1.88
3	**Support for Automatic Silk Reeling Machinery Package for enterprise**			
	Establishment of ARM Unit–5 line (2000 ends)	598,00,000	5	8.97
4	**Support for establishment of pupae processing unit**	22,85,700	40	5.03
5	**Support for Vanya Reeling and Spinning units**			
	Buniyaad reeling machine	9,750	6000	4.39
	Sonalika muga weft reeling machine	16,330	675	0.88
	Unnathi reeling machine	27,300	250	0.51
	Motorized reeling-cum-twisting machine	25,350	360	0.64
	Motorized-cum-pedal operated spinning machine	8,050	250	0.14
	Single window re-reeling machine motor operated	16,000	100	0.11
	Tasar reeling machineries package	13,87,000	6	0.58
	Miniature eri spinning plant	80,00,000	5	2.8
6	**Support for providing services of Master Reelers/ Technicians as Twister/Weaver/Dyer/Mechanics for silk industry**	2,52,000	375	9.45
7	**Support for cocoon drying facility in designated cocoon Market**			
	Conveyor hot air drier (1000 kg capacity)	16,77,500	10	0.92
	Conveyor hot air drier (2000 kg capacity)	24,27,000	5	0.67

Annexure-III

Project Monitoring Committee (State level)

Composition	Terms of Reference
Chairperson 1. Commissioner/Director of Sericulture of the State/Heads of Line Department **<u>Members</u>** 1. Director, CSTRI, Bengaluru or his representative 2. Director of the respective CSB's Research Institute/its local representative 3. Senior Accounts Officer of Sericulture Department at State Headquarter 4. Officer from Agriculture, RD/Other Department from where convergence is proposed 5. In-Charge Officer of respective Regional Offices of CSB 6. A representative each from State Sericulture Departments. looking after Seed, Pre and Post-cocoon Sectors 7. District Sericulture Officer of Project area 8. Nodal Officer from CSB for the State 9. Senior officer from the concerned State Department - **Member Convenor**	1. Formulation of projects with convergence from other funding agencies and Annual Action Plan. 2. Monitor progress on implementation of Silk Samagra-2 components at the grass root level in close association with the district/division/field level implementing agencies. 3. To ensure submission of Utilization Certificates as per GFR & progress reports to CSB for release of funds and updating beneficiary details in DBT- Serviceplus portal. 4. Finalisation of beneficiary list along with Aadhaar Number and other details. 5. To constitute Sub-Committee under the Chairmanship of DoS involving CSB and State representatives to scrutinize and recommend purchase proposals and for other matters involved in Silk Samagra-2 components. 6. Monitor production of bivoltine and other varieties of silk on quarterly basis against targets and suggest interventions in case of shortfall. 7. Review progress on utilization of infrastructure created for sericulture in earlier periods for maximization of benefits, keeping in view the mapping exercise carried out. 8. Review production and productivity improvement. 9. Discuss coverage of beneficiaries under different categories 10. Review of schemes and programmes of other Ministries/Department. Implemented for sericulture development (financial and physical) and to ensure submission of progress report to CSB. 11. Follow-up action on the decisions of AAMC and other review meetings. 12. To consider re-appropriation of fund from one component to another within the overall frame-work of scheme guidelines, with justification. 13. Updation of State profile on quarterly basis and review geo-tagging of assets. 14. Maintenance and review of district-wise database on support under the Silk Samagra-2/Other scheme. 15. To list out issues/constraints relating to sericulture development and suggest remedial measures. 16. To organize concurrent evaluation and social audit. 17. Other matters which are important for successful implementation of Silk Samagra-2 18. The Committee shall meet once in a quarter in physical or virtual mode. 19. PMC may co-opt any other member or form other Sub-committees, if need arises. 20. The term of the Committee is for the entire period of 5 years *i.e.,* 2021-2026.

Annexure-IV

Apex Approval & Monitoring Committee (CSB Secretariat level)

Composition	Terms of Reference
Chairperson 1. Member Secretary, CSB **Members** 2. DoS of States whose Projects are placed in the agenda 3. Director (Finance), CSB 4. Director (Tech), CSB 5. Director, NSSO, CSB 6. Director, CSTRI, CSB 7. Scientist-D (PCT), CSB 8. In-charge, Silk Samagra Scheme/Technical Section, CSB -**Member Convenor** **Permanent Invitees** 9. Nodal officers for States from CSB Secretariat 10. Scientist-D, Statistics, CSB Secretariat	. 1. To consider the Silk Samagra-2 projects recommended by States' PMC, which is duly scrutinised, appraised by the In-house Appraisal Committee at CSB Headquarters. 2. To approve the projects based on the overall allocation of funds, provision available under General, SCSP, TSP & North East Heads for the 5 year period. 3. To review progress of implementation of projects. 4. To review the progress of Seed production, plantation development and raw silk production (Bivoltine and other varieties of silk) against targets. 5. To oversee the implementation of Silk Samagra-2 scheme in 5 years (2021-22 to 2025-26). 6. To put in place an MIS for monitoring progress and review of Silk Samagra-2 implementation besides Geo-tagging. 7. To issue directions and guidelines from time to time to the PMC/States on all matters regarding formulation and implementation of Silk Samagra-2 schemes. 8. To review yearly evaluation reports received from States and organise Mid-Term evaluation during 2023-24 followed by Final Evaluation during 2025-26. 9. The Committee would meet minimum twice a year to review/monitor the implementation of the Silk Samagra-2 components and also approve proposals. 10. The Committee may co-opt any other member or form Sub-Committees, if deemed necessary and invite Officers from States to attend AAMC, as per requirement. 11. The term of the Committee is for the entire period of 5 years *i.e.,* 2021-2026.

Annexure-V

PROFORMA (TEMPLATE) FOR SUBMISSION OF PROJECT PROPOSALS UNDER THE SILK SAMAGRA-2 SCHEME OF THE MINISTRY OF TEXTILES, GOVERNMENT OF INDIA

1. Title of the project
2. Details of the Implementing Agency
3. Executive summary of the project
4. Intended outcome of the project (Measurable in terms of production/employment/income enhancement/market penetration. (List of indicators is given in Annexure II)
5. Baseline data
6. Source of baseline data
7. Output of the project physical deliverables
8. Proposed input in the projects
9. Component-wise cost of input
10. Implementation strategy
11. Arrangement for Aadhaar number in case of beneficiary/geo-tagging in case of infrastructure
12. Convergence framework (convergence with other schemes/programmes of State/Union Government)
13. Whether all necessary statutory/administrative clearances are available?
14. Monitoring mechanism
15. Whether land and other infrastructure facilities required for the project are available? If not, whether these facilities will be made available?
16. Whether it is proposed to follow the Central Sector pattern of implementation? If not, whether the State Govt. is willing to bear 10% cost of the project?
17. Annexures with project at a glance, year-wise phasing, unit cost details, output and outcome.
18. Other supporting information specific to the proposed project

Signature _____
(Name & Designation of the Officer)
With Office Seal

Place:
Date:

Annexure-VI

Suggested Indicators of Outcome

1. Production % increase from the baseline
2. % increase in production of cocoons per 100 dfls
3. % increase in production of cocoons from 1 acre
4. % increase in production of silk from 1 acre
5. Employment in terms of man days per acre/year
6. Beneficiaries covered under the project
7. Employment generated under the project
8. Indirect employment
9. Income enhancement (% increase in family income)
10. Market penetration - Participation in number of fairs (domestic/international)
11. Income generation per acre/year through intercropping and by-product utilization
12. Other indicators relevant to the project, based on the nature of the DPR

Annexure-VII

GFR 12 – C

[(See Rule 239)]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE (FOR STATE GOVERNMENTS)

(Where expenditure incurred by Govt. bodies only)

Sl. No.	Letter No. and date	Amount	Certified that out of Rs. of ..... grants sanctioned during the year ..... in favour of ..... under the Ministry/Department Letter No. given in the margin and Rs. on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs.....has been utilized for the propose of .....for which it was sanctioned and that the balance of Rs..... remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Government (vide No ..... dated .....)/will be adjusted towards the grants payable during the next year.
	Total		

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the propose for which it was sanctioned.
3. Abstract of Physical achievement made:

Sl. No.	Details of beneficiary-oriented Components implemented	Status of unit sanctioned		Status of beneficiary covered	
		No. of units sanctioned	No. of units completed	No. of beneficiary covered	Balance to be completed
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Kinds of checks exercised

1.
2.
3.
4.
5.

Signature.....

Designation.....

Date.....

PS: The UC shall disclose separately the actual expenditure incurred and loans and advances given to suppliers of stores and assets, to construction agencies and like in accordance with scheme guidelines and in furtherance to the scheme objectives, which do not constitute expenditure at the stage. These shall be treated as utilized grants but allowed to be carried forward.

Annexure-VIII

Checklist for Project formulation and Appraisal

#	Checklist	Compliance
A	**Project formulation & appraisal stage**	
1	Furnishing concept paper with recommendation of State PIMC	
2	Concurrence from CSB to State/Agency for DPR preparation	
3	*Based on approval of AAMC of CSB, DPR is to be submitted with the following details:*	
a)	Appraisal note of the DPR from jurisdictional Regional Office	
b)	Recommendation with comments of State PMC	
c)	PPT on the project from State/Implementing Agency	
d)	Diagnostic study/baseline survey report enclosed to the DPR	
e)	Project formulated as per the DPR Template	
4	Project analysis at CSB HQ and placing before AAMC for consideration of the DPR	
5	Brief presentation by the State/Agency	
6	Communication of approval/decision of AAMC to State/Agency	
B	**Conditions for release of first instalment**	
1	Letter with details from State/Agency for fund release	
2	Constitution of Project Level and State Level Committees	
3	Action Plan for the work to be carried out during the financial year	
4	Time line for component-wise activities along with milestones for each of the financial years of project period	
5	List of beneficiaries/undertaking to submit it before second instalment	
6	Report on the readiness at the ground and work already initiated to implement the project	
7	Arrangement for facilitating/providing road and trunk infrastructure fequired or the project	
8	Provision of matching State share, wherever required	
9	Mobilising matching beneficiary share	
10	The project shall be completed during the approved period	
11	Web based MIS development status	
12	Putting in place PFMS/EAT module for fund release	
13	Arrangement for DBT and commitment for monthly compliance	
14	Engagement of Project Manager/Co-ordinator	
15	Arrangement/status of bank account by the beneficiaries	
16	Commitment of the State Government that they have requisite statutory and legal clearances wherever required for plantation and construction work	
17	Schemes of State/Other Ministries implemented for Sericulture, if any, in the project area	
18	Status of Aadhaar enrolment among beneficiaries and by when all beneficiaries to be provided with Aadhaar	

SOP & Guidelines

C	Release of Second instalment	Compliance
1	Letter from State for second instalment, by fulfilling the GFR conditions	
2	Title of the land used for the project shall be in the name of individual beneficiaries	
3	Agreement entered into with beneficiaries for continuing sericulture activity for a minimum period of 5 years and exclusive ownership of assets created shall be in the name of Govt. of India to the extent of funding from GoI	
4	Physical and financial progress report countersigned by CSB Unit/State with supporting 70% or more UC	
5	Joint field visit report by CSB/State with supporting photographs of field progress	
6	Compliance of PFMS/EAT module and DBT	
7	Development of web based MIS and uploading data from DPR *vis-a-vis* funds released/physical targets-achievement	
8	Geo-tagging activities carried out for the plantation/assets	
9	List of beneficiaries to be assisted with second instalment	
10	Release of matching state share in proportion to the funds released in first instalment	
11	Arrangement of matching state share for 2nd instalment	
12	Arrangement made for beneficiary share in respect of the machineries /equipment supply under the project	
13	Time line for component-wise activities along with milestones for utilisation of 2nd instalment funds	
14	Stipend to the trainees credited to their account in terms of DBT	
15	Construction work/procurement of equipments and services for the projects done in accordance with relevant GFR provisions	
16	Meeting(s) held by the Project Level Committee to review the project implementation and progress	
17	The amount released is utilized in accordance with the scheme guidelines, other relevant terms & conditions and extant guidelines of government on the matter	
18	State Govt./beneficiary has not availed any financial assistance for the similar purpose from any other government/non-government organization	
19	The fund released is spent for the purpose for which it is sanctioned & there is no deviation of fund for any other purpose	
20	Fund release to the last mile/expenditure incurred is as per timeline and milestones	
D	**Release of Third instalment (Final)**	
1	Letter from State for final instalment, by fulfilling the conditions stipulated while releasing previous instalment	
2	Physical and financial progress report countersigned by CSB Unit/State with supporting 100% UC for the 1st instalment and 70% or more UC for the 2nd instalment.	
3	Joint field visit report by CSB/State with supporting photographs of field progress	
4	Action initiated for concurrent/mid-term evaluation of the project	
5	All other conditions indicated for release of 2nd instalment are also applicable for release of 3rd and final instalment	

Annexure-IX

Silk Samagra-2: Unit Cost

Brief details and Unit Cost break-up of beneficiary-oriented packages/components for implementation under Silk Samagra-2 scheme

This section presents a brief write-up on each of the components/packages with cost norms for every component. Unit cost of all the beneficiary-oriented components are fixed keeping in view the prevailing cost of required items/wages under each component as per recommended scientific lines so as to ensure effective technology transfer. In respect of the pre-cocoon sector, the base costs have been fixed as per the approved unit cost of the previous Silk Samagra scheme, which was communicated by the Ministry as a part of the guidelines for implementation vide letter No.25019/3/2016-Silk dated 4th July, 2018 and changes, wherever applicable have been made on the basis of current prices. In respect of post-cocoon sector, a tender process was carried out for each of the equipments/machineries to arrive at details of unit cost as per current prices. The unit cost fixed for the packages/components under the scheme are indicative and maximum for calculation of GOI share by implementing agencies. States have to follow the prescribed Govt. procurement process and SOR for various activities. In case, the unit cost adopted by a State is less than the indicative cost, GOI share shall be reduced on pro-rata basis as per the sharing pattern applicable to State.

The Unit Cost indicated/approved for beneficiary-oriented components/packages under Silk Samagra-2 scheme are meant for subsidy purpose and not meant for availing institutional/banking finance.

1. Funding pattern for beneficiary-oriented packages/components

a. The fund sharing pattern (%) for individual beneficiary oriented Silk Samagra-2 components other than states in NE region**:**

Category (Small and Marginal Farmers)	GOI (CSB)	State	Beneficiary
General States	50%	25%	25%
General States – For SCSP & TSP	65%	25%	10%
Special Status States (for General, SCSP & TSP Category)	80%	10%	10%

b. Funding Pattern (%) for Seri Business Enterprise/New Entrepreneurs

Category (New Entrepreneurs/Startups)	GOI (CSB)	State	Beneficiary
General	30%	20%	50%
SCSP, TSP, Special Status States/NE States	40%	30%	30%
Existing Entrepreneurs			
General	20%	20%	60%
SCSP, TSP, Special Status States/NE States	30%	30%	40%

c. Funding Pattern **(%)** for North East specific Sericulture Projects in line with NERTPS shall be continued as under:

Category	GOI (CSB)	State	Beneficiary
Group activity/Community based programmes **(Small and Marginal Farmers)**	100%	-	-
Common Facility/State infrastructure	90%	10%	-
Individual Beneficiary **(Small and Marginal Farmers)**	90%	-	10%

2. Beneficiary-oriented critical interventions: Outlay with Unit cost & Physical units projected for 5 years (2021-22 to 2025-26)

#	Scheme & Components	Unit cost (Rs.)	Total Physical (2021-26)	Financial (Rs. in cr.) (2021-26) GOI Share
A	**Capacity Building & Training for Sericulture Sector**			
1	Capacity building & training for skill seeding & skill upgradation (Unit No.)	7,000	18250	12.78
1	**Support for development of kisan nurseries for mulberry & vanya**			
1a	Mulberry kisan nursery (Unit: Per acre)	1,50,000	350	3.15
1b	Vanya kisan nursery (Unit: Per acre)	1,00,000	50	0.38
2	**Package of assistance for silkworm rearing (mulberry)**			
2a	Mulberry silkworm rearing 250 dfl capacity (Southern region only) (Unit No.) For 2 acre plantation	7,50,000	10260	461.70
2b	Mulberry silkworm rearing 150 dfl capacity (Southern, Central & Eastern regions only) (Unit No.)- For 1 acre plantation	5,00,000	5280	171.60
2c	Mulberry silkworm rearing 100 dfl capacity (North-West region only) (Unit No.)- For 0.5 to 1 acre plantation	3,00,000	1822	40.99
	Package of assistance for silkworm rearing (Vanya)			
2d	Tasar (1 ha plantation)	1,20,000	2000	18.00
	Eri (1/2 acre plantation)	1,50,000	2500	28.12
	Muga (1 acre plantation)	2,00,000	250	4.00
3	**Popularisation of Chawki Rearing Centres (No.)**	**13,00,000**	**100**	**7.80**
B. Sub-total (Pre-cocoon)			**22612**	**729.61**
1	**Support to silkworm seed rearers**			
1a	Mulberry silkworm seed rearers	5,00,000	600	18.00
1b	Vanya silkworm seed rearers	5,00,000	1000	35.00

#	Scheme & Components	Unit cost (Rs.)	Total Physical (2021-26)	Financial (Rs. in cr.) (2021-26) GOI Share
2	**Support to silkworm seed production units**			
2a	Construction of grainage building (10,000 sft) and procurement of grainage equipment (Mulberry - Bivoltine)	2,16,00,000	17	22.03
2b	Strengthening of Vanya silkworm seed production units (Tasar)	6,00,000	25	1.12
2c	Vanya private graineurs	5,00,000	500	18.75
	C. Sub-total (Seed sector)		**2142**	**94.90**
D	**Post-cocoon sector**			
1	**Support for small & medium mulberry silk reeling units**			
1a	Motorized charka to dissuade child labour	30,000	100	0.18
1b	Up-gradation of existing cottage basin/domestic basin units	2,40,000	500	7.20
1c	Establishment of Multi-end Reeling Units–10 basins	20,76,000	125	15.57
2	**Support for Automatic Silk Reeling Machinery package for individual**			
2a	Establishment of ARM Unit – 120 ends	39,15,000	100	21.53
2b	Establishment of ARM Unit – 200 ends	85,90,000	20	9.45
2c	Establishment of ARM Unit – 400 ends	1,49,66,500	85	69.97
2d	Assistance for twisting units (480 spindle capacity)	11,00,000	100	6.05
2e	Establishment of water re-cycling plant for reeling units (1.0 lakh liter per day capacity)	18,00,000	19	1.88
3	**Support for Automatic Silk Reeling Machinery package for enterprise**			
	Establishment of ARM Unit – 5 line (2000 ends)	5,98,00,000	5	8.97
4	**Support for establishment of pupae processing unit**	22,85,700	40	5.03
5	**Support for vanya reeling and spinning units**			
	Buniyaad reeling machine	9,750	6000	4.39
	Sonalika muga weft reeling machine	16,330	675	0.88
	Unnathi reeling machine	27,300	250	0.51
	Motorized reeling-cum-twisting machine	25,350	360	0.64
	Motorized-cum-pedal operated spinning machine	8,050	250	0.14
	Single window re-reeling machine - motor operated	16,000	100	0.11
	Tasar reeling machineries package	13,87,000	6	0.58
	Miniature eri spinning plant	80,00,000	5	2.80

#	Scheme & Components	Unit cost (Rs.)	Total Physical (2021-26)	Financial (Rs. in cr.) (2021-26) GOI Share
6	**Support for providing services of Master Reelers/Technicians as Twister/Weaver/Dyer/ Mechanics for silk industry**	2,52,000	375	9.45
7	**Support for cocoon drying facility in designated Cocoon Market**			
	Conveyor hot air drier (1000 kg capacity)	16,77,500	10	0.92
	Conveyor hot air drier (2000 kg capacity)	24,27,000	5	0.67
8	**Support for Silk Weaving Sector**			
	Modified Region Specific Silk Handlooms (Pit loom)	41,000	1600	3.94
	Computer Aided Textile Designing (CATD) Unit	5,85,000	130	4.56
	Electronic Jacquard (720 hooks) with lifting mechanism	2,42,000	585	8.49
	Loom up-gradation through Jacquards, Pirn winding and other equipments.	17,500	850	0.89
	Pneumatic Lifting mechanism (PLM) – 2 loom unit	38,000	250	0.57
	Sectional warping machine/Ball warping machines	35,000	450	0.95
	Asu Machine & Winding machine package	45,000	450	1.22
9	**Support for Silk Dyeing & Processing facilities**			
	Micro-tub dyeing unit - 2 kg unit	1,00,000	80	0.44
	Tub dyeing - 50 kg unit	10,13,000	15	0.84
	Arm dyeing -50 kg unit	23,80,000	5	0.65
	Silk Digital Printing machine with required Wet processing machinery package (Enterprise only)	1,65,00,000	5	2.48
	Fabric Processing unit - 250 kg	34,34,000	5	0.94
	Finishing unit	11,42,000	8	0.50
9a	**Sericin Extraction Unit 10 kg capacity**	**15,24,000**	**8**	**0.67**
10	**Support for establishing Effluent Treatment Plant (ETP) for silk processing units**			
	ETP - Discharge to ground	10,00,000	13	0.72
	ETP - Zero discharge	15,00,000	8	0.66
	A. Sub-total (Post-cocoon sector)		**13592**	**195.44**
D	**Flexi Fund (10% of project cost)**	**NA**		**17.27**
Total Financial				**1050.00**

3. Package/component-wise unit cost breakup

3.1 Capacity Building/Training for skill seeding & Skill upgradation

Capacity Building & Training is designed for empowering the sericulture stakeholders to enhance their skills & expertise in silk related Farm to Fabric activities through practical oriented training. A provision of Rs.1,277.50 lakh is proposed for the period from 2021-22 to 2025-26, to train 18,250 members in all aspects/activities of silk value chain – nursery raising, chawki rearing, late-age rearing, disease management, disinfection technique, silkworm seed preparation, post-cocoon technologies etc; with a unit cost of Rs.7,000/-. The state Sericulture Departments in collaboration with CSB institutes shall organize training under new rationalized head- "Capacity Building & Training for skill seeding & skill up-gradation". ***The unit cost has been arrived at considering (i) Wage compensation, (ii) Boarding & Lodging charges, (iii) Training material & training cost, (iv) Study material, if any, and (v) Travel Compensation to the beneficiaries.***

The unit cost details are given below:

#	Items/Particulars	Unit	Unit price (Rs.)	Unit cost (Rs.)	
				Physical	Cost
1	Beneficiary Empowerment Programme	Per Farmer	--		7,000
a	Beneficiary Training	Per Farmer	--		5,000
b	Sericulture Exposure visit	Per Farmer	--		2,000
2	Duration of programme	Days	--	6 days with each batch of 30 trainees	
	Total	--	--		**7,000**

3.2 Pre-cocoon sector

3.2.1 Support for development of Kisan nurseries

For effective plantation and survivability, raising of nurseries are essential than plantation through cuttings/seedlings. Hence, it is proposed to support Kisan Nurseries with provision for irrigation facilities for horizontal growth of the industry for both Mulberry & Vanya sector. A unit cost of Rs.1.50 lakh for Mulberry & Rs.1.00 lakh for Vanya is proposed per Kisan Nursery to support 1 Acre land holding capacity with nursery beds. A total of Rs.352.50 lakh to cover 400 Kisan nurseries is proposed from 2021-22 to 2025-26. ***Unit cost for Nursery includes all activities and equipment viz., (i) Preparation of Nursery plot; (ii) Cost of Planting material; (iii) Maintenance of the nursery garden and (iv) Cost of tools, machinery & equipment.***

Unit cost details for mulberry nursery are given below:

(Amount in Rupees)

#	Particulars	Unit	Unit Cost	Quantity	Total
I	**Preparation of Nursery**				
1	Tractor ploughing	hr	800	4	3,200
2	Sand	Truck load	10,000	2	20,000
3	Bullock plough	Day	500	2	1,000
4	Preparation of nursery bed	Man day	250	50	12,500
5	Farmyard manure	MT	1,000	10	10,000
6	Broadcasting of sand	Man day	250	8	2,000
7	Broadcasting of farmyard manure	Man day	250	8	2,000
II	**Planting and Maintenance of Nursery**				
1	Planting Material	MT/No.	2,000	6	12,000
2	Transportation of planting material	Load	3,000	1	3,000
3	Preparation of cuttings	Man day	250	35	8,750
4	Planting of cuttings	Man day	250	105	26,250
5	Irrigation	Man day	250	20	5,000
6	Weeding	Man day	250	75	18,750
7	Fertilizer	kg	6	65	390
8	Application of fertilizer	Man day	250	2	500
9	Uprooting of saplings	Man day	250	15	3,750
10	Miscellaneous	Lump sum	--	--	2,000
III	**Machineries, tools and equipment**				
1	Garden implements	Lump sum	--	--	2,000
2	Cutting making machine	No.	15,000	1	15,000
3	Electricity and diesel	Lump sum	--	--	1,910
	Total	**--**	**--**	**1 Acre**	**1,50,000**

For Vanya nursery (tasar, eri & muga), the assistance is restricted to Rs.1.00 lakh.

3.2.2 Package of assistance for silkworm rearing

Instead of giving assistance in individual mode for activities involved in silkworm rearing, it is proposed to provide assistance in bundled package form. The package proposed includes support for improved variety plantation, irrigation, construction of rearing house, supply of rearing appliance & disinfectants (prophylactic measures for better yield) and popularisation of Chawki Rearing Centres for Mulberry. The CRCs will have forward linkage with the existing as well as new plantation in the area depending on the rearing capacity.

The details of package proposed with unit cost are indicated below:

#	Particulars of Package	Unit Cost (Rs.)
A	**Mulberry silkworm rearing**	
1	**Mulberry Silkworm rearing 250 dfl capacity (Southern, Central & Eastern region only) - For 2 Acre plantation: Physical target -10,260 No.**	
	Plantation	1,20,000
	Irrigation	1,00,000
	Rearing House	4,50,000
	Rearing Equipment	75,000
	Disinfectants (Prophylactic measures)	5,000
	Total	**7,50,000**
2	**Mulberry Silkworm rearing 150 dfl capacity (Southern, Central & Eastern region only) – For 1 Acre plantation: Physical target-5,280 No.**	
	Plantation	60,000
	Irrigation	60,000
	Rearing House	3,25,000
	Rearing Equipment	50,000
	Disinfectants (Prophylactic measures)	5,000
	Total	**5,00,000**
3	**Mulberry Silkworm rearing 100 dfl capacity (North-west region only) – For 0.5 to 1 Acre plantation: Physical target - 1,822 No.**	
	Plantation	40,000
	Irrigation	30,000
	Rearing House	1,85,000
	Rearing Equipment	40,000
	Disinfectants (Prophylactic measures)	5,000
	Total	**3,00,000**
B	**Vanya Silkworm rearing**	
1	**Tasar : Physical target - 2000 No.**	
	Plantation (per ha)	80,000
	Rearing & Mounting Equipment	35,000
	Disinfectants (Prophylactic measures 300 dfl capacity–one ha)	5,000
	Total	**1,20,000**

#	Particulars of Package	Unit Cost (Rs.)
2	**Eri: Physical target - 2500 No.**	
	Plantation (per ½ acre)	20,000
	Rearing House	1,00,000
	Rearing & mounting equipment	27,500
	Disinfectants (Prophylactic measures)	2,500
	Total	**1,50,000**
3	**Muga : Physical target - 250 No.**	
	Plantation (per acre)	55,000
	Irrigation & fencing	30,000
	Rearing & mounting equipment with mounting hall	1,12,500
	Disinfectants (Prophylactic measures)	2,500
	Total	**2,00,000**

Mulberry Plantation development/Acre

(Amount in Rupees)

#	Particulars	Unit	Unit Cost	Physical	Financial
I.	**Labour Cost**				
1	Tractor tilling for land preparation	hr	1,000	4	4,000
2	FYM application	Man day	290	8	2,320
3	Preparation ridge/furrow/pit making	Man day	290	20	5,800
4	Planting of saplings	Man day	290	10	2,900
5	Ploughing for intercultural operation (two times/year)	Man day	290	4	1,160
6	Irrigation - 40 times/year	Man day	290	20	5,800
7	Weeding - 4 times/year	Man day	290	16	4,640
8	Fertilizer application - 3 times/year	Man day	290	3	870
II.	**Material Cost**				
1	Farmyard manure	MT	1270	8	10,160
2	Mulberry saplings	No.	2.5	6,000	15,000
3	Vermicompost/Bio & liquid fertilizers	Lump sum			2,000
4	Fertilizers @ 20:20:20 kg NPK/acre after 2 months of planting (200 kg Ammonium Sulphate, 125 kg Single Super Phosphate and 35 kg Muriate of Potash and another dose of N@20kg)				4,200
5	Tools/appliances	Lump sum			1150
	Total				**60,000**

Irrigation/Acre

(Amount in Rupees)

#	Particulars	Unit/Unit cost	Financial
1	Development of irrigation sources (Construction/digging of farm ponds, open wells, bore-wells, bore-well recharge structures, surface tanks including storage tanks, conservation facilities etc.)	Lump sum	60,000
2	Water lifting devices (Electric Pump-set, Diesel Engine Pump-set etc.)	Lump sum	40,000
3	Sprinkler irrigation system	Lump sum	40,000
4	Micro-drip irrigation system	Lump sum	60,000
5	Rain gun with accessories	Lump sum	40,000
	Total	--	**60,000**

Unit cost of Rs.60,000/- is maximum/acre including GST, transportation of material, installation etc. However, the unit cost is restricted to maximum of Rs.1.00 lakh for 2 acre plantation capacity. Farmers can avail any sub component of the scheme as per suitability subject to upper limit mentioned against them. Based on actual need, irrigation facility can be availed for Vanya sector also, within the overall upper ceiling limit.

Mulberry rearing house

#	Items/Particulars	Floor area unit	Unit price (Rs.)	Financial (Rs.)	Regions applicable
1	Model I - with rearing capacity of 250 dfls/batch	1,000 sft	Lump sum	4,50,000	Southern states
2	Model II - with rearing capacity of 150 dfls/batch	600 sft	Lump sum	3,25,000	Central and Eastern
3	Model III -with rearing capacity of 100 dfls/batch	400 sft	Lump sum	1,85,000	North Western and NER

Unit cost indicated above is maximum for the region including GST, transportation of building material, labour charges etc.

Eri rearing house

(Amount in Rupees)

#	Particulars	Unit	Quantity	Rate	Financial
1	Earth filling (2.5 ft height)	Man day	10	110	1,100
2	Brick-cement post	No.	12	500	6,000
3	Bricks	No.	5000	4	20,000
4	Cement	Bag	20	250	5,000

					(Amount in Rupees)
#	**Particulars**	**Unit**	**Quantity**	**Rate**	**Financial**
5	Sand	cft	260	20	5,200
6	Door frame	No.	1	1600	1,600
7	Window frame	No.	4	800	3,200
8	Door	No.	1	1600	1,600
9	Windows	No.	4	800	3,200
10	Roof Frame channels-G.I. or zinc sheet roof, material for false Ceiling - steel, bamboo or wooden framing with bamboo mesh/foam supported with wire mesh or gypsum board etc.	sft	500	65	32,500
11	Cement flooring	sft	500	16	8,000
12	Labour charge	Man day	60	180	10,800
13	Misc.				1,800
	Total				**1,00,000**

Rearing equipment

									(Amount in Rupees)
#	**Item Particulars**	**Unit**	**Unit Price**	**Southern (For 250 dfls)**		**C & W and Eastern (For 150 dfls)**		**N W & NER (For 100 dfls)**	
				Phy	Cost	Phy	Cost	Phy	Cost
1	HD PVC shoot rearing racks/iron rearing stands	sft	10	2000	20000	1050	10500	800	8000
2	Plastic tray (3' x 2') for chawki worm transportation	No.	500	25	12500	15	7500	10	5000
3	Bamboo made dala (4' x 6') for late age rearing	No.	100	--	--	90	9000	--	--
4	Bed cleaning net	No.	30	--	--	120	3600	80	2400
5	Improved/rotary mountages	No.	650	90	58500	--	--	--	--
6	Plastic collapsible mountages/bamboo chandrike	No.	70	--	--	135	9450	90	6300

#	Item Particulars	Unit	Unit Price	Southern (For 250 dfls)		C & W and Eastern (For 150 dfls)		N W & NER (For 100 dfls)	
				Phy	Cost	Phy	Cost	Phy	Cost
7	Plastic cocoon harvester (Pushers and iron frame)	Set	300	4	1200	3	900	2	600
8	Power sprayer	No.	7500	1	7500	1	7500	1	7500
9	Flame gun	No.	1500	1	1500	1	1500	1	2000
10	Humidifier & heater	Set	10000	1	10000	1	10000	1	10000
11	Solar lighting system	No.	--	--	--	1	5000	1	5000
	Total actual cost				**1,11,200**		**64,950**	**1**	**46,800**
	Unit cost recommended				**75,000**		**50,000**		**40,000**

Disinfectants (Prophylactic measures)

(Amount in Rupees)

#	Items/Particulars	Unit	Unit price	5 crops of 250 dfls/batch		4 crops of 100 to 150 dfls/batch	
				Phy	Cost	Phy	Cost
I	**General disinfectants**						
1	Asthra	100 gm	175	12	2100	8	1400
2	Sanitech	500 ml	100	--	0	8	800
3	Bleaching Powder	kg	35	25	875	18	630
4	Lime	kg	15	50	750	25	375
II	**Bed Disinfectants (Ankush, Rashak, Vijetha etc.)**	Packets	70	50	3500	25	1750
	Uzi Trap (Chemo trap for attracting adult uzi flies)	No. Strips	50	2	100	2	100
	Total				**7325**		**5055**

For mulberry and tasar sectors, unit cost of Rs.5,000/- per farmer is recommended towards disinfectants which is maximum under the component including GST, transportation, etc., while it is restricted to Rs.2,500/- for eri & muga sectors. The zone-wise unit cost indicated above is for Mulberry and shall apply to each of the regions.

Tasar host plantation (For one ha)

					(Amount in Rupees)
#	**Particulars**	**Unit**	**Quantity**	**Rate**	**Financial**
1	Cost of Asan and Arjuna seedlings including 10% mortality	No.	2037	5.00	10185
2	Soil conservation				
	a. Staggered trench (6ft x 2ft x 2ft)	No.	250	57.75	14438
	b. Cattle proof trench (4 ft x 3 ft)	cft	7000	2.63	18410
3	Pit digging (1.5ft x 1.5ft x 1ft)	No.	1852	9.05	16761
4	Cost of vermicompost @ 400 g/plant	Kg	741	8.25	6112
5	Anti-termite treatment	Lump sum			500
6	Transportation	Lump sum			750
7	Filling of pits and transplantation of seedling	No.	1852	5.91	10945
9	Intercropping	Lump sum			1900
	Total				**80,000**

Muga host plantation development (Raising and maintenance per acre)

					(Amount in Rupees)
#	**Particulars**	**Unit**	**Unit cost**	**Quantity**	**Financial**
A	**Raising of plantation**				
1	Land development using tractor	LS			3500
2	Cost of host plant seedlings including 10% mortality		6	500	3000
3	Cattle proof trench (3 ft x3 ft x 5 ft = 45 cft)-250 running mtr	mtr	55	250	13750
4	Pit digging (1.5ft x 1.5ft x 1ft)	No.	8	450	3600
5	Cost of vermicompost @ 400 g/plant	kg	8	180	1440
6	Farm yard manure	cft	10	225	2250
7	Cost of anti-termite treatment	LS			500
9	Transportation of seedlings	LS			1000
10	Filling of pits and transplantation of seedling	No.	2	450	900
11	Watering of plants	Man day	290	5	1450
12	Application of organic fertilizers	Man day	290	2	580
13	Cost of seed for intercropping/bund crop	LS			1500
14	Miscellaneous	LS			1510
	Sub Total				**34,980**

					(Amount in Rupees)
#	**Particulars**	**Unit**	**Unit cost**	**Quantity**	**Financial**
B	**Maintenance cost/year**				
1	Vermicompost	kg	8	180	1440
2	Anti-termite treatment	LS			500
3	Insecticides/pesticides	LS			700
4	Application of anti-termite/ antifungal treatment	Man day	290	4	1160
5	Farm Yard manure/compost	cft	10	225	2250
6	Application of Vermicompost & fertilizers	Man day	290	4	1160
7	Basin formation and weeding (twice/year)	No.	2	900	1800
8	Miscellaneous	LS			1000
	Sub-total				**10,010**
	Maintenance for 2 years				**20,020**
	Total cost for 1 acre plantation				**55,000**

Eri host plantation development (Raising and maintenance per half acre unit)

					(Amount in Rupees)
#	**Particulars**	**Unit**	**Unit Cost**	**Quantity**	**Financial**
1	Land development using tractor	LS			1750
2	Cost of host plant seedlings including 10% mortality		5	250	1250
3	Cattle proof trench (3 ft x 3 ft x 5 ft = 45 cft)-250 running mtr	mtr	55	125	6875
4	Pit digging (1.5ft x 1.5ft x 1ft)	No.	8	225	1800
5	Cost of vermicompost @ 400 gplant	kg	8	90	720
6	Farm yard manure	cft	10	113	1130
7	Cost of anti-termite treatment	LS			250
8	Transportation of seedlings	LS			500
9	Filling of pits and transplantation of seedling	No.	2	225	450
10	Watering of plants	Man day	290	2	580
11	Application of organic fertilizers	Man day	290	1	290
12	Cost of seed for intercropping/bund crop	LS			500
	Sub Total				**16095**

					(Amount in Rupees)
#	**Particulars**	**Unit**	**Unit Cost**	**Quantity**	**Financial**
B	**Maintenance cost/year**				
1	Vermi-compost	kg	8	90	720
2	Anti-termite treatment	LS			250
3	Insecticides/pesticides	LS			300
4	Application of anti-termite antifungal treatment	Man day	290	2	580
5	Farm yard manure/compost	cft	10	100	1000
6	Application of vermicompost & fertilizers	Man day	290	2	580
7	Basin formation and weeding (twice/year)	No.	2	450	900
	Sub-total				**4330**
	Total cost for half acre (1/2 acre) unit (Rounded off to Rs.20,000/-)				**20,425**

The assistance for eri host plantation is applicable only for **Kesseru/Ailanthus varieties and not applicable to castor plantation**.

Rearing & mounting equipment for tasar silkworm rearers

					(Amount in Rupees)
#	**Particulars**	**Unit**	**Quantity**	**Rate**	**Financial**
A	**Rearing equipment**				
1	Secateurs/looping shear	No.	2	1000	2000
2	Gattor sprayer	No.	1	9500	9500
3	Nylon net (40'x30'x10')	No.	2	8000	16000
4	Bamboos	No.	24	170	4080
	Sub-total				**31580**
B	**Tasar silkworm rearing**				
1	Slaked lime	kg	50	15	750
2	Bleaching powder	kg	10	35	350
3	Sodium Hypochloride	kg	1	200	200
4	Jeevan Sudha	Lump sum			500
5	Spraying of Sodium Hypochloride/Jeevan Sudha	Lump sum			800
6	Miscellaneous	Lump sum			1000
	Sub-total				**3600**
	TOTAL				**35,180**
					Rounded off to Rs.35,000/-

Rearing and mounting equipment with mounting hall for muga silkworm rearers

(Amount in Rupees)

#	Particulars	Unit	Quantity	Rate	Financial
	Rearing				
1	Nylon Rearing net (40'*30')	No.	4	7500	30000
2	Plastic Basket/Basin (No.)	No.	2	300	600
3	Knapsack Sprayer for application of insecticides/disinfection purpose	No.	1	5000	5000
4	Pruning saw	No.	1	400	400
5	Secateur	No.	1	350	350
6	Pick axe	No.	1	300	300
7	Bleaching powder & disinfectants	LS	-	-	850
	Sub-total				**37500**
	Mounting of silkworm				
1	Mounting hall-cum-watch & ward shed	No.	1	60000	60000
2	Box type mountage	No.	24	450	10800
3	Solar lantern (subsidized cost)	No.	1	4200	4200
	Sub-total				**75000**
	Total				**1,12,500**

Rearing and mounting equipment for eri silkworm rearers

(Amount in Rupees)

#	Particulars	Unit	Quantity	Rate	Financial
1	Rearing platform (Bamboo or steel frame)	No.	3	2000	6000
2	Plastic rearing trays - for brushing & chawki	No.	8	450	3600
3	Shaded net for shelf rearing support	Mtr	12	240	2880
4	Plastic mountage	No.	80	80	6400
5	Leaf preservation chamber	LS	-	-	1000
6	Plastic basket/basin (No.)	No.	4	300	1200
7	Knapsack sprayer for disinfection	No.	1	5000	5000
8	Chemical, bleaching powder & disinfectants/Hooks, G.I. Wire etc.	LS	-	-	1500
	Total				**27,580**
					Rounded off to Rs.27,500/-

3.2.3 Mulberry Chawki Rearing Centres (CRC)

Main objective of CRC is to promote rearing and supply of chawki reared silkworms to the farmers for robust health and enhancing productivity of bivoltine crops. Each CRC should cater to 70-100 farmers depending upon brushing capacity of the farmers/batch. A provision of Rs.780.00 lakh to cover 100 CRCs is proposed. Unit cost details of CRC are given below:

(Amount in Rupees)

#	Particulars	Unit	Unit Cost	Qty.	Total
I	Inputs for plantation and establishment of upto 2 acres chawki garden (Mulberry cuttings /saplings, labour, land development, FYM, chemical fertilizer, etc.)	LS	--	--	1,00,000
	Micro-irrigation				50,000
II	Rearing house (size:42'x30'16') to rear 5000 dfls/batch	No.	--	1	4,50,000
III	Equipments				
1	Plastic rearing trays	No.	500	400	2,00,000
2	Rearing stands GI pipes or angle iron	No.	5,000	4	20,000
3	Incubation frames	No.	50	100	5,000
4	Leaf chopping machine	No.	20,000	1	20,000
5	Humidifier (heavy duty)	No.	10,000	1	10,000
6	Heater	No.	2,500	2	5,000
7	Power sprayer	No.	14,000	1	14,000
8	Disinfection mask	No.	5,000	1	5,000
9	Microscope	No.	10,000	1	10,000
10	Wet and dry bulb thermometer	No.	1,000	1	1,000
11	Bed cleaning nets	No.	30	1,000	30,000
12	Plastic tray washing machine	No.	30,000	1	30,000
13	Chawki dusting machine	No.	30,000	1	30,000
14	1 KVA Generator	No.	20,000	1	20,000
15	Incubation centre	No.			3,00,000
	Total	**--**	**--**	**1**	**13,00,000**

In case, incubation centre is not required for every CRC, depending on geographical distribution of CRCs in a cluster area, common incubation centres to cater requirement of more than 1 CRC, can also be set up and savings, if any, can be utilised for purchase of additional equipment and vehicle to transport incubated eggs to the attached CRCs.

3.3 Seed Sector

3.3.1 Support to silkworm seed rearers

To produce quality silkworm seed, assistance to mulberry & vanya silkworm seed rearers is proposed. Under this component, support is extended towards strengthening of adopted seed rearers, disinfectants & purchasing seed testing equipments for State and RSPs besides development/maintenance of chawki garden in tasar, eri & muga sector.

The details of package proposed with unit cost as detailed below:

Particulars of Component/Package	Unit Cost (Rs.)	Proposed outlay (Rs. in lakh)
Support to mulberry silkworm seed rearers	5,00,000	1,800
Support to vanya silkworm seed rearers and seed producers (tasar, eri & muga)	5,00,000	3,500

The unit cost details for the above are given below:

Support to mulberry silkworm seed rearers

(Amount in Rupees)

#	Particulars	Unit	Unit Cost	Qty.	Total
A.	**Construction of low cost rearing house**				
	Area of the rearing house - (LBH - 51' x 22' x 14')	No.	350000	1	3,50,000
	Sub-total				**3,50,000**
B.	**Equipment support to seed rearers**				
1	Plastic chawki rearing trays (3' x 2')	No.	600	10	6,000
2	Plastic mountages	No.	85	165	14,025
3	Humidifier	No.	35000	2	70,000
4	Room heater	No.	10000	2	20,000
5	Power sprayer	No.	25000	1	25,000
6	Disinfection mask	No.	14975	1	14,975
	Sub-total				**1,50,000**
	Total (A+B)				**5,00,000**
	Technical Norm: a) The benefit shall be provided only to those Seed Rearers having valid registration. b) The Rearing House has the capacity to rear 100 bivoltine DFLs				

Support to Vanya silkworm seed rearers (eri)

(Amount in Rupees)

#	Particulars	Unit	Unit Cost	Quantity	Total
A	**Host plant cultivation**				
1	Eri perennial host plant cultivation (Kesseru) 0.5 acres	No.	120	250	30000
2	Seasonal eri host plant cultivation (castor) twice		10000	2 crop	20000
4	Green fencing		15000	LS	15000
5	Miscellaneous				5000
	Sub-total (A)				**85000**

					(Amount in Rupees)
#	**Particulars**	**Unit**	**Unit Cost**	**Quantity**	**Total**
B	**Construction activities**				
1	Construction of rearing house (35 ft x 12 ft with 5 ft verandah) with water storage and drainage faci lity	sft	580	Per 480 sft	**278400**
C	**Rearing appliances/equipments (For 100 dfls/crop) 4 crops/year**				
1	Rearing stand for young age eri silkworm rearing **(for keeping rearing tray)**	No.	5000	4	20000
2	Rearing stand for late age worm **(Bunch rearing)**	No.	1500	8	12000
3	Rearing tray (Plastic)	No.	500	30	15000
4	Feeding stand (Wooden)	No.	1000	4	4000
5	Plastic collapsible mountage	No.	500	60	30000
6	Ant wells (Aluminum)	No.	100	20	2000
7	Leaf preservation chamber (Wooden)	No.	6000	2	12000
8	Seed cocoon storage cabinet/rack	No.	9750	2	19500
9	Tarpaulin sheet	No.	3000	2	6000
10	Plastic bucket (20 litre)	No.	300	2	600
11	Plastic mug	No.	50	2	100
12	Plastic drum (50 litre)	No.	1000	1	1000
13	Disinfection mask	No.	100	5	500
14	Gl wire/plastic rope		1000	LS	1000
15	knap pack sprayer	No.	4000	1	4000
16	Foam pad		1000	LS	1000
17	Old newspaper		500	LS	500
18	Measuring cylinder	No.	200	2	400
19	Formalin/bleaching powder/soap		2000	LS	2000
20	Miscellaneous		5000	LS	5000
	Sub-total (C)				**136600**
	Tot al				**500000**

Support to vanya silkworm seed rearers and graineurs (tasar & muga)

#	Particulars	Unit	Quantity	Amount (Rs.)
A	**Assistance to vanya seed cocoon production**			
1	Development/maintenance of chawki garden		--	10,000
2	Maintenance of existing plantation for adult silkworm rearing		--	20,000
3	Rearing equipments and cost of silkworm silkworm rearing		--	20,000
	Sub-total (A)			**50,000**
B	**Assistance to vanya seed production**			
I	**Construction of building**			
1	Construction of grainage building (30'x15') with 5' verandah) with water storage and drainage facility	sft		2,45,000
II	**Grainage equipment**			
1	Microscope with light arrangement	No.	2	
2	Egg laying boxes/nylon net bags	No.	6000	
3	Egg laying cabinet	No.	1	
4	Wooden moth testing table (5ft x 1.5ft)	No.	1	
5	Wooden stools	No.	2	
6	Plastic drum (60 ltr)	No.	1	
7	Plastic bucket (20 ltr.)	No.	5	
8	Plastic tub (small - 10 ltr)	No.	5	
9	Plastic tub (big - 20 ltr)	No.	5	
10	Plastic mug	No.	5	
11	Mortar & pestle	No.	5	
12	Measuring cylinder (Plastic)	No.	1	
13	Weighing balance - Physical	No.	1	
14	Disinfection mask	No.	2	
15	GI Wire (2.5 mm)	kg	2	
16	Wet & dry thermometer	No.	1	
17	Max.-Min. thermometer	No.	1	
18	Gattor sprayer	No.	1	
	Sub-total (C)			**84,000**
III.	**Consumables**			
1	Formalin/KOH/soap/bleaching powder	LS		
2	Blotting paper, muslin cloth, scissors	LS		
3	Slides and cover slips	LS		
4	Lime	LS		
5	Soap & detergent powder	LS		
	Sub-total (D)			**5,000**
IV	**Non-eroding Corpus fund for purchase of seed cocoons**	No.		**60,000**
V	**Moth Testers@ 10 man days per operation**	Man day	10	6,000
VI	**Solar lantern**	LS		6,000

Technical Specification

A . Assistance to Vanya Seed cocoon Production

- Chawki garden with 310 plants (spacing of 1.8m x 1.8m) to take care of chawki rearing in natural host flora or other block plantation. To support chawki rearing of 200 dfls.
- Assistance shall be utilized for maintenance of existing Block Plantation for two years for increasing productivity. Provision of additional 10% seedlings has been kept towards mortality while plants; 10% Chawki garden: 1.8mx 1.8 m - 310 plants
- Lumpsum provisions are made towards fertilizer cost as composition need to be decided based on soil quality and analysis
- Provisions for improved technologies *viz.*, Jeevan Dhara, Sodium hypochloride have been made.
- Provisions are made for maintenance of existing 0.9 ha plantation with brushing capacity of 200 dfls.

B. Assistance for Vanya seed Production

- 1 No. grainage building (30' x 15'x10') with all side 5' verandah. Walls built of local brick and mortar with cemented floor and with Zinc sheet or thatched roofing.
- Land for construction of the building will be of the beneficiary contribution
- Separate provision of 5' x 12' for ovipositon, moth examination, egg washing, etc in the grainage building
- Capacity to preserve 25,000-30,000 seed cocoons and to Produce 5000-6000 dfls per operation
- Moth testers will be empanelled from the persons trained in different states under structured trainings like Integrated Skill Development Scheme of CSB, Service Providers/Community Resource Persons promoted by BTSSO/PPC.
- Non-eroding Corpus Fund to be maintained in Bank and used only for the purpose of purchase of seed cocoons. Cost of seed to be recovered from farmers and the amount equal to cost of seed to be deposited back in the Bank to maintain corpus fund.

3.3.2 Support to Silkworm Seed Production Units

In order to meet the requirement of P1 dfls of all the stake holders for the generation of quality seed cocoons and production of hybrid seed, it is proposed to support the State Government & RSPs for upgrading seed production units to produce quality silkworm seed (Bivoltine & Vanya) by supporting construction of grainage building and procurement of grainage equipment (Mulberry Bivoltine), strengthening of vanya silkworm seed production units (Tasar) and vanya private graineurs.

The details of package proposed with unit cost as detailed below:

#	Particulars of Component/Package	Unit Cost (Rs.)	Proposed outlay (Rs. in lakh)
1.	Construction of grainage building (10000 sft) and procurement of grainage equipment (Mulberry Bivoltine)	2,16,00,000	2203.20
2.	Strengthening of Vanya silkworm seed production units (tasar, eri & muga)	6,00,000	112.50
3.	Vanya private graineurs (tasar, eri & muga)	5,00,000	1875.00

Unit cost details for the above components are given below:

3.3.2.1 Construction of grainage building (10,000 sft) and procurement of grainage equipment (mulberry bivoltine)

(Amount in Rupees)

#	Particulars	Unit	Unit Cost	Quantity	Total
A.	**Construction of grainage building**				
	Area of the grainage building 10,000 sft	No.	1,95,00,000	1	1,95,00,000
	Sub-total				**1,95,00,000**
B.	**Equipment support**				
1	Plastic trays (3' x 2')	No.	600	250	1,50,000
2	Humidifier	No.	35,000	2	70,000
3	Room heater	No.	10,000	4	40,000
4	Split air conditioners (1.50 Ton each)	No.	25,000	4	1,00,000
5	Loose egg washing table	No.	18,000	1	18,000
6	Loose egg egg drying machine	No.	10,000	1	10,000
7	Moth preservation rooms	No.	3,50,000	2	7,00,000
8	Ante room and egg room	No.	8,00,000	1	8,00,000
9	D.G. Set 15 KVA	No.	2,12,000	1	2,12,000
	Sub-total				**21,00,000**
	Total				**2,16,00,000**

Technical Norm

- The benefit shall be provided only to the Registered Seed Producers with permission to produce bivoltine dfls.
- The grainage building has the capacity to produce 10 lakh bivoltine hybrid dfls.

3.3.2.2 Strengthening of vanya silkworm seed production units (tasar, eri & muga)

#	Particulars	Unit	Quantity	Amount (Rs.)
A	**Construction of grainage building**			
1	Modification and renovation of existing grainage building			2,28,000
	Sub-total			**2,28,000**
B	**Grainage equipment**			
1	Microscope with light arrangement	No.	10	
2	Egg laying boxes	No.	15000	
3	Egg laying cabinet	No.	2	
4	Wooden moth testing table (5 ft x 1.5ft.)	No.	5	
5	Wooden chair (with arms)	No.	10	
6	Gattor sprayer	No.	2	
7	Plastic drum (60 ltr)	No.	4	
8	Plastic bucket (20 ltr.)	No.	10	
9	Plastic tub (small - 10 ltr)	No.	10	
10	Plastic tub (big - 20 ltr)	No.	20	
11	Mortar & pestle	No.	100	
12	Measuring cylinder (Plastic)	No.	4	
13	Wet - Dry thermometer	No.	2	
14	Electronic weighing balance (2 kg capacity)	No.	1	
15	Humidifier	No.	1	
16	Egg drying chamber	No.	1	
17	Centrifuge (R23)	No.	1	
18	Generator (5 KV)	No.	1	
19	Disinfection mask	No.	6	
20	GI pipes for hanging cocoons	No.	15	
21	Wet - Dry thermometer	No.	3	
22	Max.-Min. thermometer	No.	3	
23	Almirah	No.	1	
24	Office table	No.	1	
	Sub-total			**2,75,000**
C.	**Consumables**			
	Consumables			
	Glassware	LS		
	Chemicals	LS		
	Egg box		2500	
	Sub-total			**97,000**
	Total			**6,00,000**

3.3.2.3 Vanya private graineurs (tasar)

#	Particulars	Unit	Quantity	Amount (Rs.)
A.	**Construction of building**			
1	Construction of grainage building (35'x15' with 5' verandah) with water storage and drainage facility	sft		
	Sub-total (A)			2,85,000
B.	**Grainage equipment**			
1	Microscope with light arrangement	No.	2	
2	Egg laying boxes/Nylon net bags	No.	6000	
3	Egg laying cabinet	No.	1	
4	Wooden moth testing table (5ft x 1.5ft)	No.	1	
5	Wooden stools	No.	2	
6	Plastic drum (60 ltr)	No.	1	
7	Plastic bucket (20 ltr.)	No.	5	
8	Plastic tub (small - 10 ltr)	No.	5	
9	Plastic tub (big - 20 ltr)	No.	5	
10	Plastic mug	No.	5	
11	Mortar & pestle	No.	5	
12	Measuring cylinder (Plastic)	No.	1	
13	Weighing balance - Physical	No.	1	
14	Disinfection mask	No.	2	
15	GI Wire (2.5 mm)	kg	2	
16	Wet & Dry thermometer	No.	1	
17	Max.-Min. thermometer	No.	1	
18	Gattor sprayer	No.	1	
	Sub-total (B)			**80,000**
C.	**Consumables**			
1	Formalin/KOH/soap/bleaching powder	LS		
2	Blotting paper, muslin cloth, scissors	LS		
3	Slides and cover slips	LS		
4	Lime	LS		
5	Soap & detergent powder	LS		
	Sub-total (C)			**5,000**
D.	Moth Testers@ 10 man days per operation	Man day	10	6,000

#	Particulars	Unit	Quantity	Amount (Rs.)
E.	Non-eroding Corpus fund for purchase of seed cocoons	No.	30000	75,000
F	Solar lantern	LS		5,000
G	Incentive @ Rs.6/- dfls for 6000 basic dfls		6000	36,000
H	Miscellaneous - Insurance of building/equipments/seed cocoons			8,000
	Sub-total (D+E+F+G+H)			**1,30,000**
	Total			**5,00,000**

Technical Specification

- Grainage Building (35' x 15'x10') with all side 5' verandah. Walls built of local brick and mortar with cemented floor and with Zinc sheet or thatched roofing.
- Land for construction of the building will be of the beneficiary contribution
- Separate provision of 5' x 12' for ovipositon, moth examination, egg washing, etc., in the grainage building.
- Capacity to preserve 30,000 seed cocoons and to produce 6000 dfls/operation
- 6000 dfls with dfl weight – 1 g
- Moth testers will be empanelled from the persons trained in different states under structured trainings like Integrated Skill Development Scheme of CSB, Service Providers/Community Resource Persons promoted by BTSSO/PPC.

Non-eroding Corpus Fund to be maintained in Bank and used only for the purpose of purchase of seed cocoons. Cost of seed to be recovered from farmers and the amount equal to cost of seed to be deposited back in the Bank to maintain corpus fund.

3.3.2.4 Vanya private graineurs (muga and eri)

(Amount in Rupees)

#	Particulars	Unit	Unit Cost	Quantity	Total
A	**Construction activities**				
1	Construction of grainage building (35'x12' with 5' verandah) with water				
	storage and drainage facility	sft	580	480	278400
	Sub-total (A)				**278400**
B	**Grainage equipment**				
1	Grainage stand	No.	2500	5	12500
2	Microscope with light arrangement	No.	7500	2	15000

					(Amount in Rupees)
#	**Particulars**	**Unit**	**Unit Cost**	**Quantity**	**Total**
3	Egg laying boxes/nylon net bags/kharikas	No.	5	3500	17500
4	Bamboo cages (Coupling)	No.	700	12	8400
	Wooden moth testing table (5ft x 1.5ft)	No.			
6	Wooden stools	No.	750	2	1500
7	Plastic drum (60 ltr)	No.	1000	1	1000
8	Plastic bucket (20 ltr.)	No.	300	2	600
9	Plastic tub (small - 10 ltr)	No.	200	3	600
10	Plastic tub (big - 20 ltr)	No.	300	2	600
11	Plastic mug	No.	50	3	150
12	Mortar & pestle	No.	80	40	3200
13	Measuring cylinder (Plastic)	No.	500	1	500
14	Weighing balance - Physical	No.	3000	1	3000
15	Disinfection mask	No.	600	2	1200
16	GI Wire (2.5 mm)	kg	250	3	750
17	Wet & Dry thermometer	No.	500	1	500
18	Max.-Min. thermometer	No.	500	1	500
19	Gattar sprayer/knapsack sprayer	No.	5000	1	5000
20	Misc	LS			2500
	Sub-total (B)				**80000**
C.	**Consumables**				
1	Formalin/KOH/soap/bleaching powder	LS			800
2	Blotting paper, muslin cloth, scissors	LS			1000
3	Slides and cover slips	LS			800
4	Lime	LS			450
5	Soap & detergent powder	LS			450
	Sub-total (C)				**3500**
D.	**Moth Testers@ 10 mandays per operation**	Man days	300	10	3000
E.	**Non-eroding Corpus fund for purchase of seed cocoons**	No.	3	30000	90000
F	**Solar lantern**	LS			4000
G	**Incentive @ Rs.6/- dfls for 6000 basic dfls**		**6**	6000	36000
H	**Misc. - Insurance of building/equipment /seed cocoons**				5100
	Sub-total (D+E+F+G+H)				**138100**
	Total				**500000**

3.4 Post-cocoon Sector

3.4.1 Support for small and medium size reeling units

In order to encourage production of gradable raw silk and to give more thrust for Bivoltine cocoon production in the country, it is proposed to support setting up of improved Small & Medium Mulberry Silk Reeling units. The units can be established by individual entrepreneurs or by a group in SPV/FPO mode.

The details of package proposed with unit cost as detailed below:

#	Particulars of Component/Package	Unit Cost (Rs.)	Proposed outlay (Rs. in lakh)
1.	Motorized charka to dissuade child labour	30,000	18.00
2.	Up-gradation of existing cottage basin/domestic basin units	2,40,000	720.00
3.	Establishment of Multi-end Reeling Units – 10 Basins	20,76,000	1557.00

Break-up of the above unit costs are detailed below:

#	Components	Unit cost of Component (in Rs.)	Machinery/Equipment		
			Name of the Machineries/Equipment's covered under the component	No. of Unit	Unit Price (Rs.)
1	Motorized charka to dissuade child labour	**30,000**	Twin charka with common shaft run by ½ HP electric motor (Single phase).	1 Unit	30,000
2	Up-gradation of existing cottage basin/domestic basin units	**2,40,000**	Two Pan Table for brushing	1 Unit	22860
			6 basin cottage basin Reeling machine (6 ends per basin)	1 Unit	240000
			6 basin Domestic basin Reeling machine (5 ends per basin)	1 Unit	240000
			Open type Re-reeling Machine 3 window (6 ends/window)	1 Unit	36000
			Small Reel Permeation Chamber	1 Unit	118600
			Generator (Capacity 5 KVA)	1 Unit	102000
			Boiler of 50 kg steam output per hour capacity with water softener (2 shell) and other accessories.	1 Unit	158000
			Solar operated UPS ½ Hp capacity	1 Unit	108000
			Epprouvette and Electronic balance of 600g capacity with 0.01 g sensitivity	1 set	15600

#	Components	Unit cost of Component (in Rs.)	Machinery/Equipment		
			Name of the Machineries/Equipment's covered under the component	No. of Unit	Unit Price (Rs.)
3	Establishment of Multi-end Reeling Units – 10 Basins	**20,76,000**	Hot air drier 50 kg capacity	1	180000
			Two Pan Table for brushing	4	91400
			Vacuum permeation pre treatment equipment or circular pressurised cocoon cooking machine	1	208000
			10 basin Multiend Reeling machine (10 ends per basin)	1	676200
			10 window closed type Re-reeling Machine (5 ends/window)	1	304000
			Small Reel Permeation Chamber	1	118600
			Epprouvette and Electronic balance of 600g capacity with 0.01g sensitivity	1 set	15600
			Generator (Capacity – 7.5 KVA)	1	118200
			Boiler of 100 kg steam output per hour capacity (IBR quality) and other accessories	1	324000
			Water softener with 8000 litres/8 hr capacity with regeneration at 25000 litres	1	40000

3.4.2. Support for Automatic Silk Reeling Machinery Package for individual/enterprise

To give more thrust for Bivoltine cocoon production and to create demand for gradable raw silk yarn in the country, it is proposed to support establishment of Automatic Reeling Units & Twisting units. The units can be established by individual entrepreneurs or by a group in SPV mode. The package includes support to ARMs of 120, 200 and 400 ends, establishment of ARM Unit – 5 line (2000 ends), twisting units and establishment of water re-cycling plant for reeling units.

The details of package proposed with unit cost as detailed below:

#	Particulars of Component/Package	Unit Cost (Rs.)	Proposed outlay (Rs. in lakh)
1.	**Support for Automatic Silk Reeling Machinery Package for individual**		
	a. Establishment of ARM Unit – 120 ends	39,15,000	2153.25
	b. Establishment of ARM Unit -200 ends	85,90,000	944.50
	c. Establishment of ARM Unit – 400 ends	1,49,66,500	6996.84

#	Particulars of Component/Package	Unit Cost (Rs.)	Proposed outlay (Rs. in lakh)
2.	**Assistance for twisting units (480 spindle capacity)**	11,00,000	605.00
3.	**Establishment of water re-cycling plant for reeling units (1 Lakh litres per day capacity)**	18,00,000	188.10
4.	**Support for Automatic Silk Reeling Machinery Package for enterprise Establishment of ARM Unit 5 line (2000 ends)**	5,98,00,000	897.00

Break-up of the above unit costs are detailed below:

#	Components	Unit cost of Component (Rs.)	Details of Machineries/Equipments		
			Name of the Machineries/Equipment's covered under the component	No. of Unit	Unit Price (Rs.)
1a	**Support for Automatic Silk Reeling Machinery Package for individual: Establishment of ARM Unit - 120 ends**	**39,15,000**	Batch type hot air drier of 100 kg capacity	1	225000
			Cocoon Deflossing machine	1	65000
			Vacuum permeation pre-treatment equipment	1	350000
			Automatic silk reeling machine 120 ends capacity with brushing unit	1	2000000
			Small reel permeation chamber	1	119000
			Closed type re-reeling machine 12 window capacity	1	328000
			Accessories and tools & spare parts for 120 ends ARM	1 set each	100000
			Motorized long skein book making machine	1	88000
			Generator (20 KVA capacity)	1	225000
			Water softener with 8000 litres/8 hours capacity with regeneration at 25000 litres.	1	40000
			IBR Boiler 200 kg steam output capacity and other accessories.	1	375000
1b	**Support for Automatic Silk Reeling Machinery Package for individual: Establishment of ARM Unit - 200 ends**	**85,90,000**	Conveyor hot air drier with hot air generator 1000 kg capacity	1	1677500
			Cocoon Deflossing machine	1	65000
			Vacuum permeation pre-treatment equipment	1	350000
			Conveyor cocoon cooking machine	1	671000

#	Components	Unit cost of Component (Rs.)	Details of Machineries/Equipments		
			Name of the Machineries/Equipment's covered under the component	No. of Unit	Unit Price (Rs.)
			Automatic silk reeling machine 200 ends capacity with a mechanical brushing unit	1	3025000
			Automatic reel permeation chamber	1	354000
			Closed type re-reeling machine 20 window capacity	1	606500
			Accessories and tools, special tools & spare parts suitable for 200 ends ARM	1 set each	277500
			Bale press	1	88000
			Skein winder	1	8000
			Reel carrier	2	27500
			Generator (30 KVA capacity)	1	290000
			Water softener with 12000 litres/8 hours capacity with regeneration at 50000 litres.	1	75000
			Pelade waste sheet making and pupae separation machine	1	200000
			Hydro extractor (10 kg capacity)	1	75000
			IBR Boiler 500 kg steam output capacity and other accessories	1	800000
1c	**Support for Automatic Silk Reeling Machinery Package for individual: Establishment of ARM Unit - 400 ends**	**1,49,66,500**	Conveyor hot air drier with hot air generator 2000 kg capacity	1	2427000
			Cocoon Deflossing machine	1	67000
			Vacuum permeation pre-treatment equipment for 400 ends ARM	1	529000
			Conveyor cocoon cooking machine (80 Cages capacity)	1	1080000
			Automatic silk reeling machine 400 ends capacity with two mechanical brushing units.	1	5955000
			Automatic reel permeation chamber for 120 reels	1	354000
			Closed type re-reeling machine 40 window capacity for 400 ends ARM	1	999600

#	Components	Unit cost of Component (Rs.)	Details of Machineries/Equipments		
			Name of the Machineries/Equipment's covered under the component	No. of Unit	Unit Price (Rs.)
			Accessories for 400 ends ARM	1 set	68400
			Tools for 400 ends ARM	1 set	85000
			Special tools for 400 ends ARM	1 set	42600
			Spare parts for 2 years for 400 ends ARM including 400 nos spare denier indicators	1 set	425800
			Bale press	1	88000
			Skein winder	1	6400
			Generator (50 KVA capacity)	1	624000
			Water softener with 20000 litres/8 hours capacity with regeneration at 80000 litres	1	250000
			Pelade waste sheet making and pupae separation machine	1	200000
			Hydro extractor (45 kg capacity)	1	200000
			IBR Boiler 1000 kg steam output capacity and other accessories	1	1500000
			Reel carrier	4	64700
2	Assistance for twisting units (480 spindle capacity)	**11,00,000**	Winding machine (50 spindles capacity)	2	187000
			Doubling machine (50 spindles)	1	101000
			Twisting machine 480 spindle (240 spindle each)	2	485000
			Twist setting chamber	1	23000
			120 yards warping machine	1	77000
			Re-reeling machine	1	52000
			Spares	1 set	175000
3	Establishment of water re-cycling plant for reeling units (1 Lakh litres per day capacity)	**18,00,000**	Water re- cycling plant	1	1800000

3.4.3 Support for Automatic Silk Reeling Machinery Package for enterprise

#	Components	Unit cost of Component (in Rs.)	Machineries/Equipments		
			Name of the Machineries/Equipment's covered under the component	No. of Unit	Price of the unit (in Rs.)
4	Establishment of ARM Unit-5 lines (2000 ends)	5,98,00,000	ARM Unit-5 lines (2000 ends)	1	59800000

Break-up of the above unit cost is detailed below:

No.	Particulars	Quantity	Cost in Rs.
1	Conveyor hot air drier with hot air generator 5000 Kg capacity	1	**4155000**
2	Cocoon Sorting Machine	2	**500000**
3	Cocoon Deflossing machine	3	**190000**
4	Vacuum permeation pre-treatment equipment for 2000 ends ARM	2	**1000000**
5	Conveyor cocoon cooking machine (80 Cages capacity)	2	**2500000**
6	Automatic silk reeling machine 400 ends capacity with two mechanical brushing units.	5	**31000000**
7	Automatic reel permeation chamber	2	**800000**
8	Closed type re-reeling machine 40 window capacity for 400 ends IARM	5	**5000000**
9	Accessories for 400 ends IARM	5 set	**350000**
10	Tools for 400 ends IARM	2 set	**180000**
11	Special tools for 400 ends IARM	2 set	**90000**
12	Spare parts for 2 years for IARM (One set for each line/ machine including 400 No's denier indicators per line/ machine)	5 set	**2000000**
13	Bale press	2	**200000**
14	Skein winder	5	**35000**
15	Generator (200 KVA capacity)	1	**1200000**
16	Water softener with 1.5 lakh litres / 8hr capacity with regeneration at 6.0 lakh liters	1	**1000000**
17	Pelade waste sheet making and pupae separation machine	3	**600000**
18	Hydro extractor (45 Kg capacity)	2	**400000**
19	IBR Boiler 5000 Kg steam output capacity and other accessories	1	**4900000**
20	Reel carrier	20	**350000**
21	Conditioning cabinet with Auto sorter with computer for denier test.	2	**400000**
22	Pupae processing conveyor hot air drier with hot air generator-1000 Kg capacity	1	**1950000**
23	Effluent treatment plant COD-7500-5000 litres/day (Ground discharge) as per PCB norms.	1	**1000000**
	TOTAL for ARM Unit-5 lines (2000 ends)		**59800000**

3.4.4 Support for establishment of pupae processing units

Silkworm pupae is the by-product of silk reeling. To enhance income of reelers & utilize by-products, developed a pelade extraction and pupa separation machine to remove pelade layer from spent silkworm pupae to utilize the pupae as feed for fish and poultry. A unit cost of Rs. 22.857 lakh is proposed with an outlay of Rs. 502.85 Lakhs for 5 years period from 2021-22 to 2025-26. This component can be used for pupa processing and canning unit for Eri sector too, with appropriate modifications suiting to the local requirement.

Unit cost details are given below:

#	Components	Unit cost of Component (Rs.)	Machineries/Equipments		
			Name of the Machineries/Equipment's covered under the component	No. of Unit	Price of the unit (Rs.)
1	**Support for establishment of Pupae processing unit**	**22,85,700**	Two No. of Pupae separation tub (20 kg capacity each) with 8 No. of Pupae separation SS crates (10 kg capacity each) OR Pelade waste sheet making & pupae separation machine	1 set	210000
			Hydro extractor (10 kg capacity)	1	75000
			Conveyor pupae hot air drier 500 kg capacity with hot air generator	1	840000
			IBR Boiler 200 kg steam output capacity and other accessories	1	375000
			Generator – 7.5 KVA	1	118200
			Effluent treatment plant (ground discharge) – 5000 litres capacity	1	660000

3.4.5 Support for Vanya Silk Reeling and Spinning units

Improved Vanya reeling machines are proposed to promote in the field for higher productivity, reduced labour, removal of drudgery and generating better quality twisted yarn in Vanya reeling sector. The package includes support for Buniyaad Reeling Machine with re-reeling attachment, Sonalika Muga weft reeling machine, Unnathi Reeling machine, Motorized Reeling cum Twisting machine, Motorized /Pedal operated spinning machines, Tasar reeling machinery package and Miniature Eri spinning plant.

The details of package proposed with unit cost as detailed below:

#	Particulars of Component/Package	Unit Cost (Rs.)	Proposed outlay (Rs. in lakh)
1.	Buniyaad Reeling Machine	9,750	438.75
2.	Sonalika Muga weft reeling machine	16,330	88.16
3.	Unnathi Reeling machine	27,300	51.19
4.	Motorized Reeling cum Twisting machine	25,350	63.88
5.	Motorized cum Pedal operated spinning machine	8,050	14.09
6.	Single window Re-reeling machine motor operated	16,000	11.20
7.	Tasar reeling machineries package	13,87,000	58.25
8.	Miniature Eri spinning plant	80,00,000	280.00

Of the above machineries, the unit cost details of devices at Sl. No. 1 to 6 are as indicated in the above Table. Details of Tasar Reeling Machinery package and Miniature Eri spinning plant, are given in the Tables below:

#	Components	Unit cost of Component (in Rs.)	Machineries/Equipments		
			Name of the Machineries/ Equipment's covered under the component	No. of Unit	Price of the units (Rs.)
7.	**Tasar Reeling machineries package**	**13,87,000**	Wet Reeling Machine (1 unit price is Rs.34500)	13	4,48,500
			Buniyaad Reeling Machine (1 unit price is Rs.9,750)	13	1,26,750
			Mot. Reeling cum Twisting M/c. (1 unit price is Rs.25,350)	12	3,04,200
			Boiler Non IBR - 50 kg	1	1,50,000
			Re-reeling Machine – Mortised Single window(1 unit price is Rs. 16,000)	2	32,000
			Permeation chamber (small)	1	50,000
			MPSM spinning machines (1 unit price is Rs. 8,050)	10	80,500
			Two pan cooking device	1	30,000
			5 KVA Generator	1	1,30,000
			Accessories [Set]	1	35,000
8	**Miniature Eri spinning plant**	**80,00,000**	Opening cum lap forming machine (1 unit price is Rs. 320000)	2	640000
			Staple length cutting machine	1	400000
			Roller and Clearer card	1	1750000

#	Components	Unit cost of Component (in Rs.)	Machineries/Equipments		
			Name of the Machineries/ Equipment's covered under the component	No. of Unit	Price of the units (Rs.)
			Draw frame (Single delivery)	1	800000
			12-spindle Flyer Frame	1	790000
			Ring Frame (64-spindle) (1 unit price is Rs. 795000)	2	1590000
			Cone winder (6 drums)	1	60000
			Doubling machine (40 Spindles)	1	90000
			Twisting machine (60 Spindles)	1	200000
			Reeling machine (40 ends)	1	170000
			Steaming chamber (Twist setting chamber)	1	19000
			Eri cocoon degumming plant	1	400000
			Carding sliver can (1 unit price is Rs. 45000)	20	900000
			Drawing sliver can (1 unit price is Rs. 3000)	30	90000
			Simplex Bobbins (1 unit price is Rs. 50)	1000	50000
			Ring frame tubes (1 unit price is Rs. 20)	2000	40000
			Twisting machine tubes (1 unit price is Rs. 20)	300	6000
			Doubling machine cone (1 unit price is Rs.20)	250	5000

3.4.6 Support for providing services of Master Reelers/Technicians as Twister/Weaver/ Dyer/ Mechanics for silk industry

One of the major constraints for sustaining silk reeling industry in non-traditional states and non-traditional areas of traditional States is the absence of skilled reelers/weaver. To overcome this problem, it is proposed to continue the component and also to have services of Master Technicians to attend the repair and other maintenance work of reeling units. A unit cost of Rs.2.52 lakh per year is proposed with an outlay of Rs.945.00 lakh for 5 years period from 2021-22 to 2025-26.

Break-up of the unit cost is given below:

#	Wages/allowances	Per Year (Rs.)
1.	Wages @ Rs.18,000/- per month	2,16,000
2.	Lump sum after completion of the tenure	36,000
	Total	**2,52,000**

The lumpsum amount to be paid at the end of the tenure of 12 months can also be paid on pro rata basis, depending on the number of months the service was provided.

3.4.7 Support for cocoon drying facility in designated cocoon market

The component is proposed to support silk reeling industry with Hot air driers of 1000 kg & 2000 kg capacity to dry the cocoons effectively, as green cocoon is perishable & having short shelf life.

The details of package proposed with unit cost as detailed below:

#	Particulars of Component/Package	Unit Cost (Rs.)	Proposed outlay from 2021-22 to 2025-26 (Rs. in lakh)
1.	Conveyor hot air drier (1000 kg capacity)	16,77,500	92.26
2.	Conveyor hot air drier (2000 kg capacity)	24,27,000	66.74

3.5 Support for Silk Weaving Sector

A major portion of the raw silk (60-70%) is consumed by the Handlooms. Silk handloom sector is the mainstay of the Indian Sericulture. Most of the handlooms have outlived their utility and results in low productivity, poor quality and facing drudgery. To support silk weaving sector with advanced technology & gadgets viz. Modified Region specific silk hand looms (Pit loom), Loom up-gradation through Jacquards, Pirn winding and other equipments, Pneumatic lifting mechanism-2 looms, Electronic Jacquard (720 hooks) with Lifting mechanism, Computer Aided Textile Designing (CATD) units, Sectional warping machine/Ball warping machines and Asu Machine & Winding machine, a package is proposed to address the issues in silk weaving sector for better productivity, quality of fabrics and reduce the drudgery of the weavers.

The details of package proposed with unit cost as detailed below:

#	Particulars of Component/Package	Unit Cost (Rs.)	Proposed outlay (Rs. in lakh)
1.	Modified Region Specific Silk Handlooms (Pit loom)	41,000	393.60
2.	Computer Aided Textile Designing (CATD) Unit	5,85,000	456.30
3.	Electronic Jacquard (720 hooks) with Lifting mechanism	2,42,000	849.42
4.	Loom up-gradation through Jacquards, Pirn winding and other equipments.	17,500	89.25

The details of package proposed with unit cost as detailed below:

#	Particulars of Component/Package	Unit Cost (Rs.)	Proposed outlay
5.	Pneumatic Lifting mechanism (PLM) 2 loom unit	38,000	57.00
6.	Sectional warping machine/Ball warping machines	35,000	94.50
7.	Asu Machine & Winding machine package	45,000	121.50

The unit cost break of the above machineries are given below:

#	Components	Unit cost of Component (Rs.)	Machineries/Equipments		
			Name of the Machineries/ Equipment's covered under the component	No. of Unit	Units Price (Rs.)
1	Modified Region Specific Silk Handlooms (Pit loom)	**41,000**	This is an inclusive Silk Handloom with all accessories as part of the unit itself.		
2	Computer Aided Textile Designing (CATD) Unit	**5,85,000**	Desktop Computer (Optional)	1	49000
			Ink jet printer (Optional)	1	9450
			Scanner (Optional)	1	5460
			UPS with battery (Optional)	1	16400
			Computerized card punching machine (Compulsory)	1	264000
			Computerized Card lacing machine (Optional)	1	211000
			Textile Designing Software (Optional)	1	30000
3	Electronic Jacquard (720 hooks) with Lifting mechanism	**2,42,000**	Electronic Jacquard with 720 hooks	1	1,98,000
			Air Compressor, Pneumatic Cylinder with all accessories, Harness etc., (Optional)	1	44,000
			Driving shaft, Chain and Driving Motor with all accessories, Harness etc., (Optional)	1	--
4	Loom up-gradation through Jacquards, Pirn winding and other equipments.	**17,500**	240 Hooks Jacquard, Nylon heald wires with lingoes, Harness thread, Comber board, Safety pins etc,		
			120 Hooks Jacquard, Nylon heald wires with lingoes, Harness thread, Comber board, Safety pins etc,		

#	Components	Unit cost of Component (Rs.)	Machineries/Equipments		
			Name of the Machineries/ Equipment's covered under the component	No. of Unit	Units Price (Rs.)
			Friction less Jacquard		Maximum of Rs.17,500
			Motorized Jacquard Lifting mechanism		
			Manual jacquard card punching set. (for 120 120 hooks/240 hooks cards)		
			Friction less Jacquard		
			Motorized Jacquard Lifting mechanism		
			Manual jacquard card punchin g set. (for 120 hooks/240 hooks cards)		
			48 Lever Dobby Teak wood with frames, Lattice, Comber board, Nylon heald wires with lingoes, 2500 No pegs etc.		
			Motorized Pirn winding machine (1/2/6 spindles)		
			Hank to bobbin winding machine (6/8 ends single side)		
			2 in 1 winding machine (4 ends - single side)		
			Butta Mechanism kit (6-10 buttas)		
			Solid border mechanism (Korvai kit)-120 to 240 hooks capacity		
			Take up motion mechanism		
			Let off motion mechanism		
5	Pneumatic Lifting mechanism (PLM) 2 loom unit	**38,000**	This is the consolidated cost of the unit		
6	Sectional warping machine/Ball warping machines	**35,000**	Sectional warping machine with creel & Beaming unit (OR)		Rs.35,000/ - (Each component)
7	Asu Machine & Winding machine package	**45,000**	Asu Machine with motor driving arrangement		Rs.30,000/-
			Winding machine for Asu machine.		Rs.15,000/-

3.6 Support for silk dyeing and processing

The technologies proposed under this component reduce consumption of water & energy and manpower requirement in silk yarn dyeing & processing sector. Apart from improving the quality of dyeing, it also helps to provide conducive working environment to the workers. It is proposed to support the establishment of 2 kg -250 kg capacity units which are contributing major role in handloom clusters *viz.*, Kanchipuram, Arani, Dharmavaram, Varanasi, Y.N. Hosakote and Molakalmur etc. The package includes support for establishing tub dyeing 2 kg and 50 kg units, Arm dyeing unit – 50 kg capacity, Fabric Processing unit – 250 kg capacity, finishing units and Sericin Extraction Unit - 10 kg capacity.

The details of package proposed with unit cost as detailed below:

#	Particulars of Component/Package	Unit Cost (Rs.)	Proposed outlay from 2021-22 to 2025-26 (Rs. in lakh)
1.	Micro tub dyeing unit 2 kg unit	1,00,000	44.00
2.	Tub dyeing-50 kg unit	10,13,000	83.57
3.	Arm dyeing-50 kg unit	23,80,000	65.45
4.	Silk Digital Printing machine with required wet processing machinery package	1,65,00,000	247.50
5.	Fabric Processing Unit -250 kg	34,34,000	94.44
6.	Finishing Unit	11,42,000	50.25
7.	Sericin Extraction Unit – 10 kg capacity	15,24,000	67.06

The detailed cost break-up of the above units are given below in seriatim:

#	Components	Unit cost of Component (Rs.)	Machineries/Equipments		
			Name of the Machineries/Equipment's covered under the component	No. of Unit	Price of the units (Rs.)
1	Micro tub dyeing unit – 2 kg unit	**1,00,000**	Stainless Steel Tubs-1 kg . (1 No.), 2 kg (2 No.) or as per the requirement	1	25000
			Electronic Balance - 2 kg capacity	1	10000
			Boiler – 50 kg (Non-IBR)	1	65000
2	Tub dyeing -50 kg unit	**10,13,000**	Stain Steel Tubs-2 kg . (2 No.), 5 kg (2 No.), 10 kg. (1 No.) & 20 kg . (1 No.) or as per the requirement	1	273000
			Water Softening Plant-8000 litres/8 hours (Recharge after 25000 litres)	1	40000
			Water Tank-2500 ltrs. Capacity (2 No.)	1	48000

#	Components	Unit cost of Component (Rs.)	Machineries/Equipments		
			Name of the Machineries/Equipment's covered under the component	No. of Unit	Price of the units (Rs.)
			Hydro Extractor - 5 kg	1	59000
			Silk Hank Drying Machine-25 kg capacity	1	100000
			Electronic Balance-2kg. capacity	1	10000
			Generator 3 KVA	1	80000
			Boiler-200 kg. capacity (IBR)	1	375000
			Colour Matching Cabinet/ Washing cum Rinsing machine	1	28000
3	Arm dyeing -50 kg unit	**23,80,000**	Two Arm dyeing machine - 2 No or as per the requirement	1	1400000
			Water Softening Plant – 8000 litres/8 hours (Recharge after 25000 litres)	1	40000
			Water Tank - 2500 ltrs. Capacity (2 No.)	1	48000
			Hydro Extractor - 5 kg	1	59000
			Silk Hank Drying Machine – 25 kg capacity	1	100000
			Electronic Balance-2 kg. capacity	1	10000
			Silent Generator - 10 KVA	1	320000
			Boiler-200 kg.capacity (IBR)	1	375000
			Colour Matching Cabinet/Washing cum Rinsing	1	28000
4	Silk Digital Printing machine with required Wet processing machinery package	**1,65,00,000**			
5	Fabric Processing Unit-250 kg	**34,34,000**	Winch/Jigger Dyeing machine-25 kg	1	250000
			Winch/Jigger Dyeing Machine-50 kg	1	330000
			Calendaring Machine/Felt Calendaring Machine/Decatizing Machine	1	800000
			Water Softening Plant – 8000 litres/8 hours (Recharge after	1	40000

#	Components	Unit cost of Component (Rs.)	Machineries/Equipments		
			Name of the Machineries/Equipment's covered under the component	No. of Unit	Price of the units (Rs.)
			Water Tank - 2500 ltrs. Capacity (2 no.)	1	48000
			Hydro Extractor - 25 kg.	1	116000
			Computerized Colour Matching (CCM)	1	545000
			Electronic Balance-2 kg. capacity	1	10000
			Boiler-750 kg. capacity (IBR)	1	975000
			Silent Generator - 10 KVA	1	320000
6	Finishing Unit	**11,42,000**	Three Bowl Calendaring Machine or Five Bowl Calendaring Machine or Felt Calendaring Machine or Decatizing Machine	1	800000
			Platform Balance-25 kg capacity	1	18000
			Boiler - 100 kg. capacity (IBR)	1	324000
7	Sericin Extraction Unit -10 kg capacity	**15,24,000**	CSTRI Eco dyeing machine: 10 kg capacity	1	1000000
			Hot Air Drying Machine-25 kg capacity		59000
			Water Softening Plant-8000 litres/8 hours (Recharge after 25000 litres)		40000
			Water Tank - 2500 ltr. Capacity (1 No.)		24000
			Hydro Extractor - 5 kg		59000
			Platform Balance 25 kg capacity		18000

3.7 Support for establishment of Effluent Treatment Plant - Zero discharge and Ground discharge type

The silk yarn dyeing and silk fabric processing facilities created under earlier plans were not provided with ETP. In recent past the Pollution Control Board has issued guidelines for strict compliance and treatment of effluent before discharge from silk processing units. With a view to equip these processing units with ETP and encourage pollution free processing units, it is proposed to provide support to establish ETP plants in existing as well as new units.

The details of package proposed with unit cost as detailed below:

#	Particulars of Component/Package	Unit Cost (Rs.)	Proposed outlay (Rs. in lakh)
1.	ETP- Discharge to Ground	10,00,000	71.50
2.	ETP- Zero discharge	15,00,000	66.00

The break-up of unit cost is given in the Table below :

#	Components	Unit cost of Component (in Rs.)	Machineries/Equipments		
			Name of the Machineries/Equipment's covered under the component	No. of Unit	Price of the units (Rs.)
1	ETP- Discharge to Ground	**10,00,000**	Effluent Treatment plant - Primary, Secondary & Tertiary treatment for the silk dyeing raw effluent (COD-7500)- 5000 litres/day capacity without civil work or any other proven/field tested technology so that the treated water is discharged to grounds (as per PCB norms) efficiently.	**1**	1000000
2	ETP- Zero discharge	**15,00,000**	Effluent Treatment Plant (5000 litre capacity) Primary, Secondary and Tertiary treatment for the silk processing unit effluent (COD7500) with RO plant and without evaporation system and civil works or any other proven/field tested technology so that the treated water is reused efficiently.	**1**	1500000

3.8 Package of assistance to Seri Business Enterprises

To scale up the import substitute Bivoltine silk production, concept of Seri-Business Entrepreneurs/corporate sericulture (farm to fabric-large scale farming)/Industry participation through up-scaling the reeling activity, to compete globally have been included. It is proposed provide rationalised scale of subsidy support as indicated in guidelines to large scale Seri-Business Entrepreneurs to attract them to invest in ARM and corporate sericulture – farm to fabric. CSB units and States to encourage Start-ups and private entrepreneurs for taking up this

venture with support from Silk Samagra-2. Unit costs proposed for various components can be adopted on pro-rata basis, to arrive at the project cost of such start-ups and seri-business enterprises. While taking up large scale farming and post cocoon activities, individual beneficiary based infrastructure could be done away with by creating large infrastructure for productivity improvement and to attain economy of scale.

3.9 Flexi Fund

It is proposed to create a Flexi Fund to meet some of the need based requirement of the sector, which could not be met by the existing components suggested above. Some of the interventions which are proposed to be covered under the Flexi Fund are;

1. Viability Gap Funding while implementing advanced technologies to cover components like turnkey concept, AMC, initial hand holding and capacity building with a view to make the enterprise viable.
2. Innovative components [which are developed during the scheme implementation period] aimed at quality and productivity improvement, use of non-conventional energy.
3. Incentivizing quality production like production of quality bivoltine raw silk and incentivizing commendable performance in post cocoon sector.
4. Establishment of Quality Certification System across silk value chain
5. Formation of Farmer Producer Organisations (FPOs) from the newly proposed farmers' group and existing sustainable project models implemented in the past.
6. Escalation in cost of equipments /machineries especially in PCT sector (including GST, transportation cost etc.).

An amount of Rs.1726.73 lakh is proposed for 5 years period from 2021-22 to 2025-26 to meet the above interventions under flexi fund. Implementing Agencies, while formulating the project, may include upto10% of the total project cost towards Flexi Fund by defining the interventions proposed to be taken up under Flexi Fund. GoI share will be in proportion to the total share of CSB for the project.

4. Information, Education & Communication (IEC)

Maximum of 5% of the project cost may be proposed towards Information, Education & Communication, Administration & Monitoring. GoI share will be in proportion to the total share of CSB for the project.

*****